रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94 REGISTERED NO. DL-33001/94

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण में प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 1995/माघ 1, 1916
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 1995/MAGHA 1, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक खंड)

सूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1994

का. आ. 106 :—नोटरीज नियम 1956 के नियम 6क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सेवा राम शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर व किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (194)/94-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

NOTICE

New Delhi, the 21st December, 1994

S.O. 106.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Sewa Ram Sharma, Advocate for appointment as a Notary to practise in Ghaziabad (U.P.).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(194)/94-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1994

का. आ. 107—नोटरी नियम 1956 के नियम 6क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री कान्ति भूषण राय, एडवोकेट के उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कलकत्ता और 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर वे किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए ।

[सं. 5 (195)/94 न्यायिक]
पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 21st December, 1994

S.O. 107.—Notice is hereby given by the Competent Authoriy in pursuance of Rule 6a of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Kanti Bhushan, Roy, Adv. for appointment as a Notary to practise in Calcutta & 24 Pargana (West Bengal).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(195)/94-Judl.]
P. C. KANNAN, Competent Authority.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसंबर, 1994

का.आ. 108.—केन्द्रीय सरकार, आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा 13 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जी विट्टल, उप विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, हैदराबाद को, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा अन्वेषण किए गए या संस्थित, मामला सं. आर. सी. 1/एस//93/सीबीआई/वीएसपी (एम.वी.ए.एच.ए.टी. मामला) और उक्त अपराध के अधीन उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक किसी अन्य मामले के अभियोजन का, आंध्र प्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित अभिहित न्यायालय-जिला और सेशन न्यायालय, विशाखापत्तनम में और उक्त अधिनियम के अधीन गठित किसी अन्य अभिहित न्यायालय के समक्ष भी, जहां उपरोक्त मामले से संबंधित विधि संबंधी विषय सुनवाई के लिए आते हैं, संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[सं. 225/38/94-एवीडी-II]
आर. एस. बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 26th December, 1994

S.O. 108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (i) of Section 13 of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 (28 of 1987), the Central Government hereby appoints Shri G. Vittal, Deputy Legal Advisor, CBI. Hyderabad, as Special Public Prosecutor, for conducting prosecution of the case RC. 1/S/93/CBI/VSP(MVAHAT case) and any other matter connected therewith or incidental thereto under the said offence, investigated or instituted by the Delhi Special Police Establishment, in the Designated Court-District and Session Court at Visakhapatnam constituted under Section 9 of the said Act in the State of Andhra Pradesh and also before any other Designated Court constituted under the said Act, where legal matters relating to the above said case comes up for hearing.

[No. 225/38/94-AVD-II]
R. S. BISHT, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1995

का.आ 109—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की अपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से आदेश सं. 220 टी/611-94-921 एम/89 दिनांक जून, 1994 के तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों तथा अधिकारिता का स्वरूप नगर, कानपुर दिनांक 23-9-89, 7/109 की एक घटना में लूटपाट, सीमा उल्लंघन अपराधों सहित दूसरे अपराध तथा दंडनीय अपराधों और उक्त कथित पंजीकृत सं. आर.सी. 6(एस)94-एस.आई.यू./II/एस. आई.सी. I के.अ. ब्यूरो के तथा संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों आदि अपराध के संबंध में, श्रीमती पुष्पा देवी सर्राफ द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश दिनांक 9-12-1993 का अपराध मि. याचिका प्रार्थना सं. 23804, 1989 का सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर विस्तार करती है।

[संख्या 228/20/94-ए.वी.डी. (II)]
आर.एस. बिष्ट, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th January, 1995

S.O. 109.—In exercise of the powers conferred by Subsection (i) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh vide order No. 220T/611-94-921M/89 dated June 1994, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Uttar Pradesh for the investigation of the offences including looting, criminal trespass & other offences in an incident dated 23rd September, 1989 at 7/169, Swarup Nagar, Kanpur and relating attempts abetments and conspiracy in relation to the aforesaid incident FIR registered with CBI at RC 6(s)/94-SIU-II/SIC-I New Delhi in view of Allahabad High Court order dated 9th December, 1993 passed in Criminal Misc. Writ Petition No. 23804 of 1989, filed by Smt. Puspa Devi Saraf.

[No. 228/20/94-AVD-II]
R. S. BISHT, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 24 नवंबर, 1994

(आयकर)

का.आ. 110.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री काशी मठ संस्थान, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखा जाता हो।

[अधिसूचना सं. 9652/फा.सं. 197/111/94-आयकर नि-1]

साधना शंकर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th November, 1994

(INCOME-TAX)

S.O. 110.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shree Kashi Math Samsthan, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely:—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9652/F. No. 197/111/94-ITA-I]

SADHNA SHANKER, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद समाहर्तालय

अधिसूचना संख्या-सीइआर/आर-5/1/94/तकनीकी

नागपुर, 25 अक्तूबर, 1994

का.आ. 111.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-बी के अंतर्गत शक्तियों को सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को प्रत्यायोजित करता हूं।

तदनुसार दिनांक 7-1-1984 की अधिसूचना संख्या सीइआर/आर-5/1/84 में अनुबद्ध सारणी के क्रम संख्या 26 की प्रविष्ट को पुन: प्रतिष्ठित करते हुए एतद्द्वारा दिनांक 17-3-1988 की अधिसूचना संख्या सीइआर/आर-5/1/88 को निरस्त किया जाता है।

[फाईल संख्या IV (16) 8-22/80/भाग-II]

जैड. बी. नगरकर, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE : NAGPUR

NOTIFICATION No. CER/R-5/1/94/TECHNICAL

Nagpur, the 25th October, 1994

S.O. 111.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 I hereby delegate the powers under Rule 56B of Central Excise Rules, 1944 to the Assistant Collector Central Excise.

Accordingly Notification No. CER/R-5/1/88 dated 17th March, 1988 is hereby rescinded restoring the entry at Sl. No. 26 of the table annexed to Notification No. CER/R-5/1/84 dated 7-1-1984.

[C. No. IV(16)8-22/80/PT-II]

Z. B. NAGARKAR, Collector

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय

कोयम्बतूर, 24 नवंबर, 1994

अधिसूचना 2/94

सीमा शुल्क

का.आ. 112.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 152 खंड (ए) के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 1 जुलाई, 1994 के अधिसूचना सं. 33/94-सीमा शुल्क (एन. टी.) के अधीन अधोहस्ताक्षरी को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. जी. के. पिल्ले, समाहर्ता, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयम्बतूर एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य, कोयम्बतूर जिला, पल्लडम तालुक के सूलूर डाक में स्थित "कन्नमपालयम" ग्राम को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 9 के अंतर्गत 100% निर्यातोन्मुख एकक (ई.ओ.यू.) के घटन के उद्देश्य से भांडागारण स्टेशन के रूप में घोषित करता हूं। जैसा कि उद्योग मंत्रालय औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित है।

[पत्र सं. VIII/40/11/94-सी.शु.]

डॉ. जी. के. पिल्ले, समाहर्ता

OFFICE OF THE COLLECTOR OR CETRAL EXCISE

NOTIFICATION NO. 2/94

Coimbatore, the 24th November, 1994

CUSTOMS

S.O. 112.—In exercise of the powers delegated to the undersigned vide Notification No. 33/94-CUS(NT) dated the 1st July, 1994 by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962, I, Dr. G. K. Pillai, Collector of Customs & Central Excise, Coimbatore hereby declare the village 'Kannampalayam' in Palladam Taluk, Sulur P.O. in the District of Coimbatore, State of Tamilnadu, to be a Warehousing Station under section 9 of the Customs Act, 1962 for the purpose of setting up of 100% E.O.U. As approved by Ministry of Industry, Secretariat of Industrial approval, New Delhi.

[C. No. VIII/40/11/94-CUS.]

DR. G. K. PILLAI, Collector

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1994

आयकर

का.आ 113.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "गोविन्द भवन कार्यालय, कलकत्ता", को कर-निर्धारण वर्ष 1995 96 से 1997-98 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के रूप में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9658/फा.सं. 197/141/94-आयकर-1]

साधना शंकर, अवर/सचिव

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st December, 1994

(INCOME-TAX)

S.O. 113.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Govind Bhawan Karyalaya, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1995-96 to 1997-98 subject to the following conditions, namely:—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9658/F. No. 197/141/94-ITA-I]

SADHNA SHANKER, Under Secy.

मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय

कलकत्ता, 5 दिसम्बर, 1994

स्पष्टीकरण

संख्या-7/94-95 :

का.आ. 114.—इस कार्यालय के एफ. संख्या स.आ./मुख्या./योजना/345/94-95 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 5/94-95 दिनांक 21-09-1994 जिसकेद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 और 221 के अधीन दिनांक 1-10-94 से स्त्रोत पर काटा गया कर से संबंधित सभी मामलों का क्षेत्राधिकार को विकेन्द्रीकरण करते हुए स.आ.आ. कम्पनी सर्कल 2(2), कलकत्ता के प्रभार से मु.आ.आ., कलकता, मु.आ.आ. II कलकत्ता और मु.आ.अ.I-III, कलकत्ता के क्षेत्राधीन संबंधित निर्धारण अधिकारियों को दिये जाने के सिलसिले में, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी मामलों जो, दिनांक 1-10-94 की ओर से, आयकर अधिनियम की धारा 195 के अधीन केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा कोई सांविधिक स्थानीय प्राधिकारियों (ऐसे जो कि आयकर अधिनियम के अधीन निर्धारणीय नहीं है) के अधीन किसी कार्यालय अथवा संस्था द्वारा स्रोत पर कर काटा गया है, में आ. अधिनियम, 1961 की धारा 195 और 221 के प्रयोजन में इसके विपरीत पूर्वोत्तर आदेश के होते हुए भी निम्नलिखित आयकर प्राधिकारी क्षेत्राधिकारी प्रयोग करेंगे।

आ.आ. का प्रभार	रेंज आ. उपा.	स.आ.आ./प्रा.अ.	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
आ. आ. प. ब.-VII कल.	आ. उपा. रें.-21 कल.	स. आ. आ. (टीडी एस) सर्कल 2 (1) कल.	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स.अ. है, कलकत्ता उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और हावड़ा के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
आ. आ. ब.-I कल.	आ. उपा., जल रेंज	अप. आ. वार्ड-1 जलपाईगुड़ी	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स.आ. है, आयकर कार्यालय जलपाईगुड़ी के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
आ. आ. प. ब.-I कल.	आ. उपा. रेंज जलपाईगुड़ी	स. आ. आ. (टीडी एस) सिलिगुड़ी	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स.आ.है, आयकर कार्यालय सिलिगुड़ी के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
आ. आ. प. ब.-I कल.	आ. उपा. रेंज जलपाईगुड़ी	स. आ. आ. (टीडी एस) सिलीगुड़ी	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स. आ. है, आकर कार्यालय सिक्किम राज्य के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
आ. आ. प. ब.-I कल.	आ. उपा. रेंज जलपाईगुड़ी	आ. अ. वार्ड-1 मालदा	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स.आ. है, आयकर कार्यालय मालदा के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
आ. अ. प. ब.-I कलकत्ता	आ. उपा. रेंज-जलपाईगुड़ी	आ. अ. वार्ड-1 कूच बिहार	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स.आ.है, आयकर कार्यालय कूच बिहार के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
आ. आ. प. ब.-I कलकत्ता	—वही—	आ. अ.वार्ड-1 दार्जीलिंग	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स.आ. है आयकर कार्यालय दार्जिलिंग के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।

1	2	3	4
आ. आ. प. ब.-Iकल.	—वही—	आ. अ. वार्ड-1 कालिपोंग	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स. आ. है आयकर कार्यालय कालिपोंग के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं ।
आ. आ. प.ब-VIIकल	आ उपा. रेंज-10 कल.	आ. आ. सर्कल-10(2) अंडमान एवं निकोबार द्वीपपुंज	उपरिनिर्दिष्ट सभी का मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स.आ. है आयकर कार्यालय अंडमान एवं निकोबार द्वीपपुंज क क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
आ. आ. प-ब-Xकल.	आ. उपा. रेंज-17 कल.	आ. अ. वार्ड-1 मुर्शिदाबाद	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामलें जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स. आ. है आयकर कार्यालय मुर्शिदाबाद के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
आ. आ. प.ब-Xकल.	आ. उपा. रेंज-17 कल.	आ. अ. वार्ड-1 नदिया	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स. आ. है, आयकर कार्यालय नदिया के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
आ. आ. प. ब.-XIकल.	आ. उपा. रेंज-19 कल.	आ. अ. वार्ड-1 हुगली	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स. आ. है, आयकर कार्यालय हुगली के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
आ. आ. प. ब-XIकल	—वही—	आ. अ. वार्ड-1 मिदनापुर	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स.आ. है, आयकर कार्यालय मिदनापुर के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
—वही—	—वही—	आ. का. हल्दिया	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहा पर धारा 195 के अधीन संदेय आ.व स आ. है, आयकर कार्यालय हल्दिया के क्षेत्राधिकार में पड़ते है।
—वही—	आ. उपा.रेंज-आसनसोल	आ. का. वार्ड-1 आसनसोल	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ. व स.आ. है, आयकर कार्यालय आसनसोल के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।

1	2	3	4
आ. आ. प. ब.—× 1कल.	आ.उपा. रेंज-आसनसोल	आ. का. वार्ड-1 दुर्गापुर	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 क अधीन संदेय आ.व स.आ.है, आयकर कार्यालय दुर्गापुर के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
—वही—	—वही—	आ. का. वार्ड-1 बर्द्धमान।	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां परधारा 195 के अधीनसंदेय आ.व स.आ.है, आयकर कार्यालय बर्द्धमान के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
—वही—	—वही—	आ. कार्यालय सिउड़ी	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां परधारा 195 के अधीनसंदेय आ.व स. है, आयकर कार्यालय सिउड़ी के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
आ. आ. प. ब.—X 1कल.	आ. उपा. रेंज-आसनसोल	आ. का. बांकुड़ा	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ.व स.आ.है, आयकर कार्यालय बांकुड़ा के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।
आ. आ. प. ब — × 1कल.	आ. उपा. रेंज आसनसोल	आ. का. पुरूलिया	उपरिनिर्दिष्ट सभी मामले जहां पर धारा 195 के अधीन संदेय आ.व स.आ.है, आयकर कार्यालय पुरूलिया के क्षेत्राधिकार में पड़ते हैं।

[सं. ग. आ./मुख्या/योजना (345)]

(के. पी. सिंह)
मु. आ. आ. III
कलकत्ता

(ए. के.बटब्याल)
मु. आ.आ.—II
कलकत्ता

(के. पी. सिंह)
मु.आ.आ.
कलकत्ता

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Calcutta, the 5th December, 1994.

CLARIFICATION

No. 7/94-95

S.O. 114—In continuation of this office Notification No. s5/94-95 dated 21-09-1994 under F.No. AC/Hqr/Planning/345/94-95 decentralising the jurisdiction over all matters relating to Tax Deduction at Source under sections 195 & 221 of the Income Tax Act, 1961 from the charge of the ACIT. Co. Cir. 2(2), Cal. to the concerned assessing officers under the regions of the CCIT, Cal., CCIT-II, Cal. & CCIT-III, Cal., with affect from 1-10-94, it is clarified that in all cases where any tax deduction at source is made under section 195 of the I.T. Act on and from 1-10-94 by any Office or concern under the Central Government or under the State Governments or under any statutory local Authorities (who are not assessable under the I.T. Act as such), the jurisdiction over such cases for the purposes of sections 195 & 221 of the I.T. Act, 1961 should be exercised by the following Income tax Authorities, notwithstanding any earlier to the contrary:

Charge of the CIT	Range D.C.	ACIT/ITO	Jurisdiction
1	2	3	4
CIT, WV-VII, Cal.	D.C. Range-21, Cal.	ACIT (TDS) Cir.21(1), Cal.	All such cases referred to above where the offices of the DDOs making the TDS u/s. 195 lie within the territorial jurisdiction of Calcutta, North 24 Parganas South, 24 Parganas & Howrah district.
CIT WB-I, Cal.	D.C. Jalpaiguri range	ITO, Ward-I, Jalpaiguri	All such cases referred to above where the offices of the DDOs making the TDS u/s. 195 lie within the jurisdiction of the Income-Tax Office at Jalpaiguri.
CIT, WB-I, Cal.	D.C. Range Jalpaiguri	ACIT (TDS) Siliguri	All such cases referred to above where the office of the DDOs making the TDS u/s. 195 lie within the jurisdiction of the Income-Tax Office at Siliguri.
CIT, WB-I, Cal.	D.C. range Jalpaiguri	ACIT (TDS) Siliguri	All such cases referred to above where the offices of the DDOs making the TDS u/s. 195 lie., within the territorial jurisdiction of the State of Sikkim.
CIT, WB-I, Calcutta.	D.C. Range Jalpaiguri.	ITO, Ward-I, Malda	All such cases referred to above where the offices of the DDOs. making the TDS u/s. 195 lie within the jurisdiction of the Income-tax office at Malda.
CIT, WB-I, Calcutta.	D.C. Range Jalpaiguri	ITO, Ward-I Cooch Behar	All such cases referred to above where the offices of the DDOs' making the TDS u/s. 195 lie within the jurisdiction of the income-tax office at Cooch Behar.
CIT, WB-I Calcutta.	-do-	ITO. Ward-I Darjeeling.	All such cases referred to above where the offices of the DDOs' making the TDS u/s. 195 lie within the jurisdiction of the Income-tax office at CoochBehar.
CIT, WB-I, Calcutta.	-do-	ITO, Ward-I Kalimpong	All such cases referred to above where the offices of the DDOs. making the TDS u/s. 195 lie within the jurisdiction of the Income-tax office at Kalimpong.,
CIT, WB-VIII, Calcutta	D.C.R. 10 Calcutta.	A.C. Circle-10(2) Andaman & Nicobar Islands	All such cases referred to above where the offices of the DDOs. making the TDS u/s. 195 lie within the jurisdiction of the. the Income tax Office at Andaman & Nicobar Islands.
CIT,WB-X, Cal.	D.C. Range-17 Cal.	ITO, Ward 1 Murshidabad	All such cases referred to above where the offices of the DDOs making the TDS u/s. 195 lie Within the jurisdiction of the ncome-tax office at Murshidabad.

1	2	3	4
CIT, WB-X, Calcutta	D.C. Range-17 Calcutta	ITO, Ward-1 Nadia	All such cases referred to above where the offices of the DDOs making the TDS u/s. 195 lie. within the jurisdiction of the Income-tax office at Nadia.
CIT, WB-XI Calcutta.	D.C. Range-19 Calcutta.	ITO, Ward-1, Hooghly.	All such cases referred to above where the offices of the DDOs making the TDS u/s. 195 lie, within the jurisdiction of the Income-tax office at Hooghly.
CIT, WB-XI, Calcutta.	-do-	ITO, Ward-1 Midnapur	All such cases referred to above where the offices of the DDOs making the TDS u/s. 195 lie. within the jurisdiction of the Income-tax office at Midnapur.
-do-	-do-	ITO Haldia	All such cases referred to above where the offices of the DDOs making the TDS u/s. 195 lie. within the jurisdiction of the Income-tax Office at Haldia.
-do-	D.C. Range Asansol	ITO, Ward-I, Asansol	All such cases referred to above where the offices of the DDOs making the TDS u/s. 195 lie. within the jurisdiction of the Income-tax office at Asansol.
CIT, WB-XI Calcutta	D.C. Range Asansol	ITO, Ward-1 Durgapur.	All such cases referred to above where the offices of the DDOs. making the TDS u/s. 195 lie. within the jurisdiction of the Income-tax office at Durgapur.
-do-	-do-	ITO, Ward-I Burdwan	All such cases referred to above where the offices of the DDOs. making the TDS u/s. 195 lie. within the jurisdiction of the Income-tax office at Burdwan.
-do-	-do-	ITO, Suri	All such cases referred to above where the offices of the DDOs making the TDS u/s. 195 lie. within the jurisdictionof the Income-tax office at Suri.
-do	-do-	ITO, Bankura.	All such cases referred to above where the offices of the DDOs making the TDS u/s. 195 lie. within the jurisdiction of the Income-tax office at Bankura.
CIT, WB-XI Calcutta.	D.C. Range Asansol	ITO, Purulia	All such cases referred to above where the offices of the DDOs making the TDS u/s. 195 lie. within the jurisdiction of the Income-tax office at Purulia.

[No. AC-/HQ/Planning/345]

K.P. SINGH Chief Commissioner of Income-tax-III Calcutta.

A.K. BATABYL, Chief Comm. of Income-tax-II Calcuita.

K.P. SINGH, Chief Comm. of Income-tax Calcutta.

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1994

स्टाम्प

का. आ. 115.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 के उपखंड (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम, बम्बई को मात्र पन्द्रह लाख तिहत्तर हजार एक सौ पच्चीस रुपये का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है, जो कि उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र बीस करोड़ सतानबे लाख और पचास हजार रुपये के कुल मूल्य के 1 से 239 तक की विशिष्ट संख्या वाले 13% एमएसएफसी बांडों 2007 (65वीं श्रृंखला) के प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप के बांडों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं. 36/93-स्टाम्प/फा. सं. 33/32/93-वि. क.]

आत्मा राम, अवर सचिव

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 21st December, 1994

STAMPS

S.O. 115.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits Maharashtra State Financial Corporation, Bombay to pay consolidated stamp duty of rupees fifteen lakh, seventy three thousand, one hundred and twenty five only, chargeable on account of the stamp duty on 13% MSFC Bonds 2007 (65th Series) bearing distinctive numbers 1 to 239 bonds in the form of promissory notes of the aggregate value of rupees twenty crores, ninety seven lakhs and fifty thousand only to be issued by the said Corporation.

[No. 36/93-Stamps/F. No. 33/32/93-ST]

ATMA RAM, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1995

का. आ. 116.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित खंड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा श्री टी. पी. करुणानन्दन, वर्तमान महाप्रबंधक, इंडियन बैंक, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31 जुलाई, 1997 तक के लिए, बैंक आफ इंडिया के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित) के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 9/28/94-बी. ओ. II]

के. के. मंगल, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 3rd January, 1995

S.O. 116.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri T. P. Karunanandan, presently General Manager, Indian Bank, as a whole-time Director (designated as the Executive Director) of Bank of India, for the period from the date of his taking charge and upto 31st July, 1997.

[F. No. 9/28/94-BO.I]

K. K. MANGAL, Under Secy.

उद्योग मंत्रालय

(लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1995

का. आ. 117:—कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 27 (34)-ई. ओ./92 (एस. एस.) तारीख 9/1/1992 और अधिसूचना सं. का. आ. 326 (अ) दिनांक 20-5-1993 के अनुसरण में श्रीमती मिन्नी मैथ्यू, भा. प्र. से. (आ. प्र.: 76), सचिव, कॉयर बोर्ड को इनकी कार्य-अवधि समाप्त होने पर इन्हें 5 सितम्बर, 1994 से इनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन किया जाता है।

[फा. सं. 2 (9)/88-कॉयर]

एम. साहू, निदेशक

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of SSI & ARI)

New Delhi, the 10th January, 1995

S.O. 117.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 27(34)-EO/92(SM), dated the 9th January, 1992, notification No. S.O. 326(E), dated 20th May, 1993 Smt. Minnie Mathew, IAS(AP:76), Secretary, Coir Board on expiry of her tenure is reverted to her parent cadre with effect from 5th September, 1994.

[File No. 2(9)/88-Coir]

M. SAHU, Director

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1995

का. आ. 118 :—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के अधीनस्थ निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80% कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:

1. राजवन सीमेंट फैक्टरी,
   सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.,
   राजवन, सिरमौर,
   हिमाचल प्रदेश-173028

2. अकलतरा सीमेंट फैक्टरी,
   सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.,
   अकलतरा,
   बिलासपुर, मध्य प्रदेश-495549

3. दिल्ली जोनल कार्यालय
सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.,
10, दरियागंज,
नई दिल्ली-110002.

4. लखनऊ जोनल कार्यालय,
सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.,
498/143 का, नियर आई.टी. क्रासिंग,
फैजाबाद रोड़,
लखनऊ-226007.

[सं. ई-11012/(1)/92-हिन्दी]
ओ.पी. शरवर, उप सचिव

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 2nd January, 1995

S.O. 118.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices/units of the Cement Corporation of India Ltd. whereof 80 per cent staff have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Rajban Cement Factory,
Cement Corporation of India Ltd.,
Rajban, Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh.

2. Akaltara Cement Factory,
Cement Corporation of India Ltd.,
Akaltara, Distt. Bilaspur
Madhya Pradesh-495549.

3. Delhi Zonal Office
Cement Corpo. of India Ltd.,
10, Daryaganj, New Delhi-110 002.

4. Lucknow Zonal Office,
Cement Corpn. of India Ltd.,
498/143 KA, Near I.T. Crossing,
Faizabad Road, Lucknow-226007.

[No. E. 11012(1)/92-Hindi]
O.P. SHARVAR, Dy. Secy.

विदेश मंत्रालय

(हज सैल)

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1994

का.आ. 119.—हज समिति अधिनियम, 1959 की धारा 12(1) के अनुसार भारत सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में पूर्व सहायक निदेशक श्री शबी अहमद को हज समिति, बम्बई के कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्री अहमद हज समिति अधिनियम, 1959 में निर्दिष्ट कार्यकारी अधिकारी की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

2. श्री अहमद कार्यकारी अधिकारी का पद भार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 12 दिसम्बर, 1994 से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर होंगे।

[सं. एम (हज) 118-1/3/94]
आर.एल. नारायण, संयुक्त सचिव (ईई/हज)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Haj Cell)

New Delhi, the 15th December, 1994

S.O. 119.—In exercise of the powers vested in the Government of India in terms of Section 12(1) of the Haj Committee Act, 1959 Shri Shabi Ahmed, formerly holding the post of Assistant Director in Indian Council of Historical Research, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi has been appointed as Executive Officer, Haj Committee, Bombay. Shri Ahmed will exercise all the powers of the Executive Officer mentioned in the Haj Committee Act, 1959.

2. Shri Ahmed will be on deputation for a period of two years with effect from 12th December, 1994 on which date he assumed charge of the post of Executive Officer.

[No. M(Haj) 118-1/3/94]
R. L. NARAYAN, Jt. Secy. (EE/Haj)

वाणिज्य मंत्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

डी ई एस-3 (इंजीनियरिंग) अनुभाग

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1995

का. आ. 120—मै. माकन गोल्ड ओवरसीज लि., बी -10, राजनिवास मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054 को डी ई ई सी बुक सं. 021118 दिनांक 29-9-92 (भाग 1) (आयात) और 2(निर्यात) सहित 8,91,09562 रु. (29,21,625 अमरीकी डालर) के निर्यात आधार वाले 7,07,21,875 रु. (23.18,750 अमरीकी डालर) के सागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए एक अग्रिम लाईसेंस सं. पी. / के / 1514193 दिनांक 29-9-92 मंजूर किया गया था, जिसकी वैधता अवधि फर्म जारी करने की तिथि से 12 महीने थी ने इस अग्रिम लाईसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की दूसरी प्रति इस आधार पर प्रदान करने के लिए आवेदन किया है कि यह खो गयी है। ईधर उधर हो गई है फर्म ने आवश्यक हलफनामा प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार पूर्वोक्त अग्रिम लाईसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रति को स्टेट बैंक मैसूर कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली से पंजीकृत कराया गया था और 5,00,06,212 रु. के लिए इस्तेमाल किया गया था और लाईसेंस के मद्दे बकाया सागत बीमा भाड़ा मूल्य 2,07,15,-663 रु. है। हलफनामे में इस आशय की घोषणा भी समाविष्ट की गई है कि अग्रिम लाईसेंस की उक्त विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति का बाद में पता चलने पर या उसके मिलने पर उसे लौटा दिया जाएगा।

2. इस बात से संतुष्ट होने पर कि अग्रिम लाइसेंस की मूल विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है, अधोहस्ताक्षरी का यह निर्देश है कि इस अग्रिम लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की दूसरी प्रति जारी की जाए। साथ ही विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा-9 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा केवल अग्रिम लाईसेंस सं. पी./के./ 1514193 दिनांक 29-9-92 की मूल विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति निरस्त करता हूं।

[फाइल सं. 01/81/40/606/ए एम/93/डी ई एस-3]
आर. के. सूद, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार
कृते महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

(Directorate General of Foreign Trade)

DES-III (Engg) Section

New Delhi, the 11th January, 1995

S.O. 120.—M|s. Maken Gold Overseas Limited, B-10, Raj Niwas Marg, Civil Lines, Delhi-110054 were granted an Advance Licence No. P|K|1514193 dated 29-9-92 for CIF value of Rs. 7,07,21,875=00 (US $ 23,18,750=00) with an Export Obligation of Rs. 8,91,09,562=00 (US $ 89,21,625=00) alongwith DEEC Book No. 021118 dated 29-9-92 (Part-I) (Import) & II (Export) with a validity of 12 months from the date of issue of the Licence. Now the firm have applied for grant of duplicate of the Exchange control Purpose been incorporated in the affidavit to the effect that the same have been lost|misplaced. The firm have furnished necessary affidavit according to which the aforesaid Exchange Control copy of Advance Licence was registered with the State Bank of Mysore, Kasturba Gandhi Marg; New Delhi and was utilised for Rs. 5,00,06,212=00 leaving unutilised CIF value of Rs. 2,07,15,663=00. A declaration has also been incorporated in the affidavit to the effect that if the said Exchange Control Purpose Copy of the Advance Licence is traced or found later on, it will be returned to the Issueing Authority.

2. On being satisfied that the Original Exchange control purpose copy of the Advance Licence has been lost, the undersigned directs issuance of duplicate Exchange control purpose copy of this Advance Licence. I also, in exercise of the powers conferred in sub-clause (4) of Clause 9 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act. 1992, hereby cancel the Original Exchange Control Purpose Copy of the Advance Licence No. P|K|1514193 dated 29-9-92.

[File No. 01|81|40|606|AM-93|DES-III]

R. K. SOOD, Dy. Director General of Foreign Trade
For Director General of Foreign Trade.

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1995

का.आ. 121:--केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे :--

सारणी

क्रम सं.	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (गेल) के अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2	3
1.	प्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली।	नई दिल्ली में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नगर क्षेत्रों के अलावा विविध कार्य केन्द्रों में निवासीय कार्यालय प्रयोजन के लिए पट्टे और कंपनी के स्वामित्व वाले स्थान।
2.	प्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., (उत्तर प्रदेश), नौएडा।	उत्तर प्रदेश में नौएडा स्थित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नगर क्षेत्रों के अलावा विविध कार्य केन्द्रों में निवासीय कार्यालय प्रयोजन के लिए पट्टे और कंपनी के स्वामित्व वाले स्थान।
3.	ज्येष्ठ उप प्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., झबुआ, (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश में झबुआ स्थित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नगर क्षेत्रों के अलावा विविध कार्य केन्द्रों में निवासीय कार्यालय प्रयोजन के लिए पट्टे और कंपनी के स्वामित्व वाले स्थान।
4.	ज्येष्ठ उप प्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., बड़ौदा, (गुजरात)	गुजरात में बड़ौदा तथा वधोविया स्थित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नगर क्षेत्रों के अलावा विविध कार्य केन्द्रों में निवासीय कार्यालय प्रयोजन के लिए पट्टे और कंपनी के स्वामित्व वाले स्थान।
5.	ज्येष्ठ प्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., औरय्या, (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश में औरय्या और पाता स्थित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नगर क्षेत्रों के अलावा विविध कार्य केन्द्रों में निवासीय कार्यालय प्रयोजन के लिए पट्टे और कंपनी के स्वामित्व वाले स्थान।
6.	उप प्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नगर क्षेत्रों के अलावा विविध कार्य केन्द्रों में निवासीय कार्यालय प्रयोजन के लिए पट्टे और कंपनी के स्वामित्व वाले स्थान।

(1)	(2)	(3)
7.	ज्येष्ठ प्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि०, मुम्बई ।	महाराष्ट्र में मुम्बई स्थित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नगर क्षेत्रों के अलावा विविध कार्य केन्द्रों में निवासीय कार्यालय प्रयोजन के लिए पट्टे और कंपनी के स्वामित्व वाले स्थान ।
8.	कार्मिक और प्रशासनिक अधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., हजीरा, (गुजरात)	गुजरात में हजीरा स्थित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नगर क्षेत्रों के अलावा विविध कार्य केन्द्रों में निवासीय कार्यालय प्रयोजन के लिए पट्टे और कंपनी के स्वामित्व वाले स्थान ।

[संख्या एल- 11011/9/94--जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक,

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 3rd January, 1995

S.O. 121 :—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below, being the officers equivalent to the rank of a gazetted officer of the Government, to be estate officers for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction, in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :—

TABLE

Sl. No.	Designation of the Officer of the Gas Authority of India Limited (GAIL)	Categories of public premises and local limits of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Manager (Personnel and Administration), Gas Authority of India Limited, New Delhi	Leased and company owned premises for residential office purpose, besides townships, in various work centres under the administrative control of the Gas Authority of India Limited in New Delhi
2.	Manager (Personnel and Administration), Gas Authority of India Limited, (Uttar Pradesh), NOIDA	Leased and company owned premises for residential office purpose, besides townships, in various work centres under the administrative control of the Gas Authority of India Limited at NOIADA in Uttar Pradesh.
3.	Sr. Deputy Manager, (Personnel & Administration, Gas Authority of India Limited, Jhabua (Madhya Pradesh)	Leased and Company owned premises for residential office purpose, besides townships, in various work centres under the administrative control of the Gas Authority of India Limited at Jhabua in Madhya Pradesh.
4.	Sr. Deputy Manager (Personnel & Administration), Gas Authority of India Limited, Baroda (Gujarat)	Leased and company owned premises for residential office purpose, besides townships, in various work centres under the administrative control of the Gas Authority of India Limited at Baroda and Vaghodia in Gujarat.
5.	Sr. Manager (Personnel and Administration), Gas Authority of India Limited, Auraiya (Uttar Pradesh)	Leased and company owned premises for residential office purpose, besides townships, in various work centres under the administrative control of the Gas Authority of India Limited at Auraiya and Pata in Uttar Pradesh.
6.	Dy. Manager (Personnel and Administration) Gas Authority of India Limited, Lucknow (Uttar Pradesh).	Leased and company owned premises for residential office prurpose, besides ownships, in various work centres under the administrative control of the Gas Authority of India Limited at Lucknow, in Uttar Pradesh.
7.	Sr. Manager (Personnel and Administration), Gas Authority of India Limited, Bombay	Leased and company owned premises for residential office purpose, besides townships, in various work centres under the administrative control of the Gas Authority of India Limited at Bombay in Maharashtra.
8.	Personnel and Administrative Officer, Gas Authority of India Limited, Hazira (Gujarat)	Leased and company owned premises for residential office purpose, besides townships, in various work centres under the administrative control of the Gas Authority of India Limited at Hazira, in Gujarat.

[No. L-11011/9/94-GP]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1995

का. आ. 122:—यत पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962] (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का. आ. सं. 640 तारीख/17-2-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

वाद-अनुसूची

एच. बी. जे. अपग्रेडेशन पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र. बीघा/एकड़/हेक्ट.	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
आगरा	किरावली	किरावली	सिरौली	2	0.1860	चकरोड
				4	0.0060	
				6	0.2400	
				7	0.0060	
				9	0.0720	
				10	0.4724	
				11	0.0080	चकरोड
				17	0.0032	
				16	0.5746	
				15	0.0828	
				37	0.0600	
				45	0.0216	
				44	0.5394	
				43	0.0120	
				46	0.0432	चकरोड
				42	0.1380	
				76/1	0.1800	
				76/2	0.6736	
				77	0.1974	
				75	0.0120	
				70	0.0250	
				69	0.0800	

1	2	3	4	5	6	7
आगरा	किरावली	किरावली	सिरौली	68/1	0.0050	
				68/2	0.1400	
				122/9	0.0900	
				122/3	0.1500	
				122/8	0.0720	
				122/5	0.1104	
				122/7	0.1224	
				122/19	0.5532	नदी
				178	0.0360	पहाणी भाग
				104	0.0624	
				योग 32	4.9746	हेक्टेयर
					या– 12.287	एकड़
					या– 19-13-04	बीघा

[सं. एल-14016/22/94 जी पी]

अर्धेन्दु सैन, निदेशक

New Delhi, the 5th January, 1995

S.O. 122.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 640 dated 17-2-94 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act), 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

CASE SCHEDULE

H.B.J. Upgradation Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Agra	Kiraoli	Kiraoli	Sirauli	2	0.1860	
				4	0.0060	Chakroad
				6	0.2400	
				7	0.0060	
				9	0.0720	
				10	0.4724	
				11	0.0080	Chakroad
				17	0.0032	
				16	0.5746	
				15	0.0828	

1	2	3	4	5	6	7
Agra	Kiraoli	Kiraoli	Sirauli	37	0.0600	
				45	0.0216	
				44	0.5394	
				43	0.0120	Chakroad
				46	0.0432	
				42	0.1380	
				76/1	0.1800	
				76/2	0.6736	
				77	0.1974	
				75	0.0120	
				70	0.0250	
				69	0.0800	
				68/1	0.0050	
				68/2	0.1400	
				122/9	0.0900	
				122/3	0.1500	
				122/8	0.0720	
				122/5	0.1104	
				122/7	0.1224	
				122/19	0.5532	River
				178	0.0360	Hill Area
				104	0.0624	
			Total	32	4.9746	
				Or	12.287	Acres
				Or	19-13-04	Bigha

[No. L-14016/22/94-G.P.]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1995

का. आ. 123—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का. आ. सं. 639 तारीख 17-2-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों की बिछाने के लिए अर्जित करने का आशय कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है। और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट, भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

वाद अनुसूची

एच. बी. जे. अपग्रेडेशन पईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र. बीघा/एकड़/हेक्ट.	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
आगरा	किरावली	किरावली	जाजौली	367	0.0060	चकरोड
				368	0.1480	
				371	0.0040	
				372	0.0830	
				373	0.0240	
				374	0.0060	चकरोड
				375	0.2360	
				378	0.1410	
				379	0.2660	
				383	0.1320	
				391	0.0060	चकरोड
			योग	11	1.0620	हेक्टेआर
				या	2.624	एकड़
				या	04-03-19	बीघा

[सं. एल 14016/22/94जी.पी.)]

आर्घेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 5th January, 1995

S.O. 123.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 639 dated 17-2-94 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And fkurther in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

CASE SCHEDULE

H.B.J. Upgradation Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Agra	Kirawali	Kirawali	Jajauli	367	0.0060	Chackrod
				368	0.1480	
				371	0.0040	
				372	0.0830	
				373	0.0240	

1	2	3	4	5	6	7
				374	0.0060	Chackrod
				375	0.2360	
				378	0.1510	
				379	0.2660	
				383	0.1320	
				391	0.0060	
				Total 11	1.0620	Hectare
				Or	2.624	Acre
				Or	04-03-19	B gha

[No. L-14016/22/94-G.P.]
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 5 जनवरी 1995

का. आ. 124—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का. आ. सं. तारीख 638/17-2-94 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

वार अनुसूची

एच. बी. जे. अपग्रेडेशन पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्र. बीघा/एकड़/हेक्ट.	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
आगरा	किरावली	किरावली	सहनपूर	76	0.2870	चकरोड
				81	0.0060	
				88	0.1020	
				89	0.1694	
				87	0.0322	
				90	0.1058	
				91	0.0060	
				92	0.8240	
				75	0.0280	

1	2	3	4	5	6	7
आगरा	किरावली	किरावली	सहसपुर	67	0.1000	
				74	0.4980	
				191	0.0060	चकरोड
				195	0.1392	
				208	0.1280	
				207	0.0360	चकरोड
				206	0.8700	
				196	0.0050	चकरोड
				201	0.0204	
				223	0.0060	चकरोड
				224	0.4500	
				257	0.0060	चकरोड
				324	0.4824	
				323	0.0088	चकरोड
				320	0.0880	
				270	0.0088	चकरोड
				266	0.0360	
				267	0.1980	
				269	0.1196	
				317	0.0144	
				271	0.0035	चकरोड
				278	0.1170	
				279	0.4020	
				281	0.1440	
				282	0.0060	चकरोड
				291	0.3780	
				293	0.2700	
				295	0.0060	चकरोड
				294	0.3300	
				298	0.1090	
				308	0.5220	
				311	0.0180	बघा
				431	0.1900	
				432	0.1680	
				433	0.2400	
				441	0.2700	
				463	0.0860	
				442	0.0960	
				443	0.0108	
				457	0.0108	चकरोड
				464	0.0380	
				465	0.2440	
				466	0.1440	
				467	0.1780	
				466	0.2140	
				469	0.0060	चकरोड

1	2	3	4	5	6	7
आगरा	किरावली	किरावली	सहनपुर	470	0.3513	
				472	0.3414	
				473	0.0640	
				475	0.3400	
				719	0.0600	रोड
				727	0.1630	
				728	0.0180	
				732	0.0600	
				733	0.0080	चकरोड
				737	0.1600	
				738	0.0720	
				739	0.0540	
				740	0.0540	
				741	0.1209	
				803	0.0270	
				777	0.2912	रास्ता
				745	0.0168	
				803		
				860	0.0060	चकरोड
				802	0.5925	
				796	0.1415	
				795	0.0288	
				797	0.0096	
				794	0.2324	
				808	0.0108	चकरोड
				809	0.4735	
				781	0.0480	
				योग 81	12.7089	हेक्टयर
				या -	31.391	एकड़
				या -	50-04-10	बीघा

[सं. एल-14016/22/94 जी. पी.]
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 5th January, 1995

S.O. 124.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 638 dated 17-2-94 under sub-section (1) of section of the Petroleum and Minerals Pipelines [Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962)], the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declare that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the fight of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited ~~free from encumbrances.~~

CASE SCHEDULE

H.B.J. Upgradation Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in Bigha/Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Agra	Kiraoli	Kiraoli	Sahanpur	76	0.2870	
				81	0.0060	Chakroad
				88	0.1020	
				89	0.1694	
				87	0.0322	
				90	0.1058	
				91	0.0060	Chakroad
				92	0.8240	
				75	0.0280	Chakroad
				67	0.1000	
				74	0.4980	
				191	0.0060	Chakroad
				195	0.1392	
				208	0.1280	
				207	0.0360	Chakroad
				206	0.8700	
				196	0.0050	Chakroad
				201	0.0204	
				223	0 0060	Chakroad
				224	0.4500	
				257	0.0060	Chakroad
				324	0 4824	
				323	0.0088	Chakroad
				320	0.0880	
				270	0.0088	Chakroad
				266	0.0360	
				267	0.1980	
				269	0.1196	
				317	0.0144	
				271	0.0036	Chakroad
				278	0.1170	
				279	0.4020	
				281	0.1440	
				282	0.0060	Chakroad
				291	0.3780	
				293	0.2700	
Agra	Kiraoli	Kiraoli	Sahanpur	295	0.0060	Chakroad
				294	0.3300	
				298	0.1090	
				308	0.5220	

1	2	3	4	5	6	7
Agra	Kiraoli	Kiraoli	Sahanpur	424	0.0180	Bandha
				431	0.1900	
				432	0.1680	
				433	0.2400	
				441	0.2700	
				463	0.0860	
				442	0.0960	
				443	0.0108	
				457	0.0180	Chakroad
				464	0.0380	
				465	0.2440	
				466	0.1440	
				467	0.1780	
				468	0.2140	
				469	0.0060	Chakroad
				470	0.3513	
				472	0.3414	
				473	0.0640	
				475	0.3400	
				719	0.0600	Chakroad
				727	0.1630	
				728	0.0180	
				732	0.0600	
				733	0.0080	Chakroad
				737	0.1600	
				738	0.0720	
				739	0.0540	
				740	0.0540	
				741	0.1209	
				803	0.0270	
				777	0.2912	Chakroad
				745	0.0168	
				803	0.0060	Chakroad
				860		
				802	0.0935	
				796	0.1415	
				795	0.0288	
				797	0.0096	
				794	0.2324	
				808	0.0108	Ckakroad
				809	0.4735	
				781	0.0480	
			G. Total	81	12.7089	Hectares
				Or	31.391	Acres
				Or	50-04-10	Bigha

[No. L-14016/22/94-G.P.]

ARDHENDU SENI, Director

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1995

का.आ. 125.—भारत का राजपत्र दिनांक 19-3-94 के भाग—2 खण्ड 3; उप खण्ड (2) के पृष्ठ संख्या 902 पर प्रकाशित भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खनिज पाइप लाइन के (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम संख्या 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप धारा (i) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या 735 दिनांक 8-3-94 ग्राम बमनई कलां परगना व तहसील खेरागढ़, जिला आगरा की प्रकाशित सूची के स्तम्भ 5, 6 व 7 में चक संख्या 121 गाटा संख्या 211, 212 व 213 क्षेत्रफल 0.164 के स्थान पर पहाड़ गाटा सं. 211 क्षेत्रफल 0.1000 एवं चक सं. 121 गाटा सं. 212, 213 क्षेत्रफल 0.0640 पढ़ा जाये। स्तम्भ 5 में चक संख्या 82 के स्थान पर 62 एवं 157 के स्थान पर गांव सभा भूमि पढ़ा जाये एवं सं. 175 के सामने स्तम्भ 6 में गाटा संख्या 222, 223, व 224 के साथ 218 एवं 220 भी पढ़ा जाये। चक संख्या 184 के सामने स्तम्भ 7 में 0.1200 एवं 0.2100 के स्थान पर 0.1980 क्षेत्रफल पढ़ा जाये। चक संख्या 303 गाटा सं. 190 क्षेत्रफल 0.0060 के स्थान पर गांव सभा भूमि गाटा सं. 190 191, क्षेत्रफल 0.1380 पढ़ा जाये।

[संख्या एल-14016/22/93-जी पी)]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th January, 1995

S.O. 125.—In the Gazette of India, Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 735 dated 8th March, 1994, published on 19th March, 1994 at page No. 902 in Volume-2, Part-3, Sub-section (ii) Under Sub-section (1) of Section-3 of Petroleum & Mineral Pipe-line (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) of Village-Bamnai Kalan, Pargana & Tehsil-Kheragarh, Distt.-Agra in volume 5, 6 & 7 be read as Hill Rock plot No. 211 area 0.1000 and Chak No. 121 Plot No. 212, 213 area 0.0640 instead of Chak No. 121 Plot No. 211, 212 and 213 area 0.1640. In column 5 Chak No. 62 be read instead of 82 and Gaon Sabha land instead of Chak No. 157. In column 6 against Chak No. 175 Plot No. 218 and 220 be also read together with Plot No. 222, 223 and 224. In column 7 the area against Chak No. 184 be read as 0.1980 instead of 0.1200 and 0.2100. In col. 5, 6 and 7 Gaon Sabha land Plot No. 190-191 area 0.1380 be read instead of Chak No. 303 Plot No. 190 area 0.0060

[No. L-14016/22/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1994

का.आ. 126.—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में और सिक्किम सरकार के परामर्श से डा. टी. आर. ग्यात्सो, अपर निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 138 तारीख 9 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्यांक 19 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"19. डा. टी. आर. ग्यात्सो,
अपर निदेशक,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,
सिक्किम सरकार, गंगटोक"

[संख्या वी. 11013/6/94-एम ई (यू. जी.)]

एस. के. मिश्र, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 8th December, 1994

S.O. 126.—Whereas the Central Government in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and in consultation with the Government of Sikkim have nominated Dr. T. R. Gyatso, Additional Director, Department of Health and Family Welfare, Government of Sikkim, Gangtok to be a member of the Medical Council of India with effect from the date of issue of this notification;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Ministry of Health Number S.O. 138 dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (a) of sub-section (1) of section 3" for serial number 19 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"19. Dr. T. R. Gyatso,
Additional Director,
Department of Health and Family Welfare,
Government of Sikkim,
Gangtok"

[No. V. 11013/6/94-ME(UG)]

S. K. MISHRA, Desk Officer

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1994

का.आ. 127.—चूंकि, निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में कतिपय संशोधन, जिन्हें केन्द्र सरकार अधिसूचित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली वृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 11-क के प्रावधानों

के अनुसार दिनांक 7-8-93 के नोटिस संख्या एफ-20(1)93—एम पी द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें जनता से अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में, आमंत्रित किए गए थे।

यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में एक आपत्ति/सुझाव जनता से प्राप्त हुआ है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है।

यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली वृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है।

अतः, अब केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11—क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहद योजना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :—

उप जोन एफ—11 (आई. आई. टी. और कटवारिया सराय) में आने वाले लगभग 0.937 हैक्टेयर (2.31 एकड़) क्षेत्रफल के भूमि उपयोग को, जो कि उत्तर तथा पश्चिम में एन. सी. ई. आर. टी. सीमा, पूर्व में महरौली रोड एवं अधचिनी गांव और दक्षिण में अरविन्द आश्रम से घिरा हुआ है, "सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" से "आवासों" में परिवर्तित किया जाता है।

[सं. के.—13011/23/92—डी डी आई बी]
एस. सी. सागर, अवर सचिव

MINISTRY OF UABAN DEVELOPMENT
(Delhi Division)

New Delhi, the 30th December, 1994

S.O. 127.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the area mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 20(1)/93-MP dated 7-8-93 in accordance with the provisions of Section 11-A of the said Act, for inviting public objections/suggestions within thirty days from the date of the said notice.

Whereas one objection/suggestion was received from the public with regard to the said proposed modification, which has been considered by the Authority.

And whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION :

The land use of an area measuring about 0.937 ha. (2.31 acres) falling in sub-zone F-11 IIT and Katwaria Sarai Area), bounded by NCERT boundary in the North and West, Mehrauli Road and Adchini Village in the East and Aurbindo Ashram in the South, is changed from 'Public and Semi-public facilities' to 'Residential'.

[No. K-13011/23/92-DDIB]
S. C. SAGAR, Under Secy.

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1995

का. आ. 128—भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की दिनांक 23 दिसम्बर 1992 की अधिसूचना सं. का. आ. 924 (अ) के तहत गोदी कामगारों के नियोजकों तथा पोत कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त कैप्टन वी. के. गुप्ता, उप महाप्रबंधक, भा. नौ. नि. कलकत्ता का भा. नौ. नि. के बम्बई स्थित कार्यालय में स्थानान्तरण हो गया है।

अतः अब गोदी कामगार (रोजगार का विनियमन) नियमावली, 1962 के नियम 4 के परन्तुक के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एल.बी.-13014/3/94-अ. स. (श्रम)]
एस. के. दरगन, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi, the 3rd January, 1995

S.O. 128.—Whereas Capt. V. K. Gupta, Deputy General Manager, S.C.I., Calcutta appointed as a member of the Calcutta Dock Labour Board representing the employers of Dock Workers and Shipping Companies vide notification of the Government of India, Ministry of Surface Transport (Transport Wing), No. S.O. 924(E) dated 23rd December, 1992 has since been thansferred to S.C.I. Office in Bombay.

Now, therefore, in pursuance of proviso to rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[No. LB-13014|3|94-US(L)]
S. K. DARGAN, Under Secy.

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1994

का. आ. 129—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड निम्नलिखित रेलों के कार्यालयों को, जहां कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है :—

पश्चिम रेलवे (रतलाम मंडल)

1. स्टेशन, इंदौर
2. स्टेशन, फतेहाबाद
3. स्टेशन, जावरा
4. स्टेशन, मन्दसौर

5. क्षेत्र अधिकारी, चित्तौड़गढ़
6. स्टेशन, भीलवाड़ा
7. स्टेशन, विजयनगर
8. स्टेशन, भैरोंगढ़
9. स्टेशन, बामनिया
10. स्टेशन, पंचपिपलिया
11. स्टेशन, पीपलोद
12. स्टेशन, संतरोड
13. स्टेशन, खाचरोद
14. स्टेशन, कालीसिंध
15. स्टेशन, शुजालपुर
16. स्टेशन सिहोर
17. स्टेशन, पंचावा
18. स्टेशन, फन्दा
19. स्टेशन, देवास
20. मंडल चिकित्सा अधिकारी, महू
21. रेल माध्यमिक विद्यालय, महू
22. रेल मा. विद्या. (हिन्दी माध्यम), रतलाम
23. रेल मा. विद्या. रतलाम

अजमेर मंडल

24. स्टेशन, रानी
25. स्टेशन, फालना
26. स्टेशन, जवाई बांध
27. स्टेशन, मारवाड़ जंक्शन
28. स्टेशन, काण्डला जंक्शन
29. स्टेशन, गांधीधाम
30. स्टेशन, मावली जंक्शन
31. स्टेशन राणाप्रताप नगर
32. स्टेशन, उदयपुर

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. लोको फोरमैन, हटिया
2. क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, रांची
3. सहायक अभियंता कार्यालय, रांची
4. स्टेशन, रांची
5. स्टेशन, मुरी
6. लोको फोरमैन, मुरी
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, बोकारो
8. दक्षिण पू. रे. मध्य विद्यालय, मोहुदा
9. मंडल चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, भागा
10. स्टेशन, भागा
11. मुख्य नियंत्रक कार्यालय, भोजूडीह
12. सहायक अभियंता, मोहुदा

पूर्व रेलवे (मालदा मंडल)

1. लोको शेड कार्यालय, जमालपुर
2. सहायक अभियंता कार्यालय, साहिबगंज
3. सहायक यांत्रिक अभियंता कार्या., साहिबगंज
4. सहायक अभियंता (भंडार) कार्या., साहिबगंज

हावड़ा मंडल

5. स्टेशन, कोटालपुकुर
6. स्टेशन, गुमानी

आसनसोल मंडल

7. स्टेशन, जसीडीह
8. स्टेशन, वैद्यनाथधाम
9. स्टेशन, कालुबथान
10. प्रबन्धक, संकेत कारखाना, हावड़ा

धनबाद मंडल

11. स्टेशन, रेणुकूट
12. सहायक अभियंता, चोपन
13. स्टेशन, चोपन
14. सहायक अभियंता, रेणुकूट

[सं. हिन्दी - 94/रा. भा 1/12/1]
एस. ए. ए. जैदी, सचिव, (रेलवे बोर्ड)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)
New Delhi, the 26th December, 1994

S.O.129.—In pursuance of sub-rules (2) and (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Railways (Railway Board), hereby notify the following Railway Offices where the staff have acquired the working knowledge of Hindi :—

Western Railway (Ratlam Division) :-

1.	Station	Indore
2.	Station	Fatehabad
3.	Station	Jaora
4.	Station	Mandasor
5.	Area Officer	Chittaurgarh
6.	Station	Bhilwara
7.	Station	Vijayanagar
8.	Station	Bhairongarh
9.	Station	Bamnia
10.	Station	Panch Piplia
11.	Station	Piplod
12.	Station	Sant Road
13.	Station	Khachrod
14.	Station	Kali Sindh
15.	Station	Shujaulpur
16.	Station	Sihor
17.	Station	Panchwa
18.	Station	Phanda
19.	Station	Dewas

20. Divisional Medical Officer, Mhow
21. Railway Secondary School, Mhow
22. Railway Secondary School (Hindi Medium), Ratlam.
23. Railway Secondary School, Ratlam.

Ajmer Division :—

24.	Station	Rani
25.	Station	Falana
26.	Station	Jawai Bandh
27.	Station	Marwar Jn.
28.	Station	Kundla Jn.
29.	Station	Gandhi Dham
30.	Station	Mavli Jn.
31.	Station	Rana Pratap Nagar
32.	Station	Udaipur

South Eastern Railway :—

1. Loco Foreman Hatia
2. Office of the Area Manager, Ranchi.
3. Office of the Asstt. Engineer, Ranchi.
4. Station Ranchi
5. Station Moori
6. Loco Foreman Moori
7. Area Manager Bokaro
8. South Eastern Railway Secondary School, Mahuda
9. Office of the Divisional Medical Officer, Bhaga.
10. Station Bhaga
11. Office of the Chief Engineer, Bhojudih.
12. Assistant Engineer, Mahuda.

Eastern Railway (Malda Division)—

1. Loco Shed Office, Jamalpur
2. Office of the Asstt. Engineer, Sahibganj.
3. Office of the Asstt. Mechanical Engineer, Sahibganj.
4. Office of the Asstt. Engineer (Stores), Sahibganj.

Howrah Division :—

5. Station Kotalpukur
6. Station, Gumani

Asansol Division :—

7. Station Jasidih
8. Station Baidyanath Dham
9. Station Kaluwadhan
10. Manager, Signal Workshop, Howrah.

Dhanbad Division :-

11. Station Renukut
12. Assistant Engineer, Chopan
13. Station Chopan
14. Assistant Engineer, Renukut.

[No. Hindi-94/OL-I/12/I]
S.A.A. ZAIDI, Secy. Railway Board

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1994

का.आ. 130—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 2, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-12-94 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/317/89-डी 2(ए)/आई.आर. (बी. 2)]
वी.के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st December, 1994

S.O. 130.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, 2, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 21-12-1994.

[No. L-12012/317/89-D.IIA/IR (B-II)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.
Reference No. CGIT-2/11 of 1990

Employers in relation to the management of Bank of India

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri L. L. D'Souza Representative.
For the Workmen—Shri C. D. Nargolkar, Advocate.

Bombay, the 1st December, 1994

AWARD PART I

Shri Umesh Chandra Agarwal, the workman joined the services of the Bank of India, the employer as an agricultural assistant at its Jalgaon branch with effect from 18-4-77. He served in that capacity for about 10 1/2 years. On 17-5-75, he was suspended. Thereafter a chargeshcet dated 20-9-85 was given to him.

2. The Employer appointed Enquiry Officer, Presiding Officer and a domestic enquiry was conducted against the workman. He was held guilty against the charges and he was dismissed from the services of the Bank with effect from 16-10-87.

3. The workman contended that the enquiry which was conducted was unfair and improper and against the principles of natural justice in which proper appreciation of evidence was not done and the punishment of dismissal was harsh and disproportionate to the alleged charges. It is pleaded that the Enquiry Officer was pre-determined and had a bias mind. It is therefore the findings of the Enquiry Officer are perverse and not in accordance with the evidence on the record. The workman was not given full opportunity to represent his case nor his arguments were received and considered. It is submitted that the important witnesses such as Mr. Patil was not examined and no weightage was given to Mr. Patil's withdrawal to the earlier complaints made by him under appreciation. Infact, the charge relates to the inflated price by the workman but the findings of the Enquiry Officer does not mention single word about it and holds the workman guilty of the charge.

4. The workman raised an industrial dispute which came to be sent to this Tribunal for adjudication by the Central Government Labour Ministry in the following terms :

> "Whether the action of the management of Bank of India in dismissing Shri U. C. Agarwal, Agricultural Assistant in the Bank of India, was justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

5. The management by its written statement Exh. 3 denied the contents of the workman. It is asserted that the procedure in respect of the departmental enquiry was rightly followed and there is no lacuna. The report of the Enquiry Officer is speaking so clearly stating forthwith reasons for the conclusion arrived at by them. He considered all the materials placed before him. It is submitted that the workman was given personal hearing to the show cause notice that was given to him with the affidavit and following necessary steps which are required to be followed in the case of domestic enquiry the order of dismissal was issued. His appeal was also refected. The action of the management in dismissing the workman from services without notice is just and the workman is not entitled to any relief.

6 The management affirmed that in the domestic enquiry the charges that were levelled against the workman were duly proved and the findings of the Enquiry Officer were just and proper. Under such circumstance and punishment

of dismissal against the workman is justified. It is pleaded that the workman is not entitled to any relief as claimed by him.

7. My Learned Predecessor framed issues at Exh. 4 for determination. On December 3, 1992 he passed an order to that effect that issue No. 1 is to be tried as a preliminary issue. By this award I have to decide it. The issue and my finding thereon is as under :

ISSUE	FINDING
1. Whether the inquiry held against the workman was not held properly and the rules of natural justice were not followed ?	The inquiry is just and proper.

REASONS

8. Shri U. C. Agarwal filed his affidavit at Exh. 9 by way of examination in chief. The management did not cross-examine the witness and had endorsed on it in the following words :

"As the workman had admitted the enquiry proceedings, the Bank does not want to cross-examine the workman on priliminary issue".

As against this Shri R. B. Dalal the Enquiry Officer had lead evidence in support of the management to prove the enquiry as just and proper and the principles of natural justice were followed.

9. The procedure of conducting an enquiry in the alleged act of mis-conduct is stated in chapter 19 of the Bipartite Settlement dated 19-10-66. Para 19.12 (A) of it deals with the enquiry procedure. Shri Dalal affirmed that he followed all the procedure contemplated therein.

10. The workman in para 2 of his affidavit had given details by which he wants to establish that the domestic enquiry which was held against him was against the principles of natural justice and the procedure. He affirmed that he was not explained the procedure of the enquiry. Infact, I do not find that the Bipartite Settlement wants any explanation of the procedure of the enquiry to the delinquent i.e. the workman. But the facts of this case reveal that the workman is aware of the procedure that was to be followed. The workman was represented by the Deputy General Secretary of the Bank of India Staff Union. It is therefore by no stretch of imagination it can be said that the representative or the workman was not aware of the procedures in a departmental enquiry. The management had filed documents at Exh. 5 regarding the whole bunch of the enquiry report. On page 4 and 17 of it, there is a reference in respect of the procedure. A time table is given how the enquiry will be conducted. Furthermore, Shri Dalal had affirmed that he explained the workman how the enquiry will be conducted.

11. The workman affirmed that he was not informed how he can set up a defence. It is rightly submitted that the workman has to be given an opportunity to lead oral and documentary evidence which were given to him. He was given an opportunity to go to the places he wanted to go for the collection of evidence. It is none of the business of the Enquiry Officer to tell the workman what defence he should take. It was the union of the workman and the representative to take suitable defence in the matter.

12. The third contention of the workman is that the documents were not exhibited at relevant times and they rate ambignously relied upon. There appears to be no merit in it. It is because all documents were completed, exhibited and handed over before the evidence could be lead. It can be further seen that nothing is brought on the record how a prejudice was caused to the workman as the documents were not exhibited while in defence. It is not in the case of the workman that the documents were not made available on which the Presenting Officer was relying. On page 19 of the document at Exh. 5 it is mentioned that all the nine documents were inspected by the workman and his representative, and that they are allowed to be exhibited. It is signed by the workman and his representative. Non-exhibiting these documents at the time of the enquiry itself had not at all prejudiced the workman. On 11-12-85 the Presenting Officer submitted a list of the witnesses and a copy of the same was handed over to the defence representative, Office Bearers on page 11 of Exh. 5. On 19-3-86 the defence representative also submitted the list of the witnesses and those documents i.e. the list were taken on the record. That itself goes to show that the workman was aware that each witness could be examined by the management for proving the charge. The grievance that the names of the witnesses were not recorded in the enquiry proceedings has no merit. It has not caused any prejudice to the workman.

13. After cross-examination of the Bank's witnesses the representative of the union stated that he may call the witness for further cross-examination, if necessary. Infact, unless he seeks permission for re-calling the witness again, he had no right to re-call the same. It is not that he is allowed to fill up the gaps by re-calling the witnesses of the management. Leaving aside this aspect of the matter there is no record to show that he gave an application for re-calling the witness with cojent reasons and that application was rejected. Under such circumstances, there is no merit in the contention that as the witnesses were not re-called he is prejudiced.

14. The workman affirmed that there was no response to the Enquiry Officer that his evidence has to be taken first and it is impossible. There is no strict rule or procedure how the witnesses are to be examined and by the defence i.e. the workman. The Enquiry Officer asked the workman whether he wents to lead any evidence by examining the witness including himself in his defence (Page 17 and 66 of the enquiry report). But the workman and his representative replied in the negative. What is necessary in such an enquiry is to give an opportunity which was given in the present case. The Enquiry Officer cannot compel the delinquent, to come in to the witness box with an interest to lead evidence and to examine the witness.

15. The workman had affirmed that his written arguments were not considered while drawing the conclusions. It can be seen that earlier submissions or written arguments are given to facilitate the Enquiry Officer to appreciate the evidence. Those earlier arguments or written statements in fact has no force of law. The Enquiry Officer has to come to the conclusion on the basis of the documents and evidence which is before him. In para 19.12 (A) of the Bipartite Settlement there is nothing in respect of written or oral arguments. On its basis it is tried to argue that the contention taken by the workman has no merit. I am not inclined to accept it. The written arguments are taken into consideration while appreciating the evidence. Here in this case on its basis it is not done so. Now it has to be seen what is its effect. Whether any prejudice is caused, to the workman by it.

16. The workman submitted his written brief on 30-6-87 when infact, he should have submitted the same on or before 30-11-86. Before that the Enquiry Officer had drawn up his defence without considering even the Banks written brief and submitted his report. Mr. Dalal had affirmed that he had also not considered the written arguments of the Bank, while giving his findings. It can be seen that at a given time the written argument was not shbmitted by the workman, therefore it is unjust to say that the Enquiry Officer should have waited till he files his written submission or that he should have send reminders to him for filing his written submissions. I therefore find that no prejudice is cased to the workman for not giving consideration to his written statement, or submissions. Infact, those would not be considered as his report was already submitted.

17. It is admitted position that in a domestic enquiry the workman fully participated and was defended by his representative of his charge. The chargesheet was explained to him properly. He has no grievance that the charges which were levelled against him were ambiguous and he did not follow them. After going through the chargesheet I do not find any ambiguity in the same. The Banks witnesses were examined in the presence of the workman and his defence representative, and they were offered for cross-examination. The documents which were relied upon by the Bank and those which were called for were listed and supplied to the workman before the evidence could commence. For this the workman was also prepared to produce his own witnesses and examine himself in his defence.

18. It reveals that the Enquiry Officer submitted his report on 30-6-87. He had given reasons for coming to the conclusions. After receipt of the report the disciplinary authority offered applying its list to the material on the record concurrent with the defence of the Enquiry Officer. Thereafter the workman was then issued with the show cause notice dated 8-8-87 proposing therein the common punishment of dismissal without notice. The order of the Enquiry Officer and the defence were also included along with the show cause notice. By the said show cause notice the workman was given an opportunity to make his submissions to the disciplinary authority on the proposed punishment of dismissal without notice.

19. Thereafter the Disciplinary Authority gave a personal hearing to the workman and his representative on 31-8-87. It is admitted position that a copy of the minutes of the personal hearing was given to the workman after considering the seriousness of the charges and the gravity of the misconduct proved against the workman who confirmed the proposed punishment of dismissal without notice from the service. Thereafter he was dismissed.

20. It can be further seen that the workman thereafter preferred an appeal to the Appellate Authority on 16-12-1987 against the order of dismissal. He submitted before the Appellate Authority along with Shri Shukla, General Secretary of the Bank of India Staff Union. The Appellate Authority after considering the submissions made by the workman and the representative and the record confirmed the punishment of dismissal. Thereafter it was imposed on the workman.

21 In the case of Sur Enamel and Stamping Works Ltd. v/s. Their Workmen 25 FJR 88 and in Maharashtra State Road Transport Corporation v/s. Prabhakar Kashinath Patate and other 1979 LIC 138 Their Lordships have observed that what is necessary for a proper domestic enquiry. The particulars laid down in this authority are observed by the Enquiry Officer is in the present case while holding Domestic Enquiry against the workman. I do not find that he had committed any irregularity in the procedure by which it can be said that the workman is prejudiced. I also do not find that any principles of natural justice were violated while holding a domestic enquiry. For all these reasons I record my findings on the points according and pass the following order :

ORDER

1. The departmental enquiry which was held against the workman was just and proper and the principles of natural justice were followed.

Dated : 1-12-1994

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1994

का.आ. 131—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पटियाला स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-12-94 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/84/90 आईआर बी(i)]

पी.जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd December, 1994

S.O. 131.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Patiala and their workmen, which was received by the Central Government on 20-12-1994.

[No. L-12012/84/90 IR(1)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI M. S. SULLAR, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I. D. 91/90

Kuldip Kumar

Vs.

State Bank of Patiala.

For the workman—Shri B. L. Sharma.

For the management—Shri N. K. Zakhmi.

Dated, the 8th November, 1994

AWARD

In the wake of Industrial Disputes raised by the workman, under Section 10(1) of the Industrial Disputes Act 1947 (hereinafter referred to as the act), the Central Government vide its Order No. L-12012/84/90-IR (B-III) dated the 17th July, 1990 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.

"Whether the action of State Bank of Patiala in terminating the services of Shri Kuldip Kumar Godown Chowkidar, at their New Grain Market Sangrur w.e.f. 6-7-86 is legal and justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled to and from what date ?"

2. The brief facts, culminating in the commencement of the present reference petition are that, the workman was appointed as Godown Chowkidar, in the branch of State Bank of Patiala, at Bhatinda on 9-1-84. The Management respondent had terminated his services, and the action of the management has been challenged by him, in the present reference.

3. The case set up by the workman, in brief in so far as relevant is that, he had worked in the Bhatinda branch of State Bank of Patiala as Godown Chowkidar from 9-1-84 to 8-3-1984 and in Sangrur branch from 14-3-86 to 5-7-86 when his services were terminated. According to the workman his service were terminated by the Management inviolation of the provision of Section 25-G and 25-H, of the Act, Sastri Award, Desai Award and Bipartite Settlement and as appointed other persons ignoring his claim. On the footing of aforesaid pleadings the workman claimed reinstatement with full back wages and continuity of service.

4. The Management contested the reference petition and filed the written statement, inter-alia pleading certain preliminary objections of maintainability of the reference petition as the workman had not completed 240 days of his service in 12 calendar months before his termination. According to the Management the case of the workman is not covered U/S 25-B and 25-F of the Industrial Disputes Act and non renewal of contract does not amount to retrenchment as defined under Section 2(oo) of the Act.

5. The case set up by the Management, in brief so far as the relevant, is that the workman had worked in Bhatinda Brach of the Bank from 9-1-84 to 8-3-84 only for a period of 60 days; at Sangrur branch from 14-3-86 to 5-7-86 as Godown Chowkidar. It is alleged that the appointment of the Workman was on purely temporary basis, in the factory premises of the borrowers, to whom the loan was advanced. The services of such employees were terminated as and when the loans were repaid by the borrowers. It was denied that any other persons in his place have been appointed by the Management. In all it has been alleged that the workman had not completed 240 days and his termination is not retrenchment as defined U/S 2(00) of the act. It will not be out of place to mention here that the Management has stoutly denied the other allegations of the workman. That

being so the Management prayed for the dismissal of the reference petition.

6. Controverting the allegations of the Management and reasserting the pleadings contained in the statement of claim, the workman filed the replication.

7. In order to substantiate his claim, Kuldip Kumar, workman appeared as his own witness as WW-1 who has tendered into evidence his affidavit Ex. W-1. The Management in order to revolt the evidence brought on record by the workman, examined Paramjit Singh Dy. Manager as MW-1 who has tendered into evidence his affidavit Ex. M-1.

8. Having Saving heard the representatives of the parties, having gone through the evidence on record and after considering the matter deeply in my mind, there is no merit in the reference petition which deserves to be declined.

9. As mentioned above the case set up by the Petitioner is that he had worked as Godown Chowkidar in Bhatinda Branch of the bank from 9-1-84 to 8-3-84 and at Sangrur branch of the bank from 14-3-86 to 5-7-86. He has also so stated in his affidavit in Ex. W-1. On the other hand the case set up by theManagement is that the workman had not completed 240 days and he was appointed on purely temporary basis. The workman while appearing as WW-1 has categorically admitted in his cross-examination that initially he was employed from 9-1-84 to 8-3-84 as Godown Chowkidar. He was disengaged after 8-3-84 from Bhatinda. He has also admitted that subsequent employment was from 14-3-86 to 5-7-86 for a specific period. Thus it would be seen that, bare perusal of evidence on record would go to show that petitioner/workman had not at all completed 240 days of his continuous service during the period of 12 calender months preceding the date of termination as riquired under Section 25-B of the act.

10. Now, the short and significant questions, though important, arise for determination in this case is whether the workman is entitled to any relief under Chapter VA of the Act, which deals with the retrenchment of any employee. Section 25-F of the Act postulates that no workman employed in any industry, who has been in contiuous service for not less than one year under an employer, shall be retrenched by that employer unless (a) the workman has been given one month's notice in writing, indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice, (b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation, which shall be equivalent to fifteen days average pay for every completed year of continuous service or any part there of in excess of six months; and (c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government by notification in the Official Gazette.

11. Section 25-H of the Act provides that where any workmen are retrenched, and the employer proposes to take into his employment any person, he shall, in such manner as may be prescribed, give a opportunity (to the retrenched workmen, who are citizen of India to offer themselves for re employment, and such retrenched workman) who offer themselves for re-employment shall have preference over other persons.

12. The retrenchment has been defined under section 2(00) of the Act to mean the termination by the employer of the service of a workmen for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action but does not include (bb) termination of the service of the workma as a result of the non-renewal of the contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry or of such contract being terminated under a stipulation in that behalf contained therein.

13. Thus it is clear that a combined reading of the above mentioned provisions would reveal that a retrenched person is that who had put in 240 days of continuous service. As indicated earlier it stands proved on the record that the workman had not put in 240 days of his continuous service and his appointment was on purely temporary basis for a specified period as admited by WW-1. In this view of the matter to my mind he can not possibly be termed as retrenchee so as to attract the benefits provided under Sections 25-S, 25-G, and 25-H of the Act. It is now well settled that if a workman has not put in 240 days of service, he has no industrial rights, and can not, therefore avail of machinery for the settlement of his dispute under the Act. The policy of the Act, draws a distinction between those, employees, with service of 240 days and more, and other with less. It was not necessary for the Management, to comply with the provisions of the Act, before termination the services of the petitioner as claimed by him. Particularly when, neither he had completed 240 days nor his case falls under the definition of retrenchment as contemplated under section 2(00) of the Act. Reliance in this regard can be placed to a judgements in cases of Gujarat Steel Tubes Ltd. Etc. Vs. Gujarat Steel Mazdoor Sabha and Other AIR 1980 S.C. page 1896, Karnal Central Coop. Bank Limited, Karnal Vs. The Presiding Officer, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Rohtak and Others 1994 (1) P.L.R. page 310, State Bank of India Vs. M. V. Raval 1981 (1) S.L.R. page 831. The Manager, State Bank of India Indore, Kanpur and Others 1990 (60) F.L.R. page 672. Thus, it would be seen that, if the aforesaid provisions of the Act are put together and are analysed in relation to the law laid down in the aforesaid judgments, then to my mind, conclusion is unescapable that workman whohad not completed 240 days of his service had no industrial rights, which can be enforced by the Tribunal under the Act. Even the Appropriate Government has not formed a correct opinion in sending the reference of the employee who had not completed 240 days, in view of the D.B. Judgement of Hon'ble Punjab and Haryana High Court in Mehar Singh Vs State of Haryana and Others 1994 (ii) L.L.J. page 250. The aforesaid judgements are the complete answer to the problem in hand.

In the light of the aforesaid reasons, it is held that workman is not entitled for any relief under the Act. Consequently, there is no merit in the reference petition, which is hereby declined. The appropriate Government be informed accordingly.

CHANDIGARH,

Dated : 8-11-1994.

M. S. SULLAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1994

का.आ. 132—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे, अम्बाला कैंट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-12-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/66/92-आईआरबी-I]

पी. जे. माइकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd December, 1994

S.O. 132.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Ambala Cantt. and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd December, 1994.

[No. L-41012/66/92-IR(B.I)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 13/1993

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-41012/66/92 आई.आर. (डी.यू.) 18-9-93

रमेश कुमार अरोड़ा पुत्र श्री घनश्याम दास अरोड़ा द्वारा श्री ऋषभ चन्द जैन, 42, पटेल कालोनी, "सी" स्कीम, जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1 मंडल कार्मिक अधिकारी (उत्तर रेलवे) अम्बाला कैन्ट (हरियाणा)

2. रेल पथ निरीक्षक (बड़ी रेल लाईन) श्रीगंगानगर, राज. वर्तमान कार्यालय अबोहर, पंजाब ।

—अप्रार्थीगण

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री के.एल.व्यास, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से श्री आर. सी. जैन

अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं (एकपक्षीय)

दिनांक अवार्ड : 5-9-94

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न विवाद अधिनिर्णय हेतु इस न्यायाधिकरण में निर्देशित किया गया है ।

'Whether the action of the D.P.O. Northern Railway Ambala City and P.W.I. Broad Gauge, Sriganganagar in terminating the services of Shri Ramesh Kumar firstly on 10-6-85 and then on 5-8-86 is legal and justified ? If not, what relief the workman concerned is entitled ?'

2. श्रमिक की ओर से प्रस्तुत क्लेम के यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी की नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में 390/—रुपये प्रति माह की दर से 4-3-83 को गैंगमैन के पद पर श्रीगंगानगर में गैंग नं. 201 में की गई थी । इसके पश्चात् दिनांक 28-2-85 को नियमित चिकित्सीय परीक्षण के पश्चात् श्रमिक को 1-3-85 से नियमित वेतन श्रृंखला में 200/—रुपये मूल वेतन पर नियुक्त किया गया तथा स्थाई कर्मचारी के रूप में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। दिनांक 3-6-85 को प्रार्थी अपने निजी कार्य में 6 दिन का अवकाश लेकर अपने गांव गया था वापस आया तब रेल पथ निरीक्षक ने ड्यूटी पर नहीं लिया व यह बताया कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं । इस संबंध में वह मंडल कार्मिक अधिकारी फिरोजपुर से मिला व उसे पुनः 23-4-86 से अस्थाई रूप से पानी पिलाने के कार्य हेतु नियुक्ति दी गई व यह पता अस्थाई होने से श्रमिक की सेवाएं पुनः 4-8-86 से समाप्त कर दी गई। श्रमिक ने इस संबंध में नियोजक को मौखिक निवेदन किये व लिखित में भी 28-6-91 को नोटिस भेजे । समझौता वार्ता विवाद के संबंध में सम्पन्न की गई उसमें कोई भी परिणाम नहीं होने से केन्द्र सरकार द्वारा यह विवाद निर्देशित किया गया है । श्रमिक का कथन है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उसकी सेवा मुक्ति से पूर्वधारा 25—एफ के प्रावधान की पालना नहीं की गई इस कारण सेवा मुक्ति का आदेश अवैध व शून्य है । प्रार्थी का यह कथन है कि उसकी सेवा मुक्ति के पश्चात् समकक्ष पदों पर अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां भी नियोजक द्वारा की गई है ।

3. नियोजक की नोटिस विधिवत तामहीन हो गया था व उनकी ओर से प्रतिनिधि श्री बी.एम. माथुर उपस्थित हुए किन्तु नियोजक की ओर से कोई भी जवाब प्रस्तुत नही किया गया। दिनांक 30-7-94 को नियोजक के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई गई।

4. श्रमिक की ओर से उसके अभिकथन के समर्थन में उसका स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन सभी तथ्यों की पुष्टि की गई है जो क्लेम में वर्णित किये गये हैं । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रमिक की नियुक्ति प्रथम बार 4-3-83 को की गई थी, उसे नियमित वेतन श्रृंखला 1-3-85 में दी गई थी व दिनांक 10-6-85 में उसे सेवा मुक्त किया गया था तथा सेवा मुक्ति से पूर्व धारा 25—एफ के तहत न तो नोटिस दिया गया है व न ही एक माह का वेतन व छंटनी का मुआवजा दिया गया। तथ्यों से यह भी प्रमाणित है कि श्रमिक ने सेवा मुक्ति से पूर्व निरन्तर 240 दिन से अधिक कार्य किया था व चूंकि उसके मामले में धारा 25-एफ के प्रावधान की योजना नहीं की गई है इसलिए 10-6-85 को पारित किये गये सेवा मुक्ति को वैधानिक व उचित नही माना जा सकता । श्रमिक को पुन अस्थाई तौर पर दिनांक 23-4-86 को सेवा में लिया गया था व उसके पश्चात् पुनः उसे 4-8-86 से सेवा मुक्त कर दिया गया । चूंकि श्रमिक का प्रथम सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 10-6-85 अवैध व शून्य है इसलिए उस पर सेवाए निरन्तर माने जाने का वैधानिक प्रावधान है व परिणाम-स्वरूप उसे दिनांक 4-8-86 से पुनः सेवा मुक्त करने की जो कार्यवाही नियोजक द्वारा की गई है वह भी अनुचित व अवैधानिक है ।

5. निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि नियोजकगण रेल पथ निरीक्षक, श्रीगंगानगर व मण्डल कार्मिक अधिकारी उत्तर रेलवे, अम्बाला सिटी द्वारा श्रमिक रमेश अरोड़ा के विरुद्ध पारित सेवा मुक्ति का आदेश दिनांक 16-6-85 व व 4-8-86 अनुचित एवं अवैध है अतः उन्हें अपास्त किया जाता है तथा श्रमिक प्रथम सेवा मुक्ति की तिथि 10-6-85 से लगातार सेवा में रहने का व समस्त बकाया वेतन व अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।

6. अवार्ड आज दिनांक 5-9-94 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

के.एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1994

का.आ. 133—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ राजस्थान लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-12-94 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/08/88-आई आर बी I)]
पी.जे. माइकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd December, 1994

S.O. 133.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Rajasthan Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 23rd December, 1994

[No. L-12012/08/88-IR(B-I)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 35/1988

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-12012/08/88/I-T-9ए दिनांक 23-5-88

अमर सिंह पुत्र श्री छोटूसिंह ग्राम हाथ की पोस्ट मालपुरा द्वारा बी.एम. बागड़ा, जयपुर ।
—प्रार्थी

बनाम

प्रबन्धक, बैंक ऑफ राजस्थान लि. पृथ्वीराज मार्ग जयपुर । —अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के.एल.व्यास, आर.एच.जे.एम.

प्रार्थी की ओर से : श्री बी.एम. बागड़ा
अप्रार्थी की ओर से : श्री आलोक फतहपुरिया
दिनांक अवार्ड : 15-7-1994

अवार्ड

श्रमिक अमरसिंह व नियोजक बैंक ऑफ राजस्थान लि. जयपुर के मध्य उत्पन्न निम्न औद्योगिक विवाद को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनिर्णय हेतु इस न्यायाधिकरण में प्रेषित किया गया है :

"क्या राजस्थान बैंक लि. जयपुर के प्रबन्धतंत्र की श्री अमर सिंह (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को 20-1-79 के पश्चात् रोजगार न देने तथा सेवाओं को समाप्त करने की कार्यवाही उचित, न्यायोचित व वैध है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

2. इसी क्रम पर यह उल्लेख करना व स्पष्ट करना जरूरी है कि मूल निर्देश जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजा गया था उसमें श्रमिक को सेवा मुक्ति की तिथि 20-1-74 अंकित थी किन्तु उसके पश्चात् निर्देश में संशोधन दिनांक 5-9-90 को प्राप्त हुआ था व उसके अनुसार सेवा मुक्ति की तिथि 20-1-79 विवाद में उल्लिखित की गई है ।

3. श्रमिक की ओर से जो क्लेम प्रस्तुत किया गया है उसका सार यह है कि उसकी नियुक्ति राजस्थान बैंक की ब्रिजलाल नगर शाखा में 26-7-78 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर की गई थी व उसने 20-1-89 तक निरन्तर व नियोजक के संतोषजनक रूप से इस पद पर कार्य किया। 20-1-79 के पश्चात् श्रमिक की सेवाएं समाप्त कर दी गई जबकि बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त थे व श्रमिक की नियुक्ति भी स्थाई पद रिक्त होने के कारण की गई थी । श्रमिक का यह भी कथन है कि उसे सेवा में हटाया गया तब बैंक में उससे कनिष्ठ कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे व इस प्रकार नियोजक द्वारा धारा 25-जी औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान की अवहेलना की गई। श्रमिक की सेवा मुक्ति के पश्चात् अन्य व्यक्तियों को भी इस पद पर नियुक्त किया गया व श्रमिक को पुनः नियुक्ति का अवसर नहीं दिया गया व इस कारण धारा 25-एच के प्रावधान की अवहेलना नियोजक द्वारा की गई है । अनुतोष यह मांगा गया है कि श्रमिक को 20-1-89 से सेवा में निरन्तर मानते हुए बकाया वेतन दिलाया जावे ।

4. नियोजक की ओर से क्लेम के जवाब में यह अभिकथित किया गया है कि श्रमिक ने बैंक को उक्त शाखा में 26-7-78 से 20-1-79 तक कार्य किया था किन्तु उसे नियुक्ति अस्थाई तौर पर अवकाश की एवज में दी गई थी तथा नियुक्ति निश्चित अवधि के लिए होने के कारण उस अवधि के समाप्त होने पर श्रमिक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई । नियोजक का कथन है कि उनकी यह कार्यवाही श्रमिक की सेवा मुक्ति अथवा छंटनी की परिभाषा में नहीं आती है । इसलिए कोई भी औद्योगिक विवाद इस मामले में उत्पन्न नहीं होता । एक विधिक आपति यह ली गई है कि धारा 2-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मात्र सेवा मुक्ति व छंटनी के विवाद को ही संबंधित श्रमिक द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है व चूंकि इस विवाद को किसी यूनियन द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है इसलिए विवाद सुनवाई योग्य नहीं है । श्रमिक की सेवा मुक्ति कथित रूप में 20-1-79 की है व निर्देश न्यायाधिकरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा 12-7-88 को प्रेषित किया गया है व इस देरी के कारण भी निर्देश सुनवाई योग्य नहीं होना नियोजक की ओर से अभिकथित किया गया है । नियोजक के अनुसार श्रमिक की नियुक्ति किसी भी स्थाई रिक्त पद के विरुद्ध नहीं की गई थी इसलिए भी उसे कोई वाद उठाने का अधिकार नहीं है । नियोजक की यह भी प्रतिरक्षा है कि वर्णित तथ्यों के आधार पर धारा 25-एफ, जी व एच के

प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते । तथ्यों पर इस बात को भी अस्वीकार किया गया है कि श्रमिक को कथित रूप से हटाया गया व उस समय श्रमिक से कनिष्ठ कर्मचारी कार्यरत थे अथवा उसके पश्चात् अन्य कर्मचारियों को सेवा में रखा गया था ।

5. मौखिक साक्ष्य के रूप में श्रमिक की ओर से उसका स्वयं का शपथ पत्र तथा नियोजक की ओर से गवाह श्री कपिल काटजू का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । श्रमिक की ओर से प्रदर्श डब्ल्यू –1 से डब्ल्यू–6 व नियोजक की ओर से प्रदर्श एम–ए से एम–4 प्रलेख प्रस्तुत किये गये हैं । बहस दोनों पक्षों की सुनी गई ।

6. दोनों पक्षों की ओर से जो अभिकथन प्रस्तुत किए गये हैं उनको देखते हुए सर्वप्रथम व सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु तथ्यों के आधार पर यह विनिश्चय करने का है कि क्या-श्रमिक की नियुक्ति नियोजक द्वारा किसी कर्मकारी के अवकाश के एवज में व निश्चित अवधि के लिए की गई थी। अथवा यह नियुक्ति स्थाई रिक्त पद के खिलाफ की गई थी । श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि की बहस में किस ईमारत को स्वीकार किया है कि श्रमिक के चूंकि 240 दिन से कम अवधि तक बैंक में काम किया है इसलिए धारा 25–एफ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते । धारा 25–जी व 25 एच अधिनियम के प्रावधान लागू होते है या नहीं इस बात का विनिश्चय उक्त तथ्य के निस्तारण के अनुसार किया जाना आवश्यक व अपेक्षित है ।

7. श्रमिक ने अपने क्लेम में व शपथ पत्र में यह अभिकथित किया है कि उसकी नियुक्ति बैंक में 26-7-78 को स्थाई रिक्त पद होने के कारण की गई थी व 19-1-79 तक उसने कार्य किया था। 26-7-78 से 19-1-79 तक बैंक में कार्य करने के तथ्य को नियोजक ने विवादग्रस्त किसी रूप में नहीं बताया है । नियोजक की प्रतिरक्षा इस संबंध में यह है कि श्रमिक की नियुक्ति एक कर्मचारी के अवकाश पर जाने के कारण निश्चित अवधि के लिए की गई थी व इसी संदर्भ में श्रमिक व नियोजक की प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करना अपेक्षित है। नियोजक की ओर से प्रदर्श एम-1 से एम-4 श्रमिक के नियुक्ति आदेश की फ़ोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई है। प्रदर्श एम-1 से एम-4 पर श्रमिक के हस्ताक्षर हैं व इसके ऊपर यह छपी हुई टिप्पणी है कि श्रमिक ने नियुक्ति को स्वीकार किया है जिसमें श्रमिक ने यह माना है कि प्रदर्श एम-1 से एम-4 पर "ए" टू "बी" उसके हस्ताक्षर हैं। श्रमिक के अनुसार वह कक्षा पांच तक पढ़ा हुआ है व इसके अलावा और उसने कहीं भी यह नहीं कहा है कि प्रदर्श एम-1 से एम-4 पर हस्ताक्षर उसने बिना समझे किये थे या उससे जबरदस्ती करवाये गये थे। गवाह ने यह भी माना है कि जब उसे नौकरी पर रखा गया तब उसके अलावा बैंक में अन्य कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं था। इसके आगे उसने इस तथ्य को मना किया है कि उसकी नियुक्ति राम स्वरूप के अवकाश पर जाने के कारण की गई थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जिस अवधि में वह बैंक में कार्यरत रहा उस बीच अन्य किसी व्यक्ति को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नहीं रखा गया था। इसके अतिरिक्त श्रमिक ने इस संबंध में जानकारी नहीं होना बताया है कि जिस समय उसे नौकरी पर रखा गया तब खाली पद हेतु कोई विज्ञप्ति नियोजक द्वारा जारी की गई हो। यह माना है कि उसकी नियुक्ति से पूर्व कोई भी चयन प्रक्रिया बैंक द्वारा नही अपनाई गई । श्रमिक को इस मौखिक साक्ष्य के विरुद्ध नियोजक के गवाह श्री काटजू ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि श्रमिक की नियुक्ति रामस्वरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अवकाश पर जाने के कारण निश्चित अवधि के लिए की गई थी। प्रदर्श एम–1 से एम-4 नियुक्ति पत्र को गवाह ने साबित किया है। इस गवाह का यह भी कथन है कि 20-1-89 से पश्चात श्रमिक को इसलिए काम पर नहीं रखा गया क्योंकि अवकाश के एवज में उसे रखा गया था व उसके अलावा कोई भी पद रिक्त नहीं था । स्थाई पद के विरुद्ध नियुक्ति के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन देने व चयन की प्रक्रिया की पालना करना नियोजक के गवाह ने बताया है व उनका कथन है कि अमर सिंह की नियुक्ति के समय ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी क्योंकि कोई भी स्थाई पद रिक्त नही था । श्रमिक के कथन को पुष्टि करते हुए इस गवाह ने यह भी बताया है कि अमर सिंह को सेवा से हटाया गया उस समय बैंक की ब्रजलाल नगर शाखा में अन्य कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत नहीं था। एक कथन गवाह का यह भी है कि स्थाई पदों पर नियुक्ति का अधिकार शाखा प्रबन्धक को नहीं है व सिर्फ सहायक महाप्रबन्धक ही इस प्रकार की नियुक्तियों को करने हेतु सक्षम है । स्थाई पद के विरुद्ध नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया गवाह ने बताई है व नियुक्ति के संबंध में जिस सक्षम अधिकारी का उल्लेख बयान में किया गया है उस बाबत गवाह से श्रमिक की ओर से कोई भी जिरह नहीं की गई है व इस कारण इन तथ्यों को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है ।

8. श्रमिक की ओर से प्रदर्श डब्ल्यू–1 व डब्ल्यू–2 पत्रों की फोटो प्रतियां साक्ष्य में पेश की गई हैं जिनके लिए नियोजक के गवाह ने यह कहा है कि इस प्रकार के पत्र प्रबन्धक को कभी भी प्राप्त नहीं हुए । दोनों पत्र श्रमिक को पुनः नियोजन देने के संबंध में हैं व उन पर विस्तृत विवचन आवश्यकतानुसार धारा 25–एच अधिनियम के प्रावधान पर विचार करते समय किया जायेगा । प्रदर्श डब्ल्यू–5 वह पत्र है जिसके जरिये केन्द्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष श्रमिक द्वारा अपना विवाद उठाया गया था व प्रदर्श डब्ल्यू–6 समझौता वार्ता असफल होने का प्रतिवेदन है ।

9. मौखिक साक्ष्य के अलावा श्रमिक की नियुक्ति की प्रकृति के संबंध में प्रदर्श एम–1 से एम–4 प्रलेख नियोजक द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। प्रथम नियुक्ति पत्र 26-7-78 को, दूसरा 28-9-78 को, तीसरा 1–11–78 को व चौथा 1–12–78 का है । चारों ही नियुक्ति पत्रों में यह उल्लेख है कि श्रमिक की नियुक्ति ए ओ जी में एक निश्चित तिथि तक की जाती है । नियुक्ति पत्र के अनुसार श्रमिक की नियुक्ति निश्चित रूप से मासिक वेतन पर की गई थी किन्तु सिर्फ उसी तथ्य से यह धारणा नही ली जा सकती कि श्रमिक की नियुक्ति स्थाई पद के विरुद्ध की गई थी । पूर्व में जो उल्लेख किया गया है

उसके अनुसार चारों ही नियुक्ति पत्र पर श्रमिक द्वारा नियुक्ति पत्र की शर्तों को स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर किये गये हैं । किसी भी नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख नहीं है कि श्रमिक की नियुक्ति किसी स्थाई पद के विरुद्ध की गई है । 26-7-78 के नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि शाखा प्रबन्धक द्वारा बैंक के मुख्यालय को भेजी गई है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि श्रमिक की नियुक्ति रामस्वरूप कर्मचारी के अवकाश पर जाने के कारण की गई है । बाद के तीनों नियुक्ति पत्र एम–2 से एम–4 प्रथम नियुक्ति पत्र की निरन्तरता में जारी किये गये हैं व उनके पृष्ठांकन में मात्र यह लिखा हुआ है कि यह नियुक्ति पत्र पूर्व के नियुक्ति पत्र की निरन्तरता में है। उक्त पृष्ठांकन से भी यह प्रकट होता है कि श्रमिक की नियुक्ति राम स्वरूप के अवकाश पर जाने के कारण की गई थी । श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि का कथन है कि प्रदर्श एम–1 से एम–4 मूल पत्र जो उन्हें दिये गये हैं उनमें पृष्ठांकन के कॉलम रिक्त हैं व इस कारण यह माना जाना चाहिये कि पृष्ठांकन में आवश्यक पूर्तियां नियोजक द्वारा बाद में फर्जी की गई हैं। नियोजक के प्रतिनिधि का इस संबंध में कथन है कि मूल पत्र पर पृष्ठांकन सामान्य कार्यालय व्यवहार के अनुसार नहीं किया जाता है व जो प्रतिलिपि जिस अधिकारी को संबोधित की जाती है उसी में आवश्यकतानुसार पृष्ठांकन दर्ज किया जाता है । नियोजक के गवाह से श्रमिक की ओर से इस संबंध में कोई भी जिरह नहीं की गई है । नियोजक एक सार्वजनिक उपक्रम है तथा उनके वहां सामान्य प्रक्रिया में रिकार्ड तैयार किया जाता है व रखा जाता है व इसलिए किसी भी विशिष्ट साक्ष्य व परिस्थिति के अभाव में यह मानने का आधार नहीं है कि प्रदर्श एम–1 से एम–4 पर पृष्ठांकन बाद में फर्जी किये गये हैं। इसके अलावा कोई भी मौखिक या प्रालेखीय साक्ष्य श्रमिक की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुत नहीं हुई है । उपलब्ध मौखिक व प्रालेखीय साक्ष्य के आधार पर यह विनिश्चय किया जाना पूर्णतः न्यायोचित है कि श्रमिक को नियुक्ति रामस्वरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अवकाश पर जाने के कारण एक निर्धारित अवधि के लिए की गई थी व उस निर्धारित अवधि के पश्चात् ही श्रमिक को सेवा में नहीं रखा गया । ऐसी स्थिति में श्रमिक को नौकरी से हटाने या उसकी छंटनी करने की परिभाषा में नियोजक की कार्यवाही नहीं आती । इस परिस्थिति में धारा 25 एफ, जी व एच के प्रावधान भी लागू नहीं माने जा सकते । श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एक निर्णय एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 3548/92 शिवप्रसाद शर्मा बनाम यू.को. बैंक निर्णय दिनांक 25-3-94 को फ़ोटो प्रति प्रस्तुत की है । उसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 25–जी व एच के प्रावधान धारा 25–एफ के प्रावधान से पूर्णतः स्वतंत्र हैं व जहां किसी भी श्रमिक की छंटनी की जाती है तो उस स्थिति में नियोजक द्वारा धारा 25–जी व एच के प्रावधान की पालना करना आज्ञापक है यदि उसके द्वारा 240 दिन निरन्तर काम नहीं भी किया गया है । इस विधिक सिद्धान्त पर नियोजक की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है किन्तु निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त उसी स्थिति में लागू होते हैं जब श्रमिक को सेवा में नहीं रखने का मामला छंटनी या सेवा मुक्ति की परिभाषा में आता हो ।

10. नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने एक बहस यह की है कि छंटनी व सेवा मुक्ति के अलावा कोई भी विवाद श्रमिक द्वारा व्यक्तिगत रूप से धारा 2-ए अधिनियम के तहत नहीं उठाया जा सकता इसलिए भी यह विवाद सुनवाई योग्य नहीं है । तथ्यों पर जो यह विनिश्चय किया गया है कि श्रमिक को सेवा में नहीं रखने का मामला छंटनी अथवा सेवा मुक्ति की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए इस बिन्दु पर भी अन्य कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार नियोजक की ओर से यह तर्क भी दिया गया है कि जो विवाद न्यायाधिकरण में प्रेषित किया गया है उसमें धारा 25-एच के प्रावधान की अवहेलना का कोई उल्लेख नहीं है व मात्र सेवा मुक्ति का विवाद ही प्रेषित किया गया है इसलिए विवाद की शर्तों के बाहर जाकर न्यायाधिकरण यह विनिश्चय करने के लिए सक्षम नहीं है कि नियोजक द्वारा धारा 25-एच के प्रावधान की पालना की गई है या नहीं यदि नहीं की गई तो उसका क्या परिणाम है । इस संबंध में उनके द्वारा यह विधि दृष्टान्त भी प्रस्तुत किया गया है जो जसविन्दर सिंह बनाम पंजीयक, सहकारी समितियां, एल. एल. जे. 1992 (पंजाब एवं हरियाणा) पेज 177 है । इसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि निर्देशित विवाद में धारा 25–एच के प्रावधान की अवहेलना के संबंध में उल्लेख नहीं हो तो न्यायाधिकरण इस संबंध में कोई भी विनिश्चय करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम नहीं है व इस विवाद को मूल विवाद के पूरक के रूप में भी तय नहीं किया जा सकता है । इसी प्रकार का अन्य निर्णय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय का करनाल जिला सहकारी बैंक बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण रोहतक एल. एल. आर. 1994 पेज 248 संदर्भित किया गया है । नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने यह बताने के लिए कि जिस श्रमिक को अवकाश के एवज में या पूर्ण रूप से अस्थाई तौर पर निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है उसे निश्चित अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखने से नियोजक की कार्यवाही सेवा मुक्ति या छंटनी की परिभाषा में नहीं आती व उस स्थिति में धारा 25-एफ, जी व एच के प्रावधान की पालना करना आज्ञापक नहीं है, निम्न विधि दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं :

1. विजया बैंक कर्मचारी यूनियन बनाम केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण बेंगलौर, एफ. जे. आर. 1988 पेज 93
2. सतीशचन्द्र पाण्डे बनाम बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय 1989 एल. आई. सी. (इलाहाबाद) 1051
3. इंडियन एयर लाईन्स बनाम सैबेस्टीयन, एफ. एल. आर. 1991 पेज 755 (केरल)
4. कृष्णामूर्ति प्रसाद बनाम इलाहाबाद बैंक, एफ. जे. आर. 1992 (इलाहाबाद) 197

5. पटेल रणछोर भाई बनाम गुजरात आयुर्वेदिक विश्व विद्यालय एल. एल. जे. 1988 (गुजरात) पेज 447

6. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल किशोर शुक्ला, एफ. जे. आर. 1991 (एस. सी.) 441

7. एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 6378/93 जयनारायण बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय निर्णय दिनांक 6-1-94 (राजस्थान उच्च न्यायालय)

11. उक्त सभी विधि दृष्टान्तों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं उनका सार यह है कि निर्धारित अवधि के लिए व पूर्ण रूप से अस्थाई कर्मचारी को सेवा में निरन्तर नहीं रखने से छंटनी अथवा सेवा मुक्ति की परिभाषा में नियोजक को कार्यवाही नहीं आती। तथ्यों पर जो विनिश्चय इस प्रकारण पू पूर्व किया गया है उसको देखते हुए विधि दृष्टान्तों पर विस्तृत विवेचन का आवश्यकता नहीं है ।

12. नियोजक की ओर से जो विधिक आपत्ति यह ली गई है कि निर्देश न्यायाधिकरण में देरी से प्राप्त हुआ है इसलिए यह न्यायाधिकरण अभिनिर्णय पारित करने के लिए सक्षम नहीं है उसे अस्वीकार किया जाता है क्योंकि इस प्रकार का कोई भी विधिक प्रावधान या विधि दृष्टान्त नियोजक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

13. मामले के उपलब्ध तथ्यों व विधिक स्थिति के विवेचन के परिणामस्वरूप प्रेषित विवाद में अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि नियोजक बैंक आफ राजस्थान द्वारा श्रमिक अमरसिंह को 20-1-79 के पश्चात सेवा में नहीं रखने की कार्यवाही न्यायोचित व वैधानिक है व इस कारण श्रमिक कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

14. अवार्ड की प्रति केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजी जाए ।

के. एल. व्यास, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1994

का. आ. 134.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार केराला मिनरल्स एन्ड मेटल्स लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, कोल्लाम के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-12-94 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल—29012/57/91—आई आर (विविध)]

के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th December, 1994

S.O. 134.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Industrial Tribunal, Kollam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kerala Minerals and Metals Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 26-12-94.

[No. L-29012/57/91-IR (Misc.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL,

KOLLAM

(Dated, this the 1st day of December, 1994)

PRESENT :

Sri C. N. Sasidharan, Industrial Tribunal

IN

Industrial Dispute No. 6/92

BETWEEN

The Managing Director, Kerala Minerals and Metals Ltd., Chavara P.O., Kollam District.

(By M/s. Menon and Menon, Advocates, Cochin)

AND

Sri D. Cletus, Kangenamcode, Vadakkumkara Veedu, Vallanchira, Panaveer Post, Nedumangadu.

(By Sri R Lekshmana Iyer, Advocate, Trivandrum.)

AWARD

This industrial dispute has been referred for adjudication by the Government of India as per Order No. L-29012/57/91-IR(Misc.) dated 29-1-1992.

The issue referred for adjudication is the following :

"Whether the action on the part of the management of Kerala Minerals and Metals Ltd., Chavara, in denying employment to Sri D. Cletus as an Asstt. Cook beyond April, 1986 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. Sri D. Cletus the workman in this case has filed a detailed claim statement and his contentions are briefly as under : Sri Cletus is a cook having long professional experience. The management offered him appointment as an Asstt. cook which was accepted by him and by order dated 4-5-1982 he was appointed. That appointment was terminated on the reason that it was a contractual one for a period of 2 years from 1-3-1982. He was being allowed all the privileges and benefits of a regular employee of the company. During the period of appointment he submitted a representation to the Managing Director of the company to absorb him in regular service which was accepted by the management and as per order dated 1-3-1983 absorbed him in the regular service. His service was terminated on the expiry of 2 years. On his representations he was again appointed in the canteen as Asstt. cook in October 1984. While he was continuously employed his service was terminated in April 1986. This according to him is illegal, irregular and unsustainable. The procedure laid down in the Industrial Disputes Act, 1947 (the Act' for short) was not complied with. It is a case of denial of employment. Before Asstt. Labour Commissioner the management had stated that the workman man handled another casual worker Sri Vijayan and considering the grave indiscipline and unlawful act he was asked not to come for work in the canteen. Such statement is absolutely false. No such incident had occurred. The workman was not given any opportunity to meet such allegations and no enquiry was also conducted. The management was duty bound to conduct an enquiry before denying employment. The prayer is for reinstatement in service with all benefits.

3. The contentions of management as stated in counter statement are briefly as under: Sri Cletus was appointed as an Asstt. Cook on contract basis for a period of 2 yers from 1-3-1982 on a consolidated salary of Rs. 550 PM on the expiry of the said period he ceased to be an employee and left the service. After 3 months the management engaged him as a casual employee in the canteen of pigment unit. He was never taken as a regular employee of the management. He was purely a casual employee. His casual employment was stopped in April 1986 for manhandling another worker Sri Vijayan. Considering the grave indiscipline and rash and unlawful act committed by the workman and since he was only a casual worker he was asked not to come for work. The management was fully justified in doing this. He has no right or locus standi to raise an industrial dispute. This dispute is not an industrial dispute coming within the Act and this Tribunal has no jurisdiction to adjudicate the issue. Sri Cletus was engaged on a consolidated monthly salary and he was not paid other benefits allowed to regular employees of the management. The management has not issued an order on 1-3-1983 absorbing him in service. Since he was a casual employee, the management was not liable to conduct an enquiry or pay compensation or notice pay or adopt a procedure as alleged by Sri Cletus. It is unsafe and undesirable to allow a person like the workman to work in the canteen in view of his rash and righteous behaviour. The management has lost confidence in him. The management has not acted illegally. Sri Cletus is not entitled to any other benefit. The casual employment will not give him any right to claim for employment under the management. Regular employment in the canteen on a regular basis can be made only through Employment Exchange, other than the preferential categories of land evictees and land acquired. According to the management Sri Cletus is not entitled to any relief.

4. The workman examined himself as WW1. Two witnesses have been examined on the side of the management as MW1 and MW2. Exts M1 to M7 have also been marked on the side of the management.

5. The claim of Sri Cletus is for reinstatement in service contending that while he was working as a permanent employee from October 1984 onwards his services wre terminated illegally. But according to the management the workman was engaged only as a casual employee from October 1984 and his engagement was stopped with effect from 22-4-1986 for committing grave misconducts. So the question to be decided is whether he was working as a casual employee from 1984 onwards. The workman as WW1 has deposed that his contract period was closed from 29-2-1984 when the period of contract was over as per Ext. M2 that thereafter he was not given any appointment order appointing him in the canteen of pigment unit that he does not know whether he was engaged casually or permanently from October 1984 and that he was not given any appointment order. According to him while working in the pigment unit he was given Rs. 250 and after 6 months he was paid Rs. 350. It is specific to note that in the claim statement filed here he has not stated that he was granted leave. Even according to him there is no material evidence to support his claim that he was permanently employed by the management. He has admitted that the management is a Government of Kerala owned company and there is scale of pay with annual increment to all permanent employees. But he was not having any scale of pay but he was admittedly paid consolidated pay. It is also admitted that he was not given any order making him permanent with effect from 1-3-1983 as claimed by him.

6. MW2 is the manager, personnel department of the management company who has deposed that the contract period of workman as Asstt. Cook was stopped as per Ext. M-2 order on the expiry of contract period and thereafter he was engaged in the pigment unit canteen as casual employee that no appointment order was given to him that he was engaged orally that he was given consolidated pay of Rs. 250 that there was no scale of pay or annual increment to him that all the permanent workers in the company are having scale of pay with annual increment that the service conditions including scale of pay, increment etc. of all permanent employees are decided as per long term settlement and such settlement was not applicable to the workman and particularly to casual employees and that there are attendance register and wages register for permanent employees. It is also stated by MW2 that in those registers the name of the workman is not included as he was only a casual employee. This witness has proved Ext. M3-series. Attendance registers, for the period from 1984 December to January 1985, Ext. M4 acquittance roll for the period from 19th January, 1986 for permanent employees and Ext. M5 Bonus payment register for the period 1985-86. It is relevant to note that in Ext. M5 to M5 registers the name of Sri Cletus is not included. MW2 has stated the procedure for appointment in the management company. According to him the management company being a Government company used to issue appointment order to all selected as permanent and that those who are posted as permanent are selected as probationer after written test and interview. He has also stated that no appointment order is given to those who are engaged casually. Admittedly the workman has not undergone any written test or interview. It is also not proved that he has submitted any application for appointment. According to MW2 the workman was not eligible to get leave or leave with wages during his tenure as casual employee. MW2 has categorically denied that the management has issued order on 1-3-1983 absorbing the workman as a permanent employee.

7. The evidence of WW1 and MM2 stated above clearly establish that Sri Cletus was only a casual employee from October 1984 onwards. The very fact that he was not given appointment order, he has not undergone any test or interview, he was not engaged pursuant to any advertisement regarding selection to the post of Asstt. Cook, he was not having any scale of pay with annual increment and he was getting only consolidated pay, clearly negative his claim that he was a permanent employee under the management. These aspects considered along with the evidence of MW2 show that the workman is pleading false case before this Tribunal that he was a permanent employee. On the other hand there are no reasons to disbelieve the evidence of MW2 supported by documentary evidence particularly Exts. M3 to M5 fully support the case of management. In this state of affairs I hold that Sri Cletus was only a casual employee under the management.

8. The workman has a contention that management has passed an order on 1-3-1983 absorbing him in the service of management. There is no supporting evidence except the interested testimony of the workman to support this contention. Admittedly his contract engagement was terminated as per Ext M2 order dated 29-2-1984. If as claimed by him he was made permanent as per order dated 1-3-1983 how can his engagement is terminated by Ext. M2 order dated 29-2-1984. Ext. M2 order make it clear that the allegation of the workman about this order dated 1-3-1983 and his absorbing in service are false. He has admitted that he was not given any appointment order after Ext. M1 order. Therefore the contention of the workman that the management had issued an order dated 1-3-1983 absorbing him in the service of management is absolutely incorrect.

9. The workman bases his claim on coupon issue register. According to him his name was written in that register which contains the names of only permanent employees and hence he is to be treated as permanent employee. At the instance of the workman the management has produced the coupon issue registers in respect of the period from June 1984 to January 1985 and July 1985 to February 1986. As I have held above the workman was working only as a casual employee and not a regular workman. So the inclusion of his name in the coupon issue register relating to the period after 1983 will not give him the status of a permanent employee considering the other circumstances and evidence stated above. MW-2 has stated that the coupon issue register contains only the names of employees who are allowed to take food from canteen. So this register will contain only the details of coupons issued to the employees who are allowed to take food in the canteen. But that does not mean that the employees who are allowed to take food in the canteen are permanent employees in the absence of any other documentary evidence. The workman while working on contract basis was admittedly given a ticket No. 159 and his name and ticket number were mentioned in the coupon issue register. During that period he was allowed to take food in the canteen and his name was written in the said register as stated in the affidavit of the management dated 2-4-1983. The averments in this affidavit are not controverted by producing any documentary evidence. He has no case that he had any right to take food from the canteen after termi-

nation of his contract engagement by Ext. M2 order. So the inclusion of his name in the coupon issue register after that period can only be considered as a mistake committed by the clerk as spoken to by MW2. Sri Cletus has not pointed out any entry in these registers that he was issued coupon during that period. Except writing his name nothing is written in these registers. The evidence of MW2 and WW1 in this regard is material. MW2 has deposed that the workman was appointed for a period of 2 years in the pigment unit of foreign technician hostel and he was given ticket No. 159 that those who are issued coupon are allowed to take food in the canteen of pigment unit and there is coupon issue register for this purposes. The following statement of WW1 in this regard is very much relevant. "Contract agreement Prakaram oru ticket No. thannirunnu. Abhalu No. 152 Nyan canteen-il work cheyyunna samayam yanikku athinte avasyam illa. Canteen-il vannu bhakshanam kazhichhu pokunna bakki jolikkarkanu canteen coupon issue cheythirunnathu." (According to contract agreement one ticket No. has been given that is No. 152. I do not need it while working in the canteen. The coupon is being issued to those workers who come and take their meals from the canteen). The above evidence of WW-1 that while working in the canteen he was not issued coupon and there was no necessity for that clearly negative the case of the workman. In these circumstances the claim based on the writing of his name in the coupon issue register without issuing any coupon falls to the ground.

10. The case of the workman is that his services were terminated without any reason and illegally. According to him he was not given notice or notice pay and the management has not complied the relevant rules while terminating his service. In the claim statement he has not stated any reason for stopping his engagement from 22-4-1986. According to him no domestic enquiry was also conducted. But in the subsequent portion of the claim statement he has stated that during the conciliation proceedings before the labour office the management filed a statement in which it was stated that he was terminated for manhandling another employee Shri Vijayan. According to WW-1 there was no such incident of assaulting. Shri Vijayan was examined here as MW-1. He has stated that on 21-4-1984 by 6.15 while he was about to leave after duty Sri Cletus has beaten him and he fell down unconscious that he was taken to the dispensary in the company that from there he was taken to the Government Hospital. Karunagappally in the ambulance of the company that incident was informed to the security that MW-2 had questioned him about this incident on the next day and that Sri Cletus had not worked there after 22-4-1986 for manhandling MW-1. MW-2 has stated that the employment of the workman was stopped due to the reason that he had beaten another employee that MW-2 came to know of incident on 21-4-1986 that he had informed this to the Managing Director of the company and as per the direction of the Managing Director the engagement of the workman was stopped. MW-2 has deposed that he had questioned Sri Cletus and Sri Vijayan and Sri Cletus had admitted the incident and requested for not taking any further action. This witness has proved Ext. M-6, Treatment register, maintained in the dispensary of pigment unit. As per pages 36 and 37 of Ext. M-6 the injury sustained to Sri Vijayan are recorded. It is also recorded as referred to Government Hospital, Karunagappally. The evidence of MW-1, MW-2 and Ext. M-6 register clearly prove the injury sustained by Sri Vijayan and the reference to the Government Hospital, Karunagappally. There are absolutely no reasons to disbelieve the evidence of these two witnesses and M-6 register. There is no allegation by the workman that there was any kind of enemity towards him by MW-1 and MW-2 or by the management. There is also no explanation as to why such entries are made in Ext. M-6 register falsely without any such incident. It may be recalled that the management is a Kerala Government Company. The evidence of MW-1 and MW-2 and M-6 register clearly proves the manhandling of Sri Vijayan on 21-4-1986. It is also proved that the engagement of the workmen was stopped for assaulting Sri Vijayan. So the case of the workman that there was no such incident and his engagement was stopped without any reason is absolutely false and contrary to evidence on record.

11. The question next to be considered is whether it was necessary to issue charge sheet and conduct a domestic enquiry before stopping the engagement of the workman. I have held above that the workman was only a casual employee and a casual employee has no right in the service of the master as he was not in the service. He was engaged casually and the management has the right to stop the engagement at any time without assigning any reason. It is the absolute right of the management if it is not desirable to continue the engagement as a casual employee. Now regarding the notice pay and compensation as provided in the Industrial Disputes Act (the Act for short) it is now settled that only if the service of an employee is terminated by way of retrenchment notice pay and compensation is necessary. Here his service was stopped on the ground of misconduct which will not amount to retrenchment under the Act. As it is proved that the engagement of the workman was stopped because of manhandling another employee. Hence his engagement will not come within the definition of retrenchment under the provisions of the Act. Therefore the contention that he was not given notice pay and compesation is devoid of merit. Since his engagement was stopped for manhandling a co-employee and the workman was only a casual employee issue of charge sheet and domestic enquiry are not at all necessary for stopping the engagement. The workman has admitted that the management has the right to stop the engagement of an employee who has done such misconduct. From the discussion made above it is clear that the contention of the workman in this regard is without force.

12. No doubt the management has not conducted any enquiry before stopping the engagement of the workman. According to the management the workman was only a casual employee and issuing of chargesheet and domestic enquiry are not at all necessary. But the management has adduced evidence before this Tribunal and proved the misconduct committed by the workman. The misconduct now proved is manhandling of one Sri Vijayan, Sri Vijayan as MW-1 and the personnel manager as MW-2 has proved the incident with the support of Ext. M 6 register. It was also proved that the engagement of the workman was stopped for comitting the misconduct of manhandling Sri Vijayan. So the action of management in stopping the engagement of the workman has only to be held as legal and justified. Since the misconduct is raised by the management in their pleadings and it is proved before this Tribunal, this Tribunal cannot declare the stoppage of engagement as illegal on the ground that there was no charge sheet or domestic enquiry. This view is supported by a decision of the High Court of Kerala reported in 1992 (i) LLR Kerala 669 wherein it was held that in the absence of charge sheet or domestic enquiry dismissal cannot be held as illegal if the management proves the misconduct before the court.

13. It is specific to note that the engagement of the workman was stopped with effect from 22nd April, 1986. He has not raised any dispute till 1991 and even in 1991 he has not raised any direct dispute before the management but only approached the labour department. This dispute has been raised after a period of about 5 years without any explanation what so ever for the long delay. Of course no time limit is fixed for raising the dispute. But since it is not raised within the reasonable time some of the records in this case could not be traced out by the management and produce before this Tribunal. The circumstances involved in this case definitely show that the dispute is highly belated and it is liable to be rejected on that ground also.

14. MW2 has stated in evidence that there is no vacancy in the canteen of pigment unit for the post of Asstt. Cook at present. According to the management, management does not require casual employee. MW2 has categorically deposed that the management has lost confidence in the workman. It is not at all advisable to engage a casual employee who had manhandled a co employee. On these grounds also the prayer of the workman cannot be allowed.

15. From the discussion made above it is clear that Sri Cletus was only a casual employee under the management and his engagement was stopped for misconduct. The action of management is legal and justified.

16. In the result, an award is passed holding that the action of the part of the management of Kerala Minerals and Metals Ltd., Chavara in stopping the employment of Sri D. Cletus beyond April 1986 is legal and justified and hence he is not entitled to any relief in this reference.

C. N. SASIDHARAN, Industrial Tribunal

APPENDIX

Witness examined on the side of the Workman:

WW1—Sri D. Cletus.

Witness examined on the side of the Management:

MW1—Sri. Vijayan Pillai.

Documents marked on the side of the Management:

Ext. M1—Office copy of appointment order as Asst. Cook on contract basis issued to the workman from the management dated 27th February, 1982.

Ext. M2—Office copy of termination order issued to the workman from the management dated 29th February, 1984.

Ext. M3-series (3 nos.)—Attendance registers of management company for the period 1984 December to 1985 January.

Ext. M4—Acquittance roll of the management for the month of January 1986 of the employees.

Ext. M5—Register for payment of bonus for the year 1985-86.

Ext. M6—Treatment register maintained in the dispensary of the pigment unit of management company.

Ext. M6 A—Pages 36 and 37 of Ext. M6.

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1994

का. आ. 135.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार केराला सिरामिक्स लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, कोलम के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-12-94 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-29011/2/91-आई आर (विविध)]
के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th December, 1994

S.O. 135.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the award of the Industrial Tribunal, Kollam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kerala Ceramics Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 26-12-1995.

[No. L-29011/2/91-IR(Misc.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, KOLLAM

(Dated, this the 2nd day of December, 1994)

PRESENT:

Sri C. N. Sasidharan, Industrial Tribunal

IN

Industrial Dispute No. 7/92

BETWEEN

The Managing Director, Kerala Ceramics Ltd., Kundara P.O., District Quilon-691501.

By Sri V. Sugathan and Sri V. Viswarajan, Advocates, Kollam.

AND

1. The Secretary, Kerala Ceramics Employees Association, Kundara P.O., District Quilon-691501.

2. The General Secretary, Kerala Ceramics Workers' Union, Kundara P.O., District Quilon-691501.

By Sri Babu Divakaran, Advocate, Quilon

AWARD

This Industrial Dispute has been referred for adjudication to this Tribunal by the Government of India as per order No. L-29011/2/91-IR(Misc.) dated 24-2-1992.

The issue for adjudication is the following:

"Whether the demand raised by (1) Kerala Ceramics Employees Association and (2) Kerala Ceramics Workers Union claiming canteen allowance in respect of security guards whose names are listed in the Annexure for the period of lay off in the Kaolin Division from 14-6-1987 to 31-10-1987 is fair and justifiable? If so what should be the quantum of canteen allowance paid to them?"

2. The Unions have filed a joint statement and the contentions are briefly as below: The management company is a Government of Kerala undertaking employing nearly 400 workmen in the two divisions viz. Kaolin and porcelain divisions. The workmen involved in this dispute are 18 security guards in the Kaolin division. This division is covered by the provisions of the Mines Act (the Act for short). The company has been running a canteen for the benefit of the workmen as provided under Mines Act. The management laid off the entire workmen from 14-6-1986 and the canteen was also closed. The lay off was lifted on 31-10-1987. During the lay off period security guards were given full employment. The Kaolin division had a unit at Mulavana where there was no canteen facility. The management therefore paid canteen allowance @ 1.50 per worker per day which was intended to enable them to meet additional expenses they had to incur in the absence of canteen facility. The security guards who had attended their duties during lay off had to spend money for their food and refreshments as the canteen was closed. Though the unions demanded canteen allowance the management did not extend the same to the guards involved in this dispute. Provision for canteen facility in subsidised rate is a welfare measure under the Mines Act and the management has no right to deny the same to security guards. Canteen facilities were available to these workmen before 14-6-1986. The management is bound to make good the additional expenses incurred by the security guards during the lay off period and hence they are entitled to get canteen allowance at the rate available in Mulavana Mines. The claim is for payment of canteen allowance @ Rs. 1.50 to the 18 security guards per day during the period 14-6-1986 to 31-10-1987.

3. The management opposes the claim. The contentions of management are briefly as below: This reference is irregular, illegal, and bad in law. The unions have no authority or locus standi to represent the workers in this case. Hence there is no valid or proper reference for adjudication. There was no practice of paying canteen allowance in lieu of subsidised canteen facilities in Kaolin and Porcelane division. The statement of the unions about allowance at Mulavana Mines as such is not correct. During the lay off period canteen was not functioning and the workers were not paid canteen allowance. The lay off was partially lifted from 11-5-1987 and 50 per cent employees lay off was lifted for maintenance. Lay off was completely lifted from 7-12-1987. On 27-2-1988 an agreement was entered into between the unions and management and canteen subsidy was fixed as Rs. 1.80 and the date of payment was determined as 1-11-87. The management has not denied any statutory right to the workers in this dispute and the workmen are not entitled to get any relief. According to the management the present demand is unsustainable and the workers are not entitled to any relief.

4. The joint secretary of union No. 1 examined himself as WW1. One of the security guards involved in this dispute was examined as WW2. Exts. W1 and W2 have also been marked on the side of the unions. The Manager (Personnel

Administration) in charge was examined as MW1 on the side of management. Exts. M1 to M4 have also been marked on their side.

5. The management has raised a preliminary objection to the effect that the dispute referred for adjudication and the claim raised before the Court differs in a material aspect and hence the claim is to be rejected. It was pointed out that as per the schedule of the reference order the dispute is with regard to eligibility of canteen allowance for the period from 14-6-1987 to 31-10-1987. Where as the demand of the union as per the claim statement is for the period 14-6-1986 to 31-10-1987. The conciliation file regarding this dispute has been produced before this court by Assistant Labour Commissioner (Central) (A.L.C. for short), which I am marking as Ext. C1 for convenience of discussion. Page numbers 1-A, 5 and 8 of this file are demand letters of unions addressed to the A.L.C., where in the claim is from June 1986. Page No. 11 of Ext. C1 file is the Minutes of the conciliation proceedings held on 21-11-1990 in which the management representative was also present. In the page it is stated that the security guards were required to attend duties during the period from 14-6-1986 to 31-10-1987. Page No. 15 of this conciliation file is the failure of conciliation report where in also the claim is stated for the period from 14-6-1986 to 31-10-1987. It is thus clear that the demand of the unions from the very beginning was for the period from 14-6-1986 to 31-10-1987. No doubt in the schedule of the reference order the dispute is stated for the period 14-6-1987 to 31-10-1987. In the light of specific statements in Ext. C1 file the date 14-6-1987 stated in the reference can only be considered as a mistake. The claim was definitely from the period in 14-6-1986 as per Ext. C1 file and the management has not raised any objection regarding the date of claim either at the conciliation stage or before this court till the time of final argument. In view of the above the objection raised by the management is only to be rejected.

6. The claim of the unions is for canteen allowance @ Rs. 1.50 per day. WW1 and WW2 have deposed that before the lay off period the management was conducting canteen in the Kaolin division and the workmen were getting food in the subsidised rates. It is also stated that in the Mulavana mines where there was no canteen facility the workmen were given canteen allowance @ Rs. 1.50 per day. It is admitted by MW1 also. According to the unions the canteen facility was stopped with effect from 13-6-1986 and the security guards involved in this dispute were made to work in all the 3 shifts during the entire period of lay off and they had to spend money from their pocket to meet the additional expenses for food and refreshment since there was no canteen facility. It is not disputed that the canteen facility was made available as required under the provisions of the Act. It is also not disputed that in the Mulavana mines the workmen were given Rs. 1.50 per day ue to the absence of canteen facility. So the present claim is justified on the ground that the canteen was not working and the canteen facility was not available to the security guards though the management is bound to provide such facility under Mines Act.

7. The claim is opposed by the management on the ground that during lay off period not more than 100 workmen were worked and the management was not bound to conduct the canteen. According to MW1 only if 250 workmen were employed the management is bound to conduct the canteen. Section 85(p) of the Act requires provision for canteen in mines where more than 250 persons are ordinarily employed. Admittedly more than 250 workmen are employed in the management company. So the normal strength of workers in the company is the ordinarily employed persons and not the number of workers employed each and every day. Since the employment strength on the roll of the company is more than 250, the management is bound to conduct a canteen. Merely because the number of persons employed were less than 100 due to lay off for certain period the management has no right to stop the canteen. The management has no case that lay off was due to the fault of the workmen. The security guards employed in all the 3 shifts during the period in question cannot be made to suffer for the reason that the other workmen were laid off by the management. No doubt running a canteen for less number of workmen may not be profitable. But the workmen employed during that period are eligible to get canteen facility or payment in lieu of such facility. The management has no case that during the period in question total employment strength of the company on the rolls was less than 250. Hence the management was bound to provide the canteen for the benefit of the employees who had worked during lay off. The stoppage of the canteen from 14-6-1986 was in controvention of the provisions of the Act also. In these circumstances the action of management in stopping the canteen was illegal and unjustified. The present argument on the ground of employment strength is without force.

8. Admittedly the management was paying Rs. 1.50 in the Mulavana mines where there was no canteen facility. That payment fully justifies the present claim of the security guards as the canteen was not working during the lay off period though these workmen were made to work in all the 3 shifts. As stated above the management is under an obligation to provide canteen facility. In the absence of canteen in Mulavana mines, canteen allowance was paid to the employees. It was thus a prevailing practice and hence become an implied condition of service. Some of the security guards in the Kaolin division had worked in Mulavana mines also during the lay off period. In view of the above the present claim is legal and justified. The above view is supported by a decision of the Supreme Court in Mcleod and Company V. Its workmen [1964 (1) L.L.J. 386]. In that case workmen claimed cash allowance in lieu of tiffin arrangement made by the company which was unsatisfactory according to the workmen. The arrangements for tiffin came to be introduced by the company on demand as 31 comparable concerns were supplying free tiffin to their employees. The Tribunal allowed the claim and the matter finally came before the Supreme Court. The apex court did not interfere the finding of the Tribunal. The court after finding how the prevailing arrangements came to be introduced held thus at page 388 :—

> "Under these circumstances, if the Tribunal took the view that the appellant was under an obligation to provide some cash allowance for tiffin to its employees, we do not see how we can interfere with it on the ground that the impugned decision is erroneous in law. The history of the relations between the parties coupled with the prevailing practice in the comparable concerns in the region strongly supports the view taken by the tribunal that in the appellant's concern it was an implied condition of service that in addition to the wages and dearness allowance, a provision for tiffin was an amenity to which the employees were entitled."

No doubt in the above case cash allowance in lieu of tiffin arrangement was a prevailing practice in comparable concern in the region which was also taken into account by the Tribunal, in the case before me canteen facility was a prevailing practice and in the absence of canteen at Mu'avana Mines payment of canteen allowance was in practice. Therefore the above decision of apex court is applicable here.

9. According to the learned counsel for the management there was no practice of paying canteen allowance to any body and an agreement for payment of canteen subsidy was entered into between the management and the unions only on 27-2-1988 and the agreement was fixed as Rs. 1.80 with effect from 1-11-1987. So the present claim is against the terms of that agreement according to the management. The present claim is for canteen allowance in lieu of canteen facility which was available to the employees earlier and not for canteen subsidy. Therefore Ext. M1 agreement has no relevance here. Further canteen subsidy was introduced when the running of the canteen was entrusted to a contractor and when the management was not directly running the canteen. The present claim is for the period when the management was directly running the canteen and there was no question of canteen subsidy. So the present argument on the basis of Ext. M1 is only to be rejected.

10. There is a dispute regarding the total number of workmen eligible to get the claim in this dispute. The claim of the unions is for 18 guards. But according to the management only 14 security guards were employed in the establishment as spoken to by MW1. Reliance was also placed on Ext. M2 the acquittance roll of Kaolin division for the period from 12/1984 to 8/1986. According to MW1 as per pages 247 and 248 of Ext. M2, which was marked as Ext. M2-A, only 14 guards were employed during May 1986. As per page 281 of Ext. M2, which was marked as Ext. M2-B only 14 guards were employed during the period July 1986.

So according to MW1 only a maximum of 14 security guards were employed. In Ext. M2-A and M2-B only names of employees employed are stated. There is no statement that particular persons were employed as security guards. However admittedly 14 security guards were employed. Further MW1 has admitted that in addition to 14 S/s. Joy, Cletus and Sunfucious were also employed as security guards but according to MW1 those 3 persons were employed for security duty also among other duties. MW1 has stated that considering the guard duty also of these 3 persons they were subsequently appointed in the company as guards. Since these 3 persons were admittedly employed for guard duty they are also eligible to get the facility for the days on which they were employed as guards. Thus he total number of guards employed becomes to 17. As per the conciliation file produced by the Assistant Labour Commissioner before this Tribunal also the claim was raised for only 17 persons. Therefore the 14 security guards admitted by MW1 as stated in Ext. M2-A and M2-B and S/Sh. Joy, Cletus and Sunfucious are eligible to get the facility now claimed by the unions.

11. In the result, an award is passed holding that the demand raised by the unions claiming canteen allowance in respect of 17 security guards involved in this dispute for the period from 14-6-1986 to 31-10-1987 is fair and justified and they are accordingly eligible to get Rs. 1.50 per day.

C. N. SASIDHARAN, Industrial Tribunal

APPENDIX

Witnesses examined on the side of the Workmen :

WW1.—Sri M. Pushparajan.

WW2.—Sri Y. Titus.

Witness examined on the side of the Management :

MW1.—Sri S. Y. Alexander.

Documents marked on the side of the Workmen :

Ext. W1.—Pay cover of Sri Y. Titus for the month of 5/1986.

Ext. W2.—Pay cover of Sri P. Poulose for the month of 2/1985.

Documents marked on the side of the Management :

Ext. M1.—True copy of the Minutes of meeting held at the Head Office of the management company on 27-2-1988 between the management and the unions.

Ext. M2.—Aquittance roll for the period from 12/1984 to 8/1986 of the Kayolin division of the management company.

Ext. M3.—Aquittance roll for the period from 9/1986 to 5/1988.

Ext. M4.—Series (3. numbers) wages registers of the employees for the period from 1-4-84 to 31-7-88.

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1994

का. आ. 136.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नैशनल बैंक, कोटा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-12-94 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/422/90—आई. आर. बी.-2]
वी. के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th December, 1994

S.O. 136.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank, Kota and their workmen, which was received by the Central Government on 23-12-94.

[No. L-12012/422/90-IR(B-II)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं सी.आई.टी. 18/91

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्र. एल-12012/422/90-आई.आर.बी-II दि. 5-4-91.

महामंत्री, राजस्थान (स्टेट) बैंक वर्कर्स आरगेनाईजेशन, कोटा । —प्रार्थी

बनाम

क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटा —अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के एल व्यास, आर.एच.जे.एस.
प्रार्थी की ओर से : श्री आर.सी. जैन
अप्रार्थी की ओर से : श्री एस.सी. गुप्ता
दिनांक अवार्ड : 22-8-1994

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रमिक श्री रमजान खां लिपिक, पंजाब नेशनल बैंक व उसके नियोजक प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, केन्द्रीय कार्यालय भरतपुर के मध्य उत्पन्न निम्न विवाद को अधिनिर्णय हेतु निर्देशित किया गया है

'Whether the action of the management of Punjab National Bank, Regional Manager, Bharatpur, in imposing punishment of two annual grade increments with cumulative effect on Shri Ramzan Khan, Clerk-cum-cashier at their Kota city branch and previously at Baran is legal and justified ? If not to what relief is the workman entitled ?'

2. श्रमिक द्वारा प्रस्तुत क्लेम के अनुसार कथित दुराचरण की घटना के समय उसकी ड्यूटी 29-9-87 को पंजाब नेशनल बैंक (जिसे बाद में बैंक संबोधित किया जायेगा) की बारां शाखा में लिपिक के पद पर थी व उसी रोज शाखा मैनेजर द्वारा श्रमिक को एक आरोप पत्र दिया जाकर निलंबित किया गया था । आरोप पत्र का जवाब श्रमिक द्वारा प्रस्तुत किया गया परन्तु उसे संतोषजनक नहीं मानने के कारण नियोजक द्वारा श्रमिक के विरुद्ध विभागीय जांच की गई तथा जांच सम्पूर्ण होने पर अनुशासनिक अधिकारी द्वारा श्रमिक के विरुद्ध दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश दिया गया व श्रमिक

द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील अधिकारी द्वारा इस आदेश को कायम रखा गया। जांच कार्यवाही के आधार पर पारित किये गये दण्डादेश को श्रमिक ने सारांश में इन आधारों पर चुनौती दी है कि जांच के दौरान श्रमिक को अपनी प्रतिरक्षा समुचित रूप से प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, आरोप पत्र से सुसंगत प्रलेख की प्रतिलिपियां श्रमिक को उपलब्ध नहीं कराई गई तथा विभागीय गवाहान से जिरह करने का समुचित अवसर श्रमिक को नहीं दिया गया। जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि श्रमिक को उपलब्ध नहीं कराने का आक्षेप भी क्लेम में लगाया गया है व इसके अलावा यह अभिकथित किया गया है कि जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई थी उससे श्रमिक के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं बनता इसलिए जांच अधिकारी का विनिश्चय अनुचित है, जांच अधिकारी ने समस्त आरोपों को सिद्ध नहीं माना है व उसके बावजूद अनुशासनिक अधिकारी ने तथ्यों पर विचार किये बिना सरसरी तौर पर आक्षेपित दण्डादेश पारित किया है। शाखा प्रबन्धक द्वारा श्रमिक को दोषारोपण पत्र देने की कार्यवाही की वैधानिकता को भी श्रमिक ने चुनौती दी है व इसके अलावा यह आपत्ति ली है कि बैंक द्वारा बनाये गये अनुशासनिक नियमानुसार संचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

3. नियोजक की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह बताया गया है कि श्रमिक के खिलाफ जांच कार्यवाही पूरी तरह नियमानुसार की गई थी व जिस अधिकारी द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है वह द्विपक्षीय समझौते व उनके अनुसार बनाये गये नियमों के अनुसार यह कार्यवाही करने के लिए सक्षम था। जांच अधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप समस्त कार्यवाही करना जवाब में बताया गया है वह यह भी कहा गया है कि श्रमिक को सुसंगत प्रलेख की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई गई थी, गवाहान से जिरह करने का व अपने गवाह प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया था। यह वैकल्पिक अनुतोष भी मांगा गया है कि यदि किसी कारण जांच कार्यवाही को दूषित माना जावे तो नियोजक को श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये दुराचरण को साबित करने का अवसर दिया जावे। बहस दोनों पक्षों की सुनी गई व उपलब्ध अभिलेख तथा प्रस्तुत विधि दृष्टान्तों पर विचार किया गया।

4. श्रमिक की ओर से दोषारोपण पत्र जारी करने के संबंध में जो विधिक आपत्ति ली गई है सर्वप्रथम उस पर विचार किया जाता है क्योंकि वह मामले को मूलभूत रुप से प्रभावित करती है। श्रमिक को आरोप पत्र शाखा प्रबंधक, बारां द्वारा 29-9-87 को जारी किया गया है। प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार इस प्रकार के मामले में अनुशासनिक अधिकारी बैंक की ओर से क्षेत्रीय प्रबन्धक को घोषित किया हुआ है व उन्हीं के समक्ष आरोप पत्र का जवाब श्रमिक ने प्रस्तुत किया था व बाद में उन्हीं के द्वारा घरेलू जांच करने के आदेश दिये गये थे। इस तथ्यात्मक व नियमों की स्थिति को देखते हुए श्रमिक की ओर से यह बहस की गई है कि शाखा प्रबन्धक श्रमिक के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं है व इसी कारण आगे की समस्त कार्यवाही अवैधानिक हो जाती है। बैंक के विद्वान प्रतिनिधि ने इस संबंध में 13-4-87 के एक परिपत्र व नियमों के संबंध में जारी किये गये आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसका पद सं 2(1) निम्न प्रकार है :

"The incumbent Incharge of each office is empowered to issue and serve charge-sheets on the defaulting workmen and to suspend them, if considered necessary, after obtaining prior approval from Disciplinary Authority designated under para (ii) below. In extreme exceptional cases where the employee is involved in a fraud of serious nature or commits an act of riotous behaviour in the premises of the Bank and it is considered expedient to suspend the employee immediately and prior permission cannot be obtained. He may be suspended by the Incumbent Incharge and subsequent approval of the Disciplinary Authority may be obtained immediately by advising the circumstances necessitating immediate actions. However, in respect of the employees of the Zonal|Reginoal Offices and exceptionally very large branches and divisions and Departments at HO, respective managers are authorised to issue and serve charge sheet and also to suspend, if necessary."

5. नियोजक पक्ष के प्रतिनिधि का कथन है कि उक्त नियम जो द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप बनाये गये हैं उनको देखते हुए शाखा प्रबन्धक द्वारा आरोप पत्र जारी करना पूर्ण रूप से उचित है व सिर्फ निलम्बन की स्थिति में ही अनुशासनिक अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है परन्तु अपवाद स्वरूप मामलों में पूर्व अनुमति के बिना भी शाखा प्रबन्धक द्वारा कर्मचारी को निलम्बित किया जा सकता है किन्तु आरोप पत्र जारी करने से पूर्व इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार की भाषा उक्त नियम में उपयोग में ली गई है उसकी व्याख्या निश्चित रूप से नियोजक प्रतिनिधि द्वारा बताई गई प्रक्रिया से किया जाना न्यायोचित है व निष्कर्ष यह है कि शाखा प्रबन्धक द्वारा जो दोषारोपण पत्र श्रमिक को जारी किया गया है वह कार्यवाही नियमानुसार वैधानिक है। द्विपक्षीय समझौता बैंक कर्मचारियों पर लागू है इस बाबत कोई भी आपत्ति श्रमिक की ओर से नहीं की गई है। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि का कथन है कि द्विपक्षीय समझौते में इस प्रकार का नियम बनाने का कोई प्रावधान नहीं है जो तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने द्विपक्षीय समझौते के खण्ड 19.14 में जो संशोधन 31-10-79 को हुआ है, उसका सहारा लेते हुए किसी भी रूप में यह बताने का प्रयास नहीं किया गया है कि उक्त समझौता बैंक को दोषारोपण पत्र के संबंध में नियम बनाने के लिए कोई शक्तियां प्रदान करता है। जहां तक श्रमिक के निलम्बन का प्रश्न है, वह बिन्दु इस विवाद में विचारणीय नहीं है इसलिए इस पर टिप्पणी करना अपेक्षित नहीं है कि श्रमिक के निलम्बन की कार्यवाही जो शाखा प्रबन्धक द्वारा की गई थी वह उचित थी या नहीं।

6. श्रमिक की ओर से एक आपत्ति वैधानिक रूप से यह ली गई है कि जांच अधिकारी जो बैंक द्वारा नियुक्त किया गया था वह प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से वेतनमान के अनुसार कनिष्ट था इसलिए यह मानने का न्यायोचित आधार है कि जांच कर्ता प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से प्रभावित हो सकता था व ऐसी स्थिति में जांच कार्यवाही को उचित नहीं माना जा सकता। जांच अधिकारी व प्रस्तुतकर्ता के पद व वेतनमान के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है लेकिन जांच का जो प्रलेख प्रस्तुत हुआ है उसमें जांच अधिकारी द्वारा 11-12-87 को आदेशिका में यह उल्लेख है कि प्रस्तुतकर्ता तृतीय वेतनमान के अधिकारी हैं जबकि जांच अधिकारी द्वितीय वेतनमान के अधिकारी हैं लेकिन इससे जांच कार्यवाही पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि दोनों की नियुक्ति अनुशासनिक अधिकारी द्वारा की गई है। इस प्रकार जहाँ तक तथ्यों का प्रश्न है, यह साबित है कि जांच अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से कनिष्ठ वेतनमान के थे किन्तु श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने ऐसा कोई भी नियम या विधि दृष्टान्त नहीं बताया है जिसके अनुसार सामान्य रूप से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की जांच अधिकारी से कनिष्ठ होना आज्ञापक या वांछित हो। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने अभिलेख या परिस्थितियों को आधार बताते हुए यह बहस भी नहीं की है कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के तुलनात्मक रूप से वरिष्ठ होने के कारण किसी भी प्रकार जांच अधिकारी विपरीत रूप से प्रभावित हुआ हो व इस कारण श्रमिक के विरुद्ध जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हुई है। किसी भी नियम व विशेष परिस्थिति की उपस्थिति के अभाव में यह मानने का आधार नहीं रहता कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के वरिष्ठ होने के कारण जांच अधिकारी ने प्रभावित होकर श्रमिक के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

7. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने क्लेम में जांच के लिए एक आपत्ति यह ली है कि आरोप पत्र से सुसंगत प्रलेख की प्रतिलिपियां श्रमिक को उपलब्ध नहीं करायी गयी व बहस में भी इस तथ्य को आधार बनाया गया है। इसके बावजूद उनके द्वारा विशिष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि श्रमिक को कौन से प्रलेख की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई गई। श्रमिक द्वारा किसी भी प्रक्रम पर जांच अधिकारी के समक्ष या अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष यह आपत्ति नहीं ली गई कि उन्हें किसी प्रलेख की प्रतिलिपि नहीं दी गई है जो उपलब्ध कराई जावे। यह बहस भी श्रमिक की ओर से नहीं की गई है कि कौनसा प्रलेख उपलब्ध नहीं होने से उसके हितों पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। समस्त गवाहान से जिरह के दौरान भी इस प्रकार की आपत्ति श्रमिक की ओर से नहीं ली गई है जैसा कि अभिलेख के पठन से स्पष्ट होता है। अतः इस आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है कि श्रमिक को सुसंगत प्रलेख की प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं कराई गई व इस कारण जांच कार्यवाही में वह अपना पक्ष समुचित रूप से नहीं रख सका।

8. श्रमिक की ओर से एक बहस यह की गई है कि जांच अधिकारी ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह इसलिए अनुचित है क्योंकि जिन आरोपों को जांच अधिकारी ने साबित माना है उनके लिए कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है व चौथे अथवा अंतिम आरोप को जिस रूप में जांच अधिकारी ने साबित माना है इस प्रकार का आरोप श्रमिक के विरुद्ध नहीं लगाया गया है। जहां तक साक्ष्य व आरोपों के प्रमाणित होने का प्रश्न है, उसके लिए इतना इतना लिखना पर्याप्त है कि जांच अधिकारी ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें समस्त उपलब्ध साक्ष्य को व प्रस्तुत प्रलेख का विवेचन किया गया है व साक्ष्य के आधार पर किस आरोप को पूर्ण रूप से व किस आरोप को आंशिक रूप से साबित माना है। जांच अधिकारी द्वारा आरोप के संबंध में किये गये विवेचन को उसी स्थिति में अनुचित माना जा सकता है यदि उसको प्रमाणित मानने के लिए कोई भी वैधानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो अथवा उपलब्ध साक्ष्य को युक्तिसंगत रूप से विवेचन करने से आरोप को साबित नहीं माना जा सकता हो। यदि उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन करने से संभावित रूप से दूसरा विनिश्चय लिया जा सकता है तो भी इस आधार पर जांच अधिकारी के विवेचन को अनुचित नहीं माना जा सकता। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने बहस में साक्ष्य पर विवेचन करते हुए किसी भी रूप में यह बताने का प्रयास नहीं किया है कि किस बिन्दु पर जांच अधिकारी का विनिश्चय आरोप साबित मानने के संबंध में अनुचित है। न्यायाधिकरण द्वारा पूरी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया व इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जांच अधिकारी ने आरोपों के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया है वह उचित व साक्ष्य आधारित है।

9. आरोप श्रमिक के विरुद्ध कुल चार लगाये गये हैं। जांच अधिकारी के प्रतिवेदन में आरोप सं. 1 को पूर्ण रूप से साबित माना गया है जिसका आधार यह है कि श्रमिक कथित घटना के दिन 20 मिनट देरी से शाखा में उपस्थित हुआ था। दूसरा आरोप किसी ग्राहक के कलैक्शन हेतु चैक स्वीकार नहीं करने व उससे अभद्र व्यवहार करने के संबंध में है तथा इस आरोप के लिए मात्र यह साबित माना गया है कि श्रमिक ने दलीप कुमार ग्राहक के चैक को अस्वीकार किया इसलिए ग्राहक सेवा में व्यवधान उत्पन्न हुआ व ग्राहक के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तीसरा आरोप शाखा प्रबन्धक के साथ अभद्र व्यवहार करने का व उनके वैधानिक आदेश की अवहेलना करने के संबंध में है। इस संबंध में जांच अधिकारी ने यह विनिश्चय दिया है कि आरोप सं. 3 का कोई भी भाग पूर्णतः सिद्ध नहीं होता है। अर्थ इसका यह है कि इस आरोप को साक्ष्य व परिस्थिति से प्रमाणित नहीं माना गया है। आरोप सं. 4 जो श्रमिक के विरुद्ध लगाया गया है उसमें यह तथ्य दर्ज किया गया है कि श्रमिक ने प्रबन्धक कक्ष में व बैंक हॉल में चिल्लाना शुरू कर दिया व नारे लगाय तथा कुछ नारों

का उल्लेख भी दोषारोपण पत्र में किया गया है। इस आरोप में कहीं भी यह उल्लिखित नहीं है कि श्रमिक बिना पूर्व अनुमति के शाखा परिसर से अनुपस्थित रहा हो किन्तु चारों आरोपों के बाद में दुराचरण की परिभाषा के संबंध में यह अवश्य उल्लेख किया गया है कि श्रमिक पूर्व अनुमति के बिना दिन भर शाखा परिसर से बाहर रहा जो गंभीर अवचार है। जांच अधिकारी ने चौथे आरोप के संबंध में यह विनिश्चय दिया है कि श्रमिक द्वारा बैंक परिसर में नारेबाजी करने का आरोप साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता किन्तु यह साबित है कि श्रमिक बिना पूर्व अनुमति के बैंक परिसर छोड़कर पूरे दिन बाहर रहा व नारेबाजी की। इस प्रकार जो चौथा आरोप श्रमिक के विरुद्ध लगाया गया है उसमें बिना अनुमति शाखा परिसर से अनुपस्थित रहने का लक्ष्य उल्लिखित नहीं है व इस कारण जिस रूप में जांच अधिकारी ने आरोप साबित माना है वह विनिश्चय उचित नहीं कहा जा सकता। जो आरोप श्रमिक के विरुद्ध नहीं है उसके लिए न तो साक्ष्य ली जा सकती है व न हो उस संबंध में कोई विनिश्चय किया जा सकता है। इसलिए जहां तक जांच अधिकारी के प्रतिवेदन का प्रश्न है, उस संबंध में मात्र चौथे आरोप का विनिश्चय ही अनुचित कहा जा सकता है व बकाया आरोप जो भी प्रमाणित या अप्रमाणित माने गये हैं उनके संबंध में जांच अधिकारी के विनिश्चय को अनुचित या गलत मानने का कोई भी आधार नहीं है। इस आंशिक रूप से अनुचित विनिश्चय का तमाम जांच कार्यवाही पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं माना जा सकता क्योंकि जो आरोप श्रमिक के विरुद्ध साबित माने गये हैं उनके आधार पर भी श्रमिक को दण्डित किया जा सकता है किन्तु अनुशासनिक अधिकारी द्वारा इस संबंध में अगले आदेश में अलग से विवेचन करना व निष्कर्ष निकालना आवश्यक है।

10. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने एक वैधानिक आपत्ति यह ली है कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जो दण्डादेश पारित किया गया है वह कारण सहित (स्पीकिंग आर्डर) नहीं है इसलिए विधिक रूप से उस आदेश को उचित नहीं माना जा सकता व इसी आधार पर आक्षेपित दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में उन्होंने निम्न दो विधि दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :

1. राजस्थान राज्य बनाम अमोलक चंद आर. एल आर. 1943 पेज 246।
2. सियाराम बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू, एल. सी 1992 (1) पेज 352।

11. दोनों विधि दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अनुशासनिक अधिकारी का आदेश कारण सहित होना चाहिये व उसमें उन तथ्यों का व परिस्थितियों का उल्लेख होना चाहिये जिनके आधार पर आरोप को प्रमाणित मानते हुए श्रमिक के विरुद्ध दण्डादेश पारित किया गया है क्योंकि इससे श्रमिक को अनुशासनिक अधिकारी के समय अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में व अपील प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। इन विधि दृष्टान्तों में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि यदि इस प्रकार कारण सहित दण्डादेश पारित नहीं किया जा सकता है तो उसे वैधानिक नहीं माना जा सकता। नियोजक की ओर से इस संबंध में कोई भी विपरीत विधि दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किया गया है संदर्भित विधि दृष्टान्तों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। उनको दृष्टिगत रखते हुए परिशिष्ट "7" दण्डादेश पर विचार किया जाना वांछित है। इस आदेश में मात्र यह लिखा गया है कि द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुसार श्रमिक को और अवचार का दोषी मानते हुए दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने से दण्ड से दण्डित किया जाना प्रस्तावित है इसलिए श्रमिक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। श्रमिक के स्पष्टीकरण के पश्चात इसी प्रस्तावित दण्डादेश की पुष्टि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा की गई है। परिशिष्ट–7 आदेश के पठन से यह स्पष्ट है कि उसमें न तो यह उल्लेख है कि श्रमिक के विरुद्ध क्या आरोप है, न ही यह उल्लेख है कि जांच अधिकारी द्वारा किन आरोपों को साबित माना गया है उनके लिए क्या साक्ष्य व परिस्थितियां उपलब्ध है। यदि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से अनुशासनिक अधिकारी द्वारा सहमति प्रकट की जाती है तो उस स्थिति में विस्तृत साक्ष्य का विवेचन करना आवश्यक नहीं हो सकता किन्तु सारांश में आरोप की प्रकृति, जांच अधिकारी के प्रतिवेदन का सारांश व साक्ष्य सारांश उल्लिखित किया जाना हर हालत में आज्ञापक है। परिशिष्ट-7 आदेश किस प्रकार से पारित किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि आज्ञापक आवश्यक तत्वों की समाविष्टि आदेश में नहीं की गई है व इस कारण इस आदेश को कारण सहित होना नहीं माना जा सकता यह मान्य विधि सिद्धान्त है कि जहां अनुशासनिक अधिकारी का आदेश कारण सहित नहीं हो उस स्थिति में आक्षेपित दण्डादेश को अपास्त करने के अलावा न्यायाधिकरण के समक्ष और कोई भी विकल्प नहीं रहता।

12. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी बहस में यह भी बताया है कि जांच अधिकारी ने श्रमिक के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में कुछ गवाहों के बयान लिये है तथा उस रोज जांच कार्यवाही को स्थगित करने के उचित कारण या फिर भी स्थगन स्वीकार नहीं किया गया इसलिए श्रमिक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है यह इस आधार पर भी जांच कार्यवाही को उचित नहीं माना जा सकता। इस संबंध में उन्होंने जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई विभिन्न आदेशिकाओं की ओर न्यायाधिकरण का ध्यान आकर्षित किया है। सर्वप्रथम जांच अधिकारी के समक्ष 11-12-87 को सम्पन्न हुई थी व उस रोज दोनों पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित थे इसके पश्चात् 20-1-88 को कार्यवाही की गई व उस रोज भी दोनों प्रतिनिधि उपस्थिति थे व कुछ प्रलेख के आदान-प्रदान के अलावा कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। 8-3-88 को आरोपित के प्रतिनिधि श्री

डी. पी० बंसल उपस्थित नहीं थे व आरोपित कर्मचारी ने आगे तारीख देने का अनुरोध किया था जो स्वीकार किया गया। आदेशिका के पठन से यह भी स्पष्ट है कि उस रोज कोई भी विभागीय गवाह उपस्थित नहीं था व आगे की तारीख 6-4-88 निश्चित की गई थी किन्तु जाँच अधिकारी उस रोज प्रशिक्षण हेतु दिल्ली गये थे इसलिए आगे तारीख 15-4-88 निश्चित की गई। 15-4-88 को दोनों प्रतिनिधि उपस्थित थे व विभाग की ओर से दो गवाहों के बयान कराये गये थे अगली तारीख 16-4-88 को प्रबन्धक का कोई गवाह उपस्थित नहीं था व श्रमिक की ओर से साक्ष्य बंद करने का अनुरोध किया गया जो अस्वीकार किया जाकर 10-5-88 की तिथि निश्चित की गई। 10-5-88 को आरोपित के प्रतिनिधि श्री डी. पी. बंसल उपस्थित थे परन्तु स्वयं आरोपित उपस्थित नहीं था व आरोपित के प्रतिनिधि ने यह अनुरोध किया कि आरोपित के निर्देश के अभाव में वे बयान कराने में असमर्थ है व इस अनुरोध पर आगामी तारीख 31-5-88 निश्चित की गई। 31-5-88 व 7-6-88 की जाँच अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण स्थगन किया गया व 14-6-88 को आगे की तारीख तक की गई उस रोज प्रस्तुतकर्ता श्री एम. एल. गुप्ता व बचाव प्रतिनिधि श्री बंसल दोनों ही उपस्थित नहीं थे व इस कारण आगे की तारीख 12-7-88 तय की गई। 12-7-88 को भी दोनों पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने के कारण कार्यवाही स्थगित की गई। अंत में 20-9-88 को व 11-10-88 को आरोपित के प्रतिनिधि श्री डी. पी. बंसल उपस्थित नहीं थे व दोनों ही रोज जांच अधिकारी को उनकी अनुपस्थिति के संबंध में तार व सूचना प्राप्त हुई थी व श्रमिक ने भी लिखित आवेदन कर यह अनुरोध किया था कि आगे की तारीख दी जाये क्योंकि उनके प्रतिनिधि उचित कारण से उपस्थित नहीं हो सकेंगे। दोनों तिथि पर आरोपित के अनुरोध को अस्वीकार किया गया व 20-9-88 को परिवादी दिलीप कुमार शर्मा का बयान लिया गया व 11-10-88 को स्वयं आरोपित के बयान प्रतिरक्षा में दर्ज किये गये। अंतिम दोनों आदेशिकाओं को आधार बनाते हुए यह बहस की गई है कि जब पूर्व में प्रबन्धक पक्ष के गवाह उपस्थित नहीं थे व प्रस्तुतकर्ता उपस्थित नहीं था तो भी स्थगन जारी किया गया था लेकिन इन दो तिथियों को बचाव प्रतिनिधि उचित कारण से अनुपस्थित था इसके बावजूद विभागीय व बचाव पक्ष के बयान उनकी अनुपस्थिति में लिये गये जिससे श्रमिक न तो समुचित रूप से प्रतिवादी से जिरह कर सकता व न ही सही रूप से अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर सका उनके कथन का सार यह है कि दोनों तिथि पर स्थगन स्वीकृत करने के न्यायोचित कारण थे परन्तु ऐसा जाँच अधिकारी द्वारा नहीं करने से जिस प्रकार बयान लिये गये है उसको देखते हुए जांच कार्यवाही को उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि श्रमिक इस संबंध में पर्याप्त दक्षता नहीं रखता था। जिस प्रकार के तथ्य जांच अधिकारी की आदेशिकाओं के आधार पर उल्लिखित व विवेचित किये गये है उनको देखते हुए यह मानने का आधार है कि दिनांक 11-10-88 से 20-9-88 को आरोपित के अनुरोध पर जाँच कार्यवाही को स्थगित करने के समुचित कारण थे व उसके अभाव में श्रमिक के विरुद्ध की गई जाँच को उचित नहीं माना जा सकता।

13. श्रमिक की ओर से एक वैधानिक बहस यह की गई है कि द्विपक्षीय समझौते के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही के जो प्रावधान बनाये गये हैं उनके अनुसार अध्याय 22 के नियम 6 (डी) में मात्र वेतन वृद्धि रोकने का प्रावधान है तथा संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने का कोई भी नियम नहीं है इसलिए जो संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने का दण्डादेश अनुशासनिक अधिकारी द्वारा पारित किया गया है यह अवैधानिक है। इस संबंध में अलकेन्द्र सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एस.एल.आर. 1981 पेज 33 को अवलम्ब लिया गया है। चूंकि श्रमिक के विरुद्ध पारित दण्डादेश की कार्यवाही को अन्य आधारों पर अनुचित माना गया है इसलिए इस विधिक बिन्दु पर विवेचन किया जाकर अलग से राय व्यक्त करना अपेक्षित व आवश्यक नहीं है।

14. जांच कार्यवाही से संबंधित तथ्यों व विधिक स्थिति के विवेचन के परिणामस्वरूप विवाद में अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, भरतपुर द्वारा श्रमिक रमजान खान के विरुद्ध दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का पारित दण्डादेश अनुचित व अवैधानिक है जिसे अपास्त किया जाता है व इसके फलस्वरूप श्रमिक समस्त सुसंगत परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

15. अवार्ड आज दिनांक 22-8-94 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

के. एल. व्यास, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1994

का. आ. 137.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक भरतपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-12-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल 12012/429/90-आई आर बी —2]

बी. के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th December, 1994

S.O. 137.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank, Kota and their workmen, which was received by the Central Government on 23-12-94.

[No .L-12012/429/90-IR(B-II)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 25/1991

रैफरेंस :—केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल. 12012/429/90—आई. आर./डी. दिनांक 5-4-91

श्री बाबू लाल क्लर्क-कम-कैशियर मार्फत महासचिव राजस्थान बैंक वर्कर्स आरगेनाईजेशन कोटा।

—प्रार्थी

बनाम

क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक, भरतपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के. एस. व्यास, आर. एच.जे.एस

प्रार्थी की ओर से श्री आर. सी. जैन

अप्रार्थी की ओर से श्री एस. सी. नेगी व श्री एस. सी. गुप्ता

दिनांक अवार्ड : 22-8-94

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधीकरण में अधिनिर्णय हेतु निर्देशित किया गया है :

'Whether the action of the management of Punjab National Bank, Regional Manager, Bharatpur in imposing punishment of stoppage of two annual grade increments with cumulative effect on Shri Babulal clerk-cum-cashier at their Kota city branch and previously at Baran is legal and justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?'

2. श्रमिक द्वारा प्रस्तुत क्लेम में आक्षेपित दण्डादेश के संबंध में यह आपत्तियां ली गई हैं कि जांच अधिकारी द्वारा सम्पन्न की गई कार्यवाही इसलिए उचित नहीं है क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा श्रमिक सम्पन्न की गई कार्यवाही इसलिए उचित नहीं है क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा श्रमिक के प्रतिनिधि के अभाव में विभागीय व बचाव पक्ष के गवाहान के बयान लिए गए व इसके अलावा यह अभिकथित किया गया है कि जांच अधिकारी के उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपों के संबंध में जो विनिश्चय दिया है वह अनुचित है तथा अनुशासनिक अधिकारी ने श्रमिक के विरुद्ध दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का जो आदेश पारित किया है वह कारण सहित नहीं होने से वैधानिक रूप से आपस्त किए जाने योग्य है व इसके अलावा यह आपत्तियां ली गई हैं कि कर्मचारी को आरोप पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है तथा बैंक ने जिस प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया था वे जांच अधिकारी से वरिष्ठ थे इसलिए जांच अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से व बिना प्रभाव के अपनी रिपोर्ट देना व जांच कार्यवाही करना संभव नहीं था।

3. नियोजक ने अपने जवाब में श्रमिक द्वारा ली गई समस्त आपत्तियों का खण्डन करते हुए यह बताया है कि जांच कार्यवाही पूरी तरह नियमानुसार व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप की गई है, आरोप पत्र नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है व बैंक का ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रस्तुतकर्ता जांच अधिकारी से कनिष्ठ होना चाहिए। यह भी जवाब में बताया गया है कि जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उससे समस्त आरोप श्रमिक के खिलाफ प्रमाणित होता है। बहस दोनों पक्षों की सुनी गई तथा उपलब्ध अभिलेख का व प्रस्तुत विधि दृष्टान्तों पर विचार किया गया।

4. श्रमिक की ओर से दोषारोपण पत्र जारी करने के संबंध में जो विधिक आपत्ति ली गई है सर्वप्रथम उस पर विचार किया जाता है क्योंकि वह मामले को मूलभूत रूप से प्रभावित करती है। श्रमिक को आरोप पत्र शाखा प्रबन्धक द्वारा द्वारा 30-9-87 को जारी किया गया है। प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार इस प्रकार के मामले में अनुशासनिक अधिकारी बैंक की ओर से क्षेत्रीय प्रबन्धक को घोषित किया हुआ है व उन्हीं के समक्ष आरोप पत्र का जवाब श्रमिक ने प्रस्तुत किया था व बाद में उन्हीं के द्वारा घरेलू जांच करने के आदेश दिए गए थे। इस तथ्यात्मक व नियमों की स्थिति को पूछते हुए श्रमिक की ओर से यह बहस की गई है कि शाखा प्रबंधक श्रमिक के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं है व इसी कारण आगे की समस्त कार्यवाही अवैधानिक हो जाती है। बैंक के विद्वान प्रतिनिधि ने इस संबंध में 13-4-87 के एक परिपत्र व नियमों के संबंध में जारी किए गए आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसका पद सं. 2(1) निम्न प्रकार है :

'The incumbent Incharge of each office is empowered to issue and serve charge-sheets on the defaulting workmen and to suspend them, if considered necessary, after obtaining prior approval from Disciplinary Authority designated under para (ii) below. In extreme exceptional cases where the employee is involved in a fraud of serious nature or commits an act of riotous behaviour in the premises of the Bank and it is considered expedient to suspend the employee immediately and prior permission cannot be obtained, He may be suspended by the Incumbent Incharge and subsequent approval of the Disciplinary Authority may be obtained immediately by advising the circumstances necessitating immediate action. However, in respect of the employees of the Zonal Regional Offices and exceptionally very large branches and divisions and Departments at HO, respective managers are authorised to issue and serve charge sheet and also to suspend, if necessary.'

5. नियोजक पक्ष के प्रतिनिधि का कथन है कि उक्त नियम जो द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप बनाए गए हैं उनको देखते हुए शाखा प्रबन्धक द्वारा आरोप पत्र जारी करना पूर्ण रूप से उचित है। व सिर्फ निलम्बन की स्थिति में ही अनुशासनिक अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है परन्तु अपवाद स्वरूप मामलों में पूर्व अनुमति के बिना भी शाखा प्रबन्धक द्वारा कर्मचारी को निलम्बित किया जा सकता है किन्तु आरोप पत्र जारी करने से पूर्व इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार की भाषा उक्त नियम में उपयोग में ली गई है उसकी व्याख्या निश्चित रूप से नियोजक प्रतिनिधि द्वारा बताई गई प्रक्रिया से किया जाना न्यायोचित है व निष्कर्ष यह है कि शाखा प्रबन्धक द्वारा जो दोषारोपण पत्र श्रमिक को जारी किया गया है वह कार्यवाही नियमानुसार वैधानिक है। द्विपक्षीय समझौता बैंक कर्मचारियों पर लागू है इस बाबत कोई भी आपत्ति श्रमिक की ओर से नहीं की गई है। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि का कथन है कि द्विपक्षीय समझौते में इस प्रकार का नियम बनाने का कोई प्रावधान नहीं है जो तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने द्विपक्षीय समझौते के खण्ड 19.14 में जो संशोधन 31-10-79 को हुआ है, उसका सहारा लेते हुए किसी भी रूप में यह बताने का प्रयास नहीं किया है कि उक्त समझौता बैंक को दोषारोपण पत्र के संबंध में नियम बनाने के लिए कोई शक्तियां प्रदान करता है। जहां तक श्रमिक के निलम्बन का प्रश्न है वह बिन्दु इस विवाद में विचारणीय नहीं है इसलिए इस पर टिप्पणी करना अपेक्षित नहीं है कि श्रमिक के निलम्बन की कार्यवाही जो शाखा प्रबन्धक द्वारा की गई थी वह उचित थी या नहीं।

6. श्रमिक की ओर से एक आपत्ति वैधानिक रूप से यह ली गई है कि जांच अधिकारी जो बैंक द्वारा नियुक्त किया गया था वह प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ था इसलिए यह मानने का न्यायोचित आधार है कि जांच कर्ता प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से प्रभावित हो सकता था व ऐसी स्थिति में जांच कार्यवाही को उचित नहीं माना जा सकता। जांच अधिकारी व प्रस्तुतकर्ता के पद व वेतनमान के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है लेकिन जांच का जो प्रलेख प्रस्तुत हुआ है उसमें जांच अधिकारी द्वारा 11-12-87 की आदेशिका में यह उल्लेख है कि प्रस्तुतकर्ता तृतीय वेतनमान के अधिकारी हैं जबकि जांच अधिकारी द्वितीय वेतनमान के अधिकारी हैं लेकिन इससे जांच कार्यवाही पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि दोनों की नियुक्ति अनुशासनिक अधिकारी द्वारा की गई है। इस प्रकार जहां तक तथ्यों का प्रश्न है, यह साबित है कि जांच अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से कनिष्ठ वेतनमान के थे किन्तु श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने ऐसा कोई भी नियम या विधि दृष्टान्त नहीं बताया है जिसके अनुसार सामान्य रूप से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का जांच अधिकारी से कनिष्ठ होना आक्षापक या वांछित हो। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने अभिलेख या परिस्थितियों को आधार बताते हुए यह बहस भी नहीं की है कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के तुलनात्मक रूप से वरिष्ठ होने के कारण किसी भी प्रकार जांच अधिकारी विपरीत रूप से प्रभावित हुआ हो व इस कारण श्रमिक के विरुद्ध जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हुई है। किसी भी नियम व विशेष परिस्थिति की उपस्थिति में अभाव में यह मानने का आधार नहीं रहता कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के वरिष्ठ होने के कारण जांच अधिकारी ने प्रभावित होकर श्रमिक के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

7. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी बहस में एक तर्क यह दिया है कि जांच अधिकारी द्वारा सम्पन्न की गई कार्यवाही इसलिए उचित व निष्पक्ष नहीं है क्योंकि अकारण श्रमिक के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में विभागीय व बचाव पक्ष के गवाहान के बयान दर्ज किए गए हैं जिससे श्रमिक अपना जवाब सही रूप से नहीं रख सका। जांच अधिकारी द्वारा तैयार किए गए अभिलेख के पठन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 9-5-88 जांच कार्यवाही में मूल रूप से पहली तारीख थी जिस दिन प्रभावी कार्यवाही होनी थी। उसी रोज श्रमिक के प्रतिनिधि द्वारा कुछ वैधानिक आपत्तियां जांच अधिकारी के समक्ष ली गई थी जिनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 21-9-88 को विभागीय गवाहान के बयान के लिए तारीख निश्चित की गई थी व उस रोज बचाव प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था किन्तु इसके बावजूद बिना कोई कारण दर्ज किए जांच अधिकारी द्वारा विभागीय गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इससे पूर्व 16-6-88 को किसी भी पक्ष के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे व जांच अधिकारी ने स्थगन स्वीकृत कर दिया था। पुनः 12-10-88 को भी स्वयं आरोपित उपस्थित था व इसके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। आदेशिका में यह उल्लेख है कि उस रोज बचाव प्रतिनिधि ने तारीख बदलने के लिए तार दिया था जो जांच अधिकारी को प्राप्त भी हो गया था किन्तु इसके बावजूद जांच अधिकारी ने स्थगन स्वीकृत करना उचित नहीं समझा। कोई भी स्पष्ट कारण जांच प्रतिनिधि के अनुरोध को अस्वीकार करने का उल्लिखित नहीं किया गया है। इस प्रकार दोनों आदेशिकाओं के पठन से यह स्पष्ट है कि बचाव प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में आरोपित के अनुरोध के बावजूद जांच अधिकारी द्वारा गवाहान के बयान दर्ज किए गए थे व बचाव प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के संबंध में प्रार्थना स्वीकार करने के संबंध में कोई भी स्पष्ट व उचित कारण आदेशिका में दर्ज नहीं किए गए हैं। नैसर्गिक न्याय का यह सिद्धान्त है कि जहां जांच कार्यवाही के बचाव प्रतिनिधि की नियुक्ति की गई हो वहां बिना किसी विशेष कारण के जांच कार्यवाही में बचाव प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में साक्ष्य नहीं ली जानी चाहिए व यदि प्रतिनिधि द्वारा अनुपस्थिति के बाबत

अनुरोध किया जाता है तो न्याय हित में उचित समय प्रदान किया जाना चाहिए । यह सही है कि आंशिक रूप से जांच कार्यवाही को लंबित अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता किन्तु इसके विपरीत श्रमिक के हितों को देखते हुए तर्क संगत कारणों पर उचित स्थगन स्वीकृत किया जाना भी आवश्यक है । नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने आदेशिकाओं के आधार पर या अन्य किसी कारण पर यह न्यायाधिकरण की सन्तुष्टि नहीं की है कि जांच अधिकारी ने बचाव प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में जो बयान दर्ज किया है व कार्यवाही उचित है तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जांच अधिकारी द्वारा बचाव प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में बयान लेने की जो कार्यवाही की गई है वह सही नहीं है व इस आधार पर जांच कार्यवाही को उचित नहीं माना जा सकता।

8. श्रमिक की ओर से एक बहस वैधानिक रूप से यह की गई है कि अनुशासनिक अधिकारी ने दण्डादेश का जो आदेश पारित किया है वह कारण सहित (स्पीकिंग आर्डर) नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है । यह आदेश 23-1-89 का है जिसके जरिये सचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव किया गया था। आदेश के पठन से यह स्पष्ट है कि उसमें न तो यह उल्लेख है कि श्रमिक के विरुद्ध आरोप लगाया है, न ही यह उल्लेख है कि जांच अधिकारी ने किन आरोपों को प्रमाणित माना है व न ही यह उल्लेख है कि प्रमाणित माने गये आरोपों के लिए क्या साक्ष्य व परिस्थितियां उपलब्ध हैं। मात्र यह लिखा गया है कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट व दस्तावेज एवं गवाहों के आधार पर दुराचरण का आरोप साबित माना जाता है। श्रमिक के विरुद्ध कुल तीन आरोप जांच कार्यवाही में लगाये गये थे। इनमें से प्रथम आरोप की जांच अधिकारी ने साबित माना है व दूसरे आरोप के लिए यह लिखा है कि साक्ष्य से साबित नहीं होता है। तीसरे आरोप के संबंध में आंशिक रूप से आरोप साबित मानते हुए यह लिखा गया है कि श्रमिक 20-7-87 को अवैधानिक हड़ताल पर रहा किन्तु यह सिद्ध नहीं माना गया है कि उसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति के संबंध में नारेबाजी की गई हो। इस प्रकार जांच अधिकारी ने साक्ष्य के आधार पर एक आरोप को प्रमाणित, एक को अप्रमाणित व एक को आंशिक रूप से प्रमाणित माना है। अनुशासनिक अधिकारी ने परिशिष्ट 6 आदेश में यह भी नहीं लिखा है कि जांच अधिकारी का आरोपों के संबंध में क्या विनिश्चय है। परिशिष्ट-6 आदेश के संबंध में श्रमिक का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् मात्र प्रस्तावित दण्डादेश की पुष्टि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा की गई है व उसमें भी अलग से कोई कारण उल्लिखित नहीं किया गया है। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने इन तथ्यों को देखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दो निर्णय सिद्धाराम बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 1992 (1) पेज 352 व राजस्थान राज्य बनाम श्रमोलक चंद आर.एल.आर. 1983 पेज 246 को संदर्भित किया है। दूसरे संदर्भित निर्णय में जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती अधीन था उसमें भी कर्मचारी के दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड दिया गया है। इन विधि दृष्टान्तों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उनको देखते हुए किसी भी रूप में 23-1-89 के अनुशासनिक अधिकारी के आदेश को सकारण पारित किया हुआ नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में उस आदेश को अपास्त करना पूर्ण रूप से वैधानिक है।

9. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने यह बहस की थी कि जांच अधिकारी ने पूर्ण रूप से आंशिक रूप से जिन आरोपों को साबित माना है उनका यह विनिश्चय उचित नहीं है क्योंकि इसका कोई भी आधार उपलब्ध साक्ष्य से नहीं बनता। उनका यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जांच प्रतिवेदन में उपलब्ध साक्ष्य पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है व यह स्थिति नहीं बनती कि जिन आरोपों को पूर्ण रूप से व आंशिक रूप से जांच अधिकारी ने साबित माना है उनके लिए कोई भी वैधानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अथवा उपलब्ध साक्ष्य से इस प्रकार का विनिश्चय किसी भी स्थिति में निकालना संभव नहीं हो। जांच अधिकारी द्वारा अपने विवेक का उपयोग करते हुए साक्ष्य का जिस प्रकार से विवेचन किया गया है उसको गलत या अतार्किक नहीं माना जा सकता। एक गवाह दिलीप कुमार को विभागीय गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है किन्तु उसकी साक्ष्य के बिना भी जो अन्य गवाह उपस्थित हुए हैं उनसे जांच अधिकारी ने आरोपों को साबित मानने का जो विनिश्चय किया है वह अनुचित नहीं है। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने विशिष्ठ रूप से साक्ष्य व परिस्थितियों का विश्लेषण करके यह बताने का प्रयास नहीं किया है कि जांच अधिकारी का विनिश्चय किस प्रकार अनुचित है।

10. नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने प्रस्तुत जवाब के आधार पर यह बहस की है कि यदि किसी कारण न्यायाधिकरण जांच कार्यवाही को उचित नहीं माने तो श्रमिक के विरुद्ध दुराचरण का आरोप साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे। इस प्रार्थना का श्रमिक की ओर से इस आधार पर विरोध किया गया है कि धारा 11-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम व इससे पूर्व धारा 10 औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत जो सिद्धान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं उनसे कहीं भी यह प्रकट नहीं होता कि सेवा मुक्ति के मामले के अलावा अन्य मामलों में भी नियोजक को दुराचरण के संबंध में नियोजक को न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित नहीं है। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वविदित फायरस्टोन के मामले को संदर्भित किया है व नियोजक की ओर से ऐसा कोई विधि दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया हो कि वर्तमान मामले में यदि जांच कार्यवाही को अनुचित माना जावे तो नियोजक को न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य

प्रस्तुत करने का अवसर वैधानिक रूप से दिया जा सकता है। इसके अलावा एक तथ्य यह भी विचारणीय है कि जांच कार्यवाही को अनुचित मानने के अलावा आक्षेपित दण्डादेश का इस आधार पर भी गलत माना गया है कि अनुशासनिक अधिकारी का आदेश कारण सहित नहीं है व उस स्थिति में जांच कार्यवाही को अनुचित मानने का आधार नहीं होता व किसी भी रूप में नियोजक को ऐसी परिस्थिति में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जा सकता। यदि अनुशासनिक अधिकारी का आदेश कारण सहित नहीं है तो उस स्थिति में आक्षेपित दण्डादेश को कायम नहीं रखा जा सकता।

11. श्रमिक की ओर से एक वैधानिक बहस यह की गई है कि द्विपक्षीय समझौते के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही के जो प्रावधान बनाये गये हैं उनके अनुसार अध्याय 22 के नियम 6(डी) में मात्र वेतन वृद्धि रोकने का प्रावधान है तथा संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने का कोई भी नियम नहीं है इसलिए जो संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने का दण्डादेश अनुशासनिक अधिकारी द्वारा पारित किया गया है वह अवैधानिक है। इस संबंध में अलकेन्द्र कुमार सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एस.एल.आर. 1981 पेज 33 का अवलम्ब लिया गया है। चूंकि श्रमिक के विरुद्ध पारित दण्डादेश की कार्यवाही को अन्य आधारों पर अनुचित माना गया है इसलिए इस विधिक बिन्दु पर विवेचन किया जाकर अलग से राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

12. जांच कार्यवाही से संबंधित तथ्यों व विधिक स्थिति के विवेचन के परिणामस्वरूप विवाद में अतिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, भरतपुर द्वारा श्रमिक बाबूलाल के विरुद्ध दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का पारित दण्डादेश अनुचित व अवैधानिक है जिसे अपास्त किया जाता है व इसके फलस्वरूप श्रमिक समस्त सुसंगत परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

13. अवार्ड आज दिनांक 22-8-94 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

के.एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1994

का.आ. 138.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-12-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-17011/12/90-आई.आर.बी.-2]
वी.के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th December, 1994

S.O. 138.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of United India Insurance Company Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 23-12-94.

[No. L-17011/12/90-IR(B-II)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 2/1991

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-17011/12/90 आई.आर. (बी-2) दिनांक 11-12-90

श्री शांति लाल बोहरा, डैवलपमेन्ट ऑफिसर, यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि.।

—प्रार्थी

बनाम

यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि.।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के.एल. व्यास, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से :	श्री जे.एल. शाह
विपक्षी की ओर से :	श्री एस.के. सिंघल
दिनांक अवार्ड :	26-7-1994

अवार्ड

विभागीय जांच के पश्चात श्री शांति लाल बोहरा, विकास अधिकारी, यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. की सेवाएं कम्पनी द्वारा दिनांक 23-6-87 के आदेश सं जे आर ओ. पी ई आर 911 : 87 से समाप्त की गई। इस आदेश से व्यथित होकर श्रमिक द्वारा समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद रखा गया तथा वहां वार्ता सफल न होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न विवाद अधिनिर्णय हेतु प्रेषित किया गया है :

"Whether the action of the management of United India Insurance Co. Ltd. in terminating the services of the Shanti Lal Bohra, Development Officer at their Banswara Branch vide office Order No. JRO : Per : 911:87 dated 23-6-87 is just and legal ? If not, to what relief is the worker concerned entitled and from what date ?"

2. क्लेम में श्रमिक ने यह बताया है कि उसकी नियुक्ति दिनांक 8-9-77 को निरीक्षक के पद पर (वर्तमान में विकास अधिकारी, सहायक महाप्रबन्धक यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी) (जिसे बाद में कम्पनी संबोधित किया जायेगा) नई दिल्ली द्वारा की गई थी व तब से श्रमिक ने निरन्तर निष्ठापूर्वक अपने पद का कार्य किया था। श्रमिक का कथन यह है कि जुलाई 1985 से 1987 के मध्य उसकी माता गंभीर रूप से बीमार थी जिनकी सेवा सुश्रुषा में श्रमिक लग गया व इस कारण उसके द्वारा जुलाई 1985 से सितम्बर 1986 के मध्य कवर नोट के जरिये 13,377/रुपये की राशि विभिन्न ग्राहकों से वसूल की गई थी जो समय पर कम्पनी में जमा नहीं कराई जा सकी। 14-8-86 को श्रमिक ने लिखित प्रार्थना पत्र के जरिये उक्त राशि कम्पनी में जमा कराने का अनुरोध किया जिसके संबंधि में 4-9-86 के पत्र से कम्पनी द्वारा स्वीकृति दी गई व 16-9-86 व 27-9-86 को यह राशि श्रमिक ने कम्पनी में जमा करवाई थी। इसके बावजूद 10-12 86 को एक आरोप पत्र दुराचरण के संबंध में कम्पनी द्वारा श्रमिक को जारी किया गया। इस जांच में श्रमिक को अपना पक्ष सही रूप से प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया व दोषारोपण पत्र के संबंध में जो जवाब श्रमिक ने दिया उसमें उसके द्वारा अपनी परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करते हुए यह निवेदन किया गया कि कोई भी दुराचरण का आरोप नहीं बनता। विभागीय जांच पूरी करने के पश्चात श्रमिक को कम्पनी द्वारा सेवा मुक्त किया गया जो इसलिए अवैधानिक है क्योंकि जांच कार्यवाही निष्पक्ष रूप से सम्पन्न नहीं की गई, जो साक्ष्य जांच में प्रस्तुत हुई उससे कोई भी दुराचरण का आरोप साबित नहीं होता, श्रमिक को अपनी प्रति रक्षा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया तथा 23-6-87 के पश्चात भी श्रमिक ने 30-4-88 तक कम्पनी में कार्य किया इसलिए आक्षेपित सेवा मुक्ति का आदेश स्वतः ही निरस्त हो गया। यह भी अभिकथित किया गया है कि यदि दुराचरण के आरोप को साबित माना जावे तो भी श्रमिक को जो दण्ड दिया गया है व अत्यधिक व आरोप की प्रकृति को देखते हुए गैर आनुपातिक है।

3. नियोजक की ओर से जवाब में श्रमिक की नियुक्ति तिथि को स्वीकार किया गया है किन्तु इस तथ्य को अस्वीकार किया गया है कि जुलाई 1985 से 1987 के मध्य तक श्रमिक की माता बीमार थी व यह भी कहा गया है कि इस तथ्य का श्रमिक के क्लेम से कोई भी संबंध नहीं है। नियोजक के अनुसार 13,377/- रुपये लंबे समय तक कम्पनी में जमा नहीं कराने का कोई भी संतोषजनक व मानने योग्य कारण श्रमिक द्वारा क्लेम में या विभागीय जांच में नहीं बताया गया है। नियोजक के अनुसार इस राशि का गलत उपयोग श्रमिक ने लम्बे समय तक अपने पास रखकर किया है इसलिए कम्पनी के आचरण, अनुशासनिक व अपील नियम 1975 के नियम 3(1)(1) व नियम 4(1), 4(5) के तहत दुराचरण का आरोप बनता है। नियोजक के अनुसार चूंकि श्रमिक के विरुद्ध नैतिक अवपतन व बेईमानी का आरोप साबित है इसलिए उसके खिलाफ जो भी सेवामुक्ति का आदेश पारित किया गया है वह उचित, न्यायसंगत व वैधानिक है। जांच कार्यवाही के संबंध में पद सं. 7 में विस्तृत तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि जांच कार्यवाही सम्पूर्ण रूप से नियमानुसार व उचित प्रक्रिया से की गई है। श्रमिक द्वारा सेवा मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील भी प्रस्तुत की गई थी जो अस्वीकार करने का उचित कारण जवाब में बताया गया है। 23-1-87 के पश्चात श्रमिक ने कम्पनी में किसी भी रूप में कार्य किया हो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से नियोजक द्वारा अस्वीकार किया गया है।

4. नियोजक की ओर से विभागीय जांच का सम्पूर्ण अभिलेख न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है व इसके अलावा भी दोनों पक्ष की ओर से कुछ प्रलेख की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है।

5. प्रारंभ में घरेलू जांच की निष्पक्षता व औचित्यता बाबत बहस के लिए स्थगन किया गया था। 29-3-94 को श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने अभिलेख को देखते हुए यह स्वीकार किया कि श्रमिक के विरुद्ध जो जांच की गई है वह सही व उचित है व इस प्रकार इस बिन्दु का विनिश्चय श्रमिक के विरुद्ध किया हुआ है।

6. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने जांच की निष्पक्षता के अलावा यह बहस की है कि जो परिस्थितियों श्रमिक द्वारा देरी से रकम जमा कराने बाबत बताई गई हैं उनको व अन्य परिस्थितियों को देखते हुए तथा कम्पनी द्वारा बनाये गये नियमों में दुराचरण की जो परिभाषा है उसके अनुसार कोई भी दुराचरण का आरोप श्रमिक के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है व इसके अलावा विकल्प में यह बहस की गई है कि यदि कोई भी दुराचरण का आरोप साबित माना जावे तो धारा 11-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के लिए यह न्यायोचित है कि श्रमिक के विरुद्ध पारित किये गये दण्डादेश में कमी करके उसे पुनः सेवा में रखने का आदेश प्रदान करें। उनके अनुसार सेवा मुक्ति का आदेश परिस्थितियों को देखते हुए अनुचित, अवैधानिक व गैर आनुपातिक है। दोनों तर्क जो श्रमिक की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं उन पर क्रमशः विचार किया जायेगा।

7. कंपनी द्वारा जो आचरण, अनुशासन व अपील नियम 1975 बनाये गये हैं उनके नियम 3(1)(1) व नियम 4(1) व 4(5) के तहत दोषारोपण पत्र श्रमिक को जारी किया गया है। निर्विवाद तथ्य जिन पर विवाद आधारित है वे इस प्रकार हैं कि श्रमिक द्वारा करीब 18 माह की अवधि तक 13,377 रुपये की राशि जो कवर नोट के जरिये ग्राहकों से वसूल की गई थी वे कंपनी के खाते में जमा नहीं कराये गये व आरोपों को जो विस्तृत विवरण लिखित में श्रमिक को दिया गया है उसमें इन्हीं तथ्यों का उल्लेख है। देखना यह

है कि इन तथ्यों से नियम 3(1) (1), 4(1) व 4(5) के तहत आरोप लगाने का कोई भी आधार बिन्दु है अथवा नहीं। नियम 3(1)(1) में यह प्रावधान है कि हर कर्मचारी द्वारा पूर्व मंजूर कार्य के संबंध में रखी जावेगी । नियम 4(1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कर्मचारी द्वारा कम्पनी के व्यापार व समिति के संबंध में धोखा, चोरी या बेईमानी का कोई कृत्य नहीं किया जायेगा व नियम 4(5) के प्रावधान के अनुसार कर्मचारी द्वारा ऐसा कोई नहीं किया जायेगा जिससे कम्पनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो । नियम 3(1)(1), 4(1) व 4(5) में जो दुराचरण की परिभाषा दी गई है उनके तहत श्रमिक का कथित कृत्य शामिल होता है इस बात पर भी कोई विवाद मानने योग्य नहीं है । बीमा अधिनियम में यह प्रावधान है कि बीमा ऐजेण्ट द्वारा जो भी राशि वसूल की जायेगी वह 24 घंटे के भीतर कंपनी में जमा कराई जायेगी । इस प्रावधान के अनुसार निश्चित रूप से यह जिम्मेदारी श्रमिक की थी कि उसके द्वारा 13,377 रुपये में से जितनी जितनी राशि जिस समय कवर नोट के जरिये वसूल की गई वह अगले दिन या उस रोज संभव नहीं होने की स्थिति में उसके बाद के कार्य दिवस को कंपनी में जमा कराई जाती । समय पर रकम जमा नहीं कराने का जो तथ्य आरोप पत्र में वर्णित है व जिसको जांच में प्रमाणित माना गया है उनको देखते हुए यह मानना उचित है कि श्रमिक द्वारा इस रकम को समय पर जमा नहीं कराने के कारण अपने कर्तव्य का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ नहीं किया गया था । इसी प्रकार नियम 4(1) व 4(5) में जो दुराचरण की परिभाषा दी गई है उसके तहत भी श्रमिक का कार्य आता है क्योंकि समय पर कंपनी में रकम जमा नहीं कराने से निश्चित रूप से कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा लम्बे समय तक बिना कारण कंपनी की रकम को अपने पास रखने से श्रमिक का कार्य इस रकम के प्रति बेईमानी का प्रतीक माना जाना चाहिये । आरोप जो श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये हैं उसमें यह उल्लेख है कि उसने समय पर रकम जमा नहीं कराई तथा इस प्रकार उसके द्वारा इस रकम का दूसरे कार्य के लिए दुरुपयोग किया गया। आरोप पत्र के साथ जो तथ्यों का विवरण दिया गया है उसमें भी 4—8—86 तक श्रमिक द्वारा 13,377 रुपये की रकम जमा नहीं कराने का विवरण है व इस प्रकार नियम 3(1)(1) व नियम 4(1) व 4(5) के तहत दुराचरण करने का आरोप लगाया गया है । जो तथ्य दोषारोपण पत्र आरोपों के विवरण के संबंध में उल्लिखित किय गये हैं व जिन पर कोई भी विवाद नहीं है उनको देखते हुए यह मानने का आधार नहीं है कि श्रमिक के खिलाफ इन तथ्यों से दुराचरण का कोई भी आरोप साबित नहीं होता है । श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी बहस में इस बात पर गंभीरता से बहस नहीं की है कि जांच कार्यवाही में श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये आरोप तथ्यात्मक रूप से साबित नहीं होते हैं । इसके अलावा भी जो प्रलेख नियोजक की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं उन पर सरसरी तौर से विचार किया जाना अपेक्षित है । श्रमिक ने दिनांक 4—8—86 को एक लिखित आवेदन नियोजक को दिया था जिसमें यह माना गया कि 13,377 रुपये की रकम उसने समय पर जमा नहीं कराई थी तथा यह रकम जमा कराने की अनुमति प्राथना पत्र के माध्यम से मांगी गई थी। इसके पश्चात सितम्बर 1986 में दो किश्तों में यह रकम श्रमिक द्वारा जमा कराई गई है जैसा कि उसके स्वयं के पत्र दिनांक 20—1—87 से साबित होता है । इस पत्र में भी श्रमिक ने यह माना है कि उक्त रकम लम्बे समय तक उसके पास रही है व इस प्रकार उसने गलती की है किन्तु उसका कोई भी आशय इस रकम को लम्बे समय तक अपने पास रखने का नहीं था । जांच अधिकारी के समक्ष श्रमिक ने 21-4-87 को बिना किसी शर्त यह लिखकर दिया है कि वह दोषारोपण पत्र में लगाये गये आरोप को स्वीकार करता है। इसी के आधार पर मौखिक साक्ष्य जांच अधिकारी द्वारा लेखबद्ध नहीं की गई व श्रमिक को दोषी मानने का प्रतिवेदन नियोजक को प्रस्तुत किया गया। श्रमिक ने अपने क्लेम में जो यह प्रतिरक्षा ली है कि वह अपनी माता की बीमारी के कारण अनियंत्रित कारणों से समय पर रकम जमा नहीं करा सका वह प्रतिरक्षा उसने नियोजक के समक्ष किसी भी प्रक्रम पर नहीं ली थी, न ही जांच कार्यवाही में इस प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत की थी । इस निर्देश में भी श्रमिक ने इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है । ऐसी स्थिति में क्लेम में जो उसका कथन है कि रकम समय पर जमा नहीं कराने का न्यायोचित कारण था वह न तो जांच अधिकारी ने माना है व न ही न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार करने का कोई आधार है । निष्कर्ष यह है कि उपलब्ध प्रालेखीय साक्ष्य व जांच कार्यवाही से यह प्रमाणित है कि श्रमिक द्वारा 13,377 रुपये की रकम विलम्ब से कंपनी में जमा कराई गई थी । जो प्रलेख पेश हुए हैं उनके अनुसार इस कुल रकम में से सर्वप्रथम 18—7—85 को संग्रहित की गई 415 रुपये व सबसे बाद की रकम 19—5—86 को 128 रुपये रुपये की थी । कुल राशि 13,377—रुपये सितम्बर 1986 में श्रमिक द्वारा जमा कराये गये हैं । इस प्रकार न्यूनतम चार माह व अधिकतम 14 माह के विलम्ब से अलग अलग वसूल की गई राशि श्रमिक द्वारा कंपनी में जमा कराई गई है । उपलब्ध साक्ष्य व परिस्थितियों का निष्कर्ष यह है कि श्रमिक के विरुद्ध जो दोषारोपण किये गये हैं उनके अनुसार नियम 3(1)(1), 4(1) व 4(5) के तहत श्रमिक के खिलाफ दुराचरण के आरोप साबित होते हैं।

8. अगला विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या यह ऐसा मामला है जिसमें धारा 11—ए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करके सेवा मुक्ति के आदेश में कमी को जाकर अन्य लघु दण्ड से श्रमिक को दण्डित किया जाना अपेक्षित न न्यायोचित हो । धारा 11—ए अधिनियम में न्यायाधिकरण को इस संबंध में सीमित क्षेत्राधिकार दिया हुआ है व उसके अनुसार यदि न्यायाधिकरण की सन्तुष्टि इस बाबत हो कि श्रमिक के विरुद्ध पारित दण्डादेश न्यायोचित नहीं है तो उसी स्थिति में आक्षेपित दण्डादेश में परिवर्तन करके कमी की जा सकती

है । न्यायालय की सन्तुष्टि इस संबंध में किन तथ्यों व परिस्थितियों से हो सकती है इस प्रकार के सिद्धान्त विभिन्न निर्णयों में निर्विवाद रूप से प्रतिपादित किये गये हैं । न्यायाधिकरण की सन्तुष्टि किसी भी मामले में विषय परख नहीं हो सकती है व वस्तु परखता के आधार पर ही धारा 11-ए अधिनियम के अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 7079/93 भागीरथमल रैणवा बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर निर्णय दिनांक 21-2-94 में इस संबंध में जो सिद्धान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् प्रतिपादित किए गए हैं वे निम्न प्रकार है :

'However, power under Section 11-A can be exercised only on fulfillment of the conditions enumerated in that Section, namely that the Labour Court/Tribunal or the National Tribunal must be satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified. However, conferment of wide power on the labour court/tribunal or National tribunal to stt aside the order of discharge or dismissal does not mean that in each case and every case the labour Court/Tribunal or National Tribunal has got untrammelled power to interfere with the punishment imposed by the employer. The power has to be exercised only after the Labour Court/Tribunal or National Tribunal is satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified. The satisfaction of the Labour Court, Tribunal or the National Tribunal is not a subjective satisfaction but clearly an objective satisfaction. This obviously involves application of mind by the Labour Court, Tribunal or National Tribunal on various relevant circumstances, like the nature of delinquency committed by the workman his past conduct, the impact of the delinquency on the employer's business/industry as also the total length of service rendered by the workman. That apart, the Labour Court, Tribunal or National Tribunal is required to consider as to whether the decision taken by the management is just or not. Only after due consideration of these factors, the labour court, Tribunal or National Tribunal can upheld the punishment imposed by the employer, Interference cannot be done by the Labour Court, Tribunal or National Tribunal with the quantum of punishment without recording a specific finding in the manner aforesaid and after consideration of the material circumstances.

9. उक्त विधि दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्तों व इस प्रकरण के तथ्यों व सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए न्यायाधिकरण को यह सन्तुष्टि होना संभव नहीं है कि श्रमिक के विरुद्ध सेवा मुक्ति का जो आदेश दिया गया है वह न्यायोचित नहीं है अथवा अत्याधिक है । जहाँ किसी भी कर्मचारी की नैतिकता दुराचरण के संबंध में निहित हो उस प्रकार के मामले में नर्म कार्यवाही करके सेवा मुक्ति के आदेश को अपास्त किया जाना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता ।

10. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने श्रमिक के खिलाफ नम्र कार्यवाही करने के लिए 1979 एल. आई. सी. (एस.सी.) 1043 का अवलम्ब अपनी बहस में लिया है । संदर्भित मामले में श्रमिकगण के खिलाफ कोई भी आरोप पत्र बेईमानी या नैतिकता के संबंध में नहीं लगाया गया था व मात्र फैक्ट्री परिसर में नारेबाजी करने, हैण्डबिल व पैम्फलेट वितरित करने के कथित तथ्यों के आधार पर दुराचरण का आरोप लगाया गया था व इस कारण उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर श्रमिक को कोई भी अनुतोष दिया जाना वांछित नहीं है ।

11. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने बहस में एक तर्क यह दिया है कि कम्पनी द्वारा इसी प्रकार के मामले में सर्वश्री उमेश द्विवेदी व धर्मेन्द्र नानावटी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किये गये थे व जाँच में उनको दोषी पाये जाने के बावजूद उनके खिलाफ पदावनति व वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिये गये थे जबकि श्रमिक के विरुद्ध उन्हीं तथ्यों पर सेवा मुक्ति का आदेश दिया गया है जो भेदभाव की नीति का प्रतीक है इसलिए भी उनके अनुसार सेवा मुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित है । सर्वश्री उमेश द्विवेदी व धर्मेन्द्र नानावटी की जांच के संबंध में जो प्रलेख पत्रावली पर प्रस्तुत हुए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि उनके खिलाफ आरोप पत्र में वर्णित तथ्य श्रमिक के आरोप पत्र के तथ्यों से किसी भी रूप में सामानान्तर नहीं थे। इसके अलावा तर्क के लिए यदि यह भी माना जावे कि नियोजक ने इसी प्रकार के मामले में अन्य श्रमिकों के विरुद्ध सेवा मुक्ति से भिन्न दण्डादेश पारित किया है तो भी इसी आधार पर श्रमिक को कोई भी अनुतोष नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह यह साबित न करें कि उसके विरुद्ध सेवा मुक्ति का आदेश मात्र उसे उत्पीड़ित करने के लिए पारित किया गया है । अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के प्रावधान इस प्रकार के मामलों में लागू नहीं होते हैं । नियोजक के खिलाफ उत्पीड़न के सिद्धान्तों के परिणामस्वरूप सेवा मुक्ति का आदेश पारित करने का कोई भी कथन क्लेम में श्रमिक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है व न ही इस प्रकार की साक्ष्य या परिस्थितियां उपलब्ध हैं ।

12. श्रमिक की ओर से एक बहस यह की गई है कि 13,377 रुपये की कुल राशि में से कुछ रकम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में वसूल की गई थी जिनका निजी उपयोग श्रमिक द्वारा किया जाना संभव नहीं था व इसलिए दुरुपयोग की जाने वाली रकम वास्तव में 13,377 रुपये से कम है व इस प्रकार भी आरोपों की गंभीरता में कमी होती है । उन्होंने इस संबंध में 14-8-76 का स्वयं श्रमिक का लिखा हुआ एक पत्र बहस के समय प्रस्तुत किया है उसके पठन से यह स्पष्ट है कि क्रमांक 22 तक कुल 13,377 रुपये वसूल करने का इस पत्र में उल्लेख है व डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जो राशि वसूल की गई है क्रम सं. 23 व 24 पर उल्लिखित है व उनका योग कुल 96 रुपये होता है । इसलिए श्रमिक की ओर से प्रस्तुत किये गये उक्त तर्क में भी कोई सार

प्रकट नहीं होता है । अन्य कोई भी विधिक या तथ्यात्म बहस किसी भी पक्ष की ओर से नहीं की गई है ।

13. उपलब्ध तथ्यों व विधिक स्थिति के विवेचन के परिणामस्वरूप निर्देशित विवाद में अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि श्रमिक शांति लाल बोहरा के खिलाफ नियोजक युनाईटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी द्वारा दिनांक 22-6-77 को पारित सेवा मुक्ति आदेश न्यायोचित व वैध है व इस कारण श्रमिक कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

14. अवार्ड आज दिनांक 26-7-1994 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

के.एल. व्यास, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1994

का.आ. 139:— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनाईटेड कामर्शियल बैंक जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-12-94 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/661/87-डी. 2 (ए)/आई.आर (बी.2)
वी.के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th December, 1994

S.O. 139.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of United Commercial Bank, Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on 23-12-94.

[No. L-12012/661/87-D.IIA/IR(B-II)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 45/88

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-12012/661/87-डी 2 (ए) दि. 14-7-88

एन.के. शर्मा, मार्फत महासचिव, यूको बैंक स्टाफ एसोसियेशन द्वारा यूको बैंक, बी.डी. रोड, जयपुर ।
—प्रार्थी

बनाम

जोनल मैनेजर, यूको बैंक, जोनल कार्यालय, ए-30 (बी) शास्त्री नगर, जयपुर ।
—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के.एल. व्यास, आर.एच.जे.एस

प्रार्थी की ओर से : श्री बी.एम. बागड़ा
अप्रार्थी की ओर से : श्री मान सिंह गुप्ता
दिनांक अवार्ड : 18-8-1994

अवार्ड

केन्द्र सरकार द्वारा अधिनिर्णय हेतु निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को निर्देशित किया गया है :

"क्या यूको बैंक, जयपुर के प्रबन्धतंत्र की 9-4-87 के श्री एन.के. शर्मा की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

2. क्लेम के अनुसार श्रमिक का कथन यह है कि उसको नियुक्ति विपक्षी यूको बैंक, एम.आई.रोड शाखा, जयपुर में 18-1-85 को स्थाई रूप से रिक्त पद पर की गई थी व प्रारंभ में उसे प्रतिदिन 10 रुपये, फिर 13 रुपये व बाद में 15 रुपये दैनिक वेतन अदा किया गया । श्रमिक ने 9-4-87 तक इस प्रकार से बैंक की उक्त शाखा में कार्य किया व इसके पश्चात उसकी सेवाएं बिना कारण व बिना धारा 25-एफ, जी, एच अधिनियम की पालना किये समाप्त की गई । श्रमिक के अनुसार नियोजक का यह कार्य श्रम विरोधी व शोषण की परिभाषा में आता है । अनुतोष यह मांगा गया है कि सेवा मुक्ति की तिथि से पुनः श्रमिक को सम्पूर्ण बकाया वेतन एवं लाभ सहित नौकरी में रखने का आदेश दिया जावे । नियोजक की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अभिकथन किया गया है कि श्रमिक को 18-1-85 को अथवा कभी भी किसी स्थाई जगह के विरुद्ध कोई नियुक्ति नहीं दी गई तथा आवश्यकतानुसार अंशकालीन कार्य के लिए उसे दैनिक वेतन पर शाखा मैनेजर द्वारा नियुक्त किया गया था व पूरी अवधि में उसने 240 दिन से अधिक कार्य नहीं किया । जिस अवधि में श्रमिक को नियुक्त किया गया उस बीच उसने नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य नहीं किया बल्कि उससे शाखा का विधि कार्य आवश्यकतानुसार लिया गया था । इसमें पानी भरना व अन्य कार्य भी शामिल थे । श्रमिक को प्रतिदिन का वेतन भी अंशकालिक व आकस्मिक कार्य के आधार पर किया गया था । धारा 25-एफ, जी व एच औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की पालना नियोजक द्वारा नहीं करना स्वीकार किया गया है परन्तु यह अभिकथित किया गया है कि श्रमिक के मामले में इस प्रकार के प्रावधान की पालना करना किसी भी रूप में आवश्यक नहीं था । उनका यह भी कथन है कि बैंक में स्थाई जगह होने पर नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किये जाते हैं व निर्धारित योग्यता के अनुसार परीक्षा व साक्षात्कार के पश्चात ही नियुक्ति की जाती है किन्तु श्रमिक के मामले में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी । अतिरिक्त कथन में यह बताया गया है कि श्रमिक की नियुक्ति मात्र एक घण्टे कार्य के लिए

की गई थी इस कारण व किसी भी रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत श्रमिक की परिभाषा में नहीं आता है । चूंकि श्रमिक ने अंशकालीन रूप से विशिष्ट कार्य के लिए बैंक में कार्य किया था इस कारण उसे नियमित नियुक्ति देने का कोई नियम या औचित्य नहीं है ।

3. दोनों पक्षों की ओर से संबंधित प्रलेख की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं व मौखिक साक्ष्य के रूप में श्रमिक ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा नियोजक की ओर से एक गवाह श्री गोपीचन्द का शपथ पत्र प्रस्तुत किया किया गया है । बहस दोनों पक्षों की सुनी गई तथा उपलब्ध साक्ष्य, प्रलेख व दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत विधि वृष्टान्तों पर विचार किया गया ।

4. दोनों पक्षों के अभिकथनों को देखते हुए विनिश्चय हेतु प्रकरण में निम्न बिन्दु बनाये जाते हैं :

1. आया श्रमिक द्वारा बैंक की एम.आई. रोड शाखा जयपुर में 240 दिन से अधिक कार्य किया गया व किस रूप में किया गया ?

2. आया नियोजक द्वारा श्रमिक के मामले में धारा 25 एफ जी व एच की पालना नहीं करने का क्या प्रभाव है ?

5. श्रमिक नरेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने शपथ पत्र में क्लेम के तथ्यों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि उसे शाखा प्रबन्धक द्वारा 18-1-85 को रिक्त स्थाई पद पर नियुक्त किया गया व इस रूप में उसने 8-4-87 तक बैंक में दैनिक वेतन पर कार्य किया । उसने यह भी बताया है कि बैंक का यह कहना गलत है कि श्रमिक को आकस्मिक रूप से अथवा अंशकालीन रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था । उसका यह भी कथन है कि नियोजन की अवधि में उसने वह सारा कार्य किया था जो एक नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कराया जाता है, नियमित रूप से उपस्थिति रजिस्टर में स्वयं द्वारा हाजिरी दर्ज करना व वाउचर के जरिये भुगतान प्राप्त करना भी श्रमिक ने बताया है । शपथ पत्र के पद सं. 6 में विस्तृत विवेचन देते हुए यह बताया गया है कि 18-1-85 से 8-4-87 तक श्रमिक ने कुल 610 दिन उक्त शाखा में कार्य किया था । इस संबंध में शाखा मैनेजर द्वारा 17-10-86 तक का प्रमाण-पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-4 दिया गया था जिसमें यह उल्लेख है कि श्रमिक ने 17-10-86 तक बैंक की शाखा में 420 दिन कार्य किया था । इसके पश्चात् भी श्रमिक के कथनानुसार उसे 8-7-87 तक बैंक में कार्य किया था । श्रमिक की ओर से बैंक में रखे गये उपस्थिति रजिस्टर व भुगतान वाउचर्स तलब करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके संबंध में बैंक की ओर से 21-12-91 को श्री के.के. मोदी का एक शपथ पत्र व कुछ वाउचर्स की फोटो प्रतियां प्रस्तुत करते हुए यह बताया गया कि इसके अलावा कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सकता । शपथ पत्र में यह अंकित नहीं किया गया है कि इसके अलावा अन्य वाउचर्स या अन्य रिकार्ड बैंक द्वारा तैयार नहीं किए गए थे । जो वाउचर्स श्रमिक को भुगतान बाबत प्रस्तुत किये गये हैं वे 3-10-86 से 20-3-87 के बीच के हैं । इनसे भी श्रमिक के कथन की पुष्टि होती है कि उसने मार्च 1987 तक बैंक में दैनिक वेतन पर कार्य किया था ।

6. उक्त तथ्यों के संदर्भ में जो जिरह श्रमिक से की गई है उसमें उसने यह बताया है कि प्रदर्श डब्ल्यू-4 प्रमाण-पत्र श्री के.एल. बंसल तत्कालीन शाखा प्रबन्धक द्वारा जारी किये गये थे जिसके अनुसार उसने 420 दिन तक बैंक में कार्य किया था । इसके अतिरिक्त श्रमिक की नियुक्ति की अवधि व उसके कार्य की प्रकृति के संबंध में कोई भी जिरह नहीं की गई है । इस साक्ष्य के खिलाफ नियोजक की ओर से श्री गोपी चन्द गवाह ने शपथ पत्र में यह बताया है कि श्रमिक ने 12-1-86 से 9-4-87 के बीच मात्र 99 दिन बैंक में कार्य किया था तथा किसी भी वर्ष में उसने 240 दिन से अधिक काम नहीं किया । प्रदर्श डब्ल्यू-4 प्रमाण पत्र के लिए गवाह का कथन है कि यह संबंधित शाखा प्रबन्धक के यहां द्वारा बिना रिकार्ड के आधार पर के जारी किया गया था । इसके अलावा श्री टी.एन. बाफना द्वारा इस संबंध में की गई रिपोर्ट भी गवाह ने प्रस्तुत की है जो प्रदर्श एम-2 है व इसके अनुसार श्रमिक ने 18-1-85 से 9-4-87 तक 208 दिन काम किया था । गवाह का यह भी कथन है कि श्रमिक को उक्त अवधि में आकस्मिक कार्य के लिए रखा जाता था व उसकी नियुक्ति नियमित रिक्त स्थान पर नहीं की गई थी । गवाह की जिरह से यह स्पष्ट है कि उसने जो भी बयान दिया है व रिकार्ड पर आधारित है तथा उसे कोई भी व्यक्तिगत: जानकारी नहीं है क्योंकि न तो वे संबंधित शाखा में नियुक्त थे व न ही शाखा के निरीक्षण का कार्य उनके पास था । जिरह में गवाह ने यह भी कहा है कि कुल मिलाकर श्रमिक ने 119 दिन शाखा में कार्य किया था जबकि मूल बयान में यह माना है कि 9-7-85 तक श्रमिक ने 99 दिन काम किया था व श्री बाफना की रिपोर्ट के अनुसार 9-4-87 तक 208 दिन काम किया था । इस प्रकार स्वयं गवाह का बयान भी एक दूसरे के विपरीत है । प्रदर्श डब्ल्यू-4 प्रमाण पत्र के लिए गवाह का कथन है कि यह संबंधित बैंक प्रबन्धक द्वारा गलत जारी किया गया था यह साक्ष्य किसी भी रूप में मानने योग्य नहीं है क्योंकि प्रथम तो जिस अधिकारी ने प्रमाण पत्र जारी किया है उसे नियोजक ने साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है व इसके अलावा प्रमाण पत्र गलत होने का कोई भी आधार नियोजक की ओर से नहीं बताया गया है । पूर्व में जैसा लिखा गया है उनके अनुसार पूरा रिकार्ड भी नियोजक ने तलब कराने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया है । श्री बाफना की रिपोर्ट प्रदर्श एम-2 में मात्र यह लिखा हुआ है कि श्रमिक ने 119 दिन बैंक में कार्य किया था व उसकी अवधि 12-10-86 से 11-10-87 बताई गई है जो भी बैंक के कथन के विपरीत है तथा स्वयं श्री बाफना ने भी प्रदर्श एम-2 में यह लिखा है कि 8-4-87 से श्रमिक की सेवाएं समाप्त हो गई थी । प्रदर्श एम-2 में 119 दिन काम करने के संबंध में किसी भी आधार का उल्लेख श्री बाफना द्वारा नहीं किया गया है

व मात्र प्रोफार्मा उनके द्वारा भरा हुआ है जो बैंक के आकस्मिक श्रमिक के नियुक्तिकरण के बाबत तैयार किया है । इसके अलावा कोई भी साक्ष्य नियोजक की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है । प्रदर्श एम-4 व स्टेटमैंट है जो बैंक के आकस्मिक कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में तैयार करवाया था व उसमें भी श्रमिक द्वारा 240 दिन से कम काम करना बताया गया है । इस विवरण का स्वतंत्र रूप से बिना साक्ष्य के कोई भी महत्व नहीं है । दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह संदेह रहित मानने का आधार है कि श्रमिक ने बैंक की संबंधित शाखा में 8-4-87 तक 610 दिन कार्य किया था । साक्ष्य से यह भी साबित है कि श्रमिक की नियुक्ति दैनिक वेतन पर की गई थी तथा उससे बैंक का वह विभिन्न कार्य लिया जाता था जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है । प्रदर्श डब्ल्यू-4 शाखा प्रबन्धक द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसमें भी यह अंकित है कि श्रमिक को स्थाई कर्मचारियों के अवकाश पर होने के कारण अथवा पीने का पानी भरने के लिए व कूलर में पानी भरने के लिए नौकरी पर रखा गया था । ये तमाम कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा किये जाने वाले हैं ।

7. नियोजक पक्ष ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा श्रमिक को सेवा मुक्त करने से पूर्व धारा 25-एफ, जी,एच अधिनियम की पालना नहीं की गई थी व उनकी प्रतिरक्षा यह है कि ऐसा करना श्रमिक की सेवा अवधि को व कार्य की प्रकृति को देखते हुए आवश्यक नहीं था । पूर्व में जो विवेचन किया गया है उसमें यह साबित माना गया है कि श्रमिक को दैनिक वेतन पर विविध कार्य के लिए रखा गया था व उसने 240 दिन से अधिक बैंक में कार्य किया था । ऐसी स्थिति में धारा 25, एफ व जी अधिनियम की पालना आज्ञापक है इस बात का विरोध नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने भी बहस में नहीं किया है । इसके विपरीत उनका कथन है कि यदि श्रमिक द्वारा 240 दिन से अधिक कार्य करना साबित हो तो धारा 25-एफ के प्रावधान की पालना आवश्यक है, चाहे उसने दैनिक वेतन पर अथवा अंशकालीन रूप से कार्य किया हो इस संबंध में किसी भी विधि दृष्टान्त की आवयकता नहीं है व इसके बावजूद श्रमिक की ओर से जो दो निर्णय प्रस्तुत किये गये हैं उनको संदर्भित किया जाता है । ये निर्णय आर.एल.आर. 1991 (2) पेज 326 कन्हैयालाल बनाम राजस्थान राज्य व एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 5449/91 निर्णय दि. 24-8-92 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हैं । दोनों में यह प्रतिपादित किया गया है कि दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले श्रमिकों के मामले में भी 240 दिन से अधिक की अवधि के पश्चात सेवा मक्ति के मामले में धारा 25-एफ के. प्रावधान की पालना की जाना आज्ञापक है ।

8. नियोजक ने अपने जवाब में जो यह कहा है कि श्रमिक को अंशकालीन रूप से व दैनिक वेतन पर रखा गया था इसलिए सेवा में उसे नियमित नहीं कहा जा सकता, इस संबंध में इतना उल्लेख किया जाना पर्याप्त होगा कि जो विवाद निर्देशित किया गया है उसके तहत न्यायाधिकरण को मात्र यह विनिश्चय करना है कि श्रमिक को सेवा मुक्ति की कार्यवाही वैध है अथवा नहीं । नियोजक की ओर से निम्न विधि दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं :

1. ए.आई.आर. 1992 (एस.सी.) 789, दिल्ली डैवेलपमैंट हॉर्टीकल्चर एम्पलाईज यूनियन बनाम दिल्ली प्रशासन ।
2. ए.आई.आर. 1993 (ए.सी.) 1317 भारत संघ बनाम राजेन्द्र कुमार शर्मा ।
3. एल.एल.जे. 1985 (वॉल्यूम-1) (बॉम्बे) एस. आर. सिरोमकर बनाम गोआ प्रशासन ।

प्रथम संदर्भित निर्णय जवाहर रोजगार योजना से संबंधित है जो विशिष्ट योजना होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस सबध में विशिष्ट रूप से सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं जो अन्य मामले में लागू नहीं होते । दूसरे संदर्भित निर्णय में मात्र यह प्रतिपादित किया गया है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उस अवधि का वेतन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं जिसमें वे काम नहीं करते । तीसरे संदर्भित निर्णय के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से किसी भी रूप में सुसंगत नहीं हैं ।

9. चूंकि श्रमिक की सेवाएं 25-एफ के प्रावधान की पालना किये बिना समाप्त की गई हैं इसलिए सेवा मुक्ति की कार्यवाही अवैध व अनुचित है तथा श्रमिक पुनः सेवा में निरन्तरता बनाये हुए आने का अधिकारी है । श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि जिस तिथि से उसे बैंक से हटाया गया तब से वह लगातार बेरोजगार है । कोई जिरह इस संबंध में नियोजक द्वारा नहीं की गई व खण्डन में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है ।

10. एक बिन्दु जो नियोजक की साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है उस पर विचार किया जाना अपेक्षित है । प्रदर्श एम-1 समझौता के अनुसार जितने आकस्मिक श्रमिकों ने बैंक में 240 दिन से अधिक कार्य किया था उनको बैंक की स्थाई नौकरी में रखने का प्रावधान बनाया गया था व इसके अनुसार समस्त कर्मचारियों की सूची व उनकी योग्यता व अयोग्यता के संबंध में विवरण तैयार किया गया था । प्रदर्श एम-2 व एम-4 जो प्रलेख बैंक ने प्रस्तुत किये हैं उनमें यह उल्लेख है कि इस समझौते के अनुसार श्रमिक बैंक में स्थाई होने का इसलिए पात्र नहीं है क्योंकि उसने 240 दिन से कम कार्य किया है । उपलब्ध साक्ष्य में यह साबित माना गया है कि श्रमिक ने 240 दिन से अधिक दैनिक वेतन पर बैंक में कार्य किया था इसलिए प्रदर्श एम-1 समझौते के अनुसार भी वह नौकरी में स्थाई होने का अधिकारी है परन्तु चूंकि विवाद में इस बिन्दु पर विनिश्चय नहीं होना है इसलिए अधिनिर्णय के तहत यह अनुतोष श्रमिक को दिलाया जाना न्यायोचित नहीं है कि उसे उक्त समझौते के तहत स्थाई रूप से नौकरी दी जावे उक्त समझौते का उल्लेख मात्र इसलिए किया गया है कि स्वयं बैंक ने भी 240 दिन से अधिक कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा

मुक्ति को अवैध मानते हुए उन्हें नौकरी में लेने बाबत समझौता यूनियन के साथ किया था ।

11. उपलब्ध साक्ष्य व विधि की स्थिति के विवेचन के परिणामस्वरूप विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि नियोजक यूको बैंक जयपुर द्वारा श्रमिक नरेन्द्र कुमार शर्मा की दिनांक 9-4-87 से सेवा मुक्ति की कार्यवाही अवैध व अनुचित है इसलिए श्रमिक सेवा की निरन्तरता कायम रखते हुए उक्त तिथि से पुनः सेवा में आने का अधिकारी है । सेवामुक्ति की तिथि से अधिनिर्णय की तिथि का समस्त पिछला वेतन व अन्य लाभ भी श्रमिक नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है ।

12. अधिनिर्णय आज दिनांक 18-8-1994 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के भेजा जावे ।

के.एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1994

का. आ. 140.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार खेतड़ी कोपर काम्पलेक्स के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-12-94 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल – 43012/9/87 – डी – III – बी]
बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th December, 1994

S.O. 140.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Khetri Copper Complex and their workmen, which was received by the Central Government on the 28-12-94.

[No. L-43012/9/87-D.III-B]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 23/89

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र.एल. 43012/9/87-डी-III(बी) दिनांक 4-1-89

श्री गंगा राम मार्फत महासचिव, राष्ट्रीय कॉपर मजदूर कांग्रेस, डी – 217, आई. वी., खेतड़ी नगर, जिला झुंझुनू (राज.) —प्रार्थी

बनाम

खेतड़ी कॉपर काम्पलैक्स, खेतड़ी नगर, जिला झुंझुनू । —अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के.एल.व्यास, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल
अप्रार्थी की ओर से : श्री मनोज शर्मा
दिनांक अवार्ड : 16-9-94

अवार्ड

श्रमिक गंगा राम खेतड़ी कॉपर परियोजना, खेतड़ी के मामले में संबंधित यूनियन द्वारा उठाये गये विवाद के फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा निम्न विवाद अधिनिर्णय हेतु निर्देशित किया गया है :—

"Whether the action of the management of Khetri Copper Complex, P.O. Khetrinagar, District Jhunjhunu in not promoting Shri Ganga Ram Mechanist is justified ? If not, what relief is the said workman entitled to ?"

2. श्रमिक की ओर से जिन तथ्यों के आधार पर क्लेम प्रस्तुत किया गया है उनका सार यह है कि श्रमिक गंगा राम की नियुक्ति मैकेनिस्ट "बी" (मशीनमिस्त्री) के पद पर 10-5-77 को हुई थी व एक अन्य श्रमिक पी. एन. शिवदासम की नियुक्ति इस पद पर 27-10-77 को हुई थी तथा दोनों ही श्रमिक जिन मशीनों पर कार्य करते थे वे मशीनिस्ट "ए" के पद के कार्य के अनुरूप थी व इसके बावजूद प्रबन्धक द्वारा 10-2-86 के आदेश से श्रमिक शिवदासम की पदोन्नति मैकेनिस्ट "ए" के पद पर 1-8-30 से की गई । श्रमिक का कथन है कि चूंकि दोनों श्रमिकगण एक ही प्रकार का कार्य करते थे व वर्तमान श्रमिक पी.एन. शिवदासम से वरिष्ठ था इसलिए प्रबन्धक द्वारा श्रमिक को पदोन्नति नहीं देने की कार्यवाही अनुचित व अवैधानिक है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के तहत भेदभाव की नीति का प्रतीक है ।

3. नियोजक की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें एक प्रारंभिक आपत्ति यह ली गई है कि केन्द्र सरकार द्वारा गंगा राम के मामले में प्रारम्भ में 1-7-87 को विवाद न्यायाधिकरण में निर्देशित करने का निर्णय लिया गया था व उससे व्यथित होकर विवाद के संबंध में रिट याचिका श्रमिक गंगा राम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि तथ्यों से संबंधित होने के कारण रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है व संबंधित सरकार को विवाद को न्यायाधिकरण में निर्देशित करने का आदेश दिया गया । इन परिस्थितियों में यह अभिकथित किया गया है कि निर्देशित विवाद के अनुसार कोई भी औद्योगिक विवाद होना प्रकट नहीं होता है । तथ्यों के संबंध में इस बात को अस्वीकार नहीं किया गया है कि नियुक्ति तिथि के अनुसार श्रमिक गंगाराम एक अन्य श्रमिक पी.एन. शिवदासम से वरिष्ठ है । इसके अतिरिक्त यह प्रतिरक्षा ली गई है कि पी एन शिवदासम की पदोन्नति प्रबन्धक द्वारा 10-2-86 के आदेश से नहीं की गई थी जैसा कि श्रमिक का अभिकथन है बल्कि कार्य मूल्यांकन समिति (जिसे बाद में समिति

संबोधित किया जाएगा) की सिफारिश के अनुसार शिवदासम का स्थरीकरण मशीनिस्ट 'ए' के वेतनमान में किया गया था। समिति के कार्य के संबंध में पूर्व इतिहास का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि 11-8-70 को औद्योगिक न्यायाधिकण जयपुर द्वारा एक अधिनिर्णय पारित किया गया था जिसकी अनुपालना में समिति का गठन हुआ था व इसमें प्रबन्धक, संबंधित यूनियन व राष्ट्रीय उत्पादक परिषद् के सदस्य शामिल थे। समिति की प्रथम रिपोर्ट 1-4-71 से लागू की गई। 1974 में श्रमिक संघों ने यह मांग उठाई कि 1971 में कुछ कार्यों का मूल्यांकन समिति द्वारा नहीं हुआ था इसलिए यह कार्य पुनः करवाये जायें। संबंधित श्रमिक संघों के साथ 19-2-74 को एक समझौता हुआ था व इसके अनुसार पुनः समिति को कार्य मूल्यांकन करने का अनुरोध किया गया। इस समिति के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि समिति के सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था। संबंधित यूनियन द्वारा 25-2-78 को पुनः एक मांगों का चार्टर प्रस्तुत किया गया व इसके अनुसार 17-4-78 को एक समझौता सम्पन्न हुआ। इसके अनुसार पुनः समिति की सिफारिश पर एक लिखित समझौता प्रबन्धक व यूनियन के बीच 4-8-83 को सम्पादित हुआ। कुछ पदों के मामले में पुनः मूल्यांकन करने का निर्णय समझौते के अनुसार लिया गया व इसके अनुसार एक समिति का पुनः गठन किया गया जिसमें समस्त संबंधित यूनियन के सदस्य भी शामिल थे। इस समिति के समक्ष सदाशिवम ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था व समिति ने तमाम तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह निर्णित किया कि पूर्व में शिवदासम का स्थरीकरण मैकेनिस्ट "बी" के वेतनमान में सही रूप से नहीं किया गया था व इस समिति की सिफारिश के अनुसार मैकेनिस्ट "ए" का वेतनमान टी–8 शिवदासम को 1-8-80 से स्वीकृत किया गया। श्रमिक गंगाराम के संबंध में यह बताया गया है कि वह प्रारंभ से मैकेनिस्ट 'बी' के पद के अनुरूप कार्य करता था व इसी कारण समिति ने उसे उसी पद पर स्थरीकरण करने की सिफारिश की थी। इसके विरुद्ध गंगाराम द्वारा कोई भी प्रतिवेदन या अपील प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार नियोजक के जवाब का सार यह है कि श्रमिक सदाशिवम को कोई विभागीय पदोन्नति नहीं दी गई थी बल्कि न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय व समझौते के अनुसार गठित समिति की सिफारिश के अनुसार कार्य के अनुरूप उसका स्थरीकरण मशीनिस्ट "ए" के पद पर किया गया था व इस कारण कोई भी अनुतोष इस विवाद में श्रमिक गंगाराम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

4. श्रमिक गंगाराम की ओर से संबंधित यूनियन द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में यह बताया गया है कि नियोजक का यह कथन गलत है कि शिवदासम मशीनिस्ट "ए" का कार्य कर रहा था, सदाशिवम का व गंगाराम का कार्य किसी भी प्रकार भिन्न नहीं था बल्कि गंगाराम प्रारंभ से ही मशीनिस्ट "ए" के पद का कार्य कर रहा था, श्रमिक शिवदासम विपक्षी संस्थान के कार्मिक अधिकारी श्री चाकू के रिश्तेदार हैं इसलिए सदाशिवम को गलत रूप से पदोन्नति प्रबन्धक द्वारा दी गई थी। इस प्रत्युत्तर में भी नियोजक द्वारा बताये गये इन तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया है कि अधिनिर्णय व समझौते के अनुसार समिति का गठन हुआ था व इसकी सिफारिश के अनुसार सदाशिवम का स्थरीकरण किया गया था।

5. मौखिक साक्ष्य के रूप में श्रमिक की ओर से स्वयं उसका व नियोजक की ओर से एक गवाह श्री एन.एल. बटेडिया, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी का सपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। नियोजक की ओर से प्रालेखीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श एम–1 से प्रदर्श एम-10 प्रलेख की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

6. सर्वप्रथम यह उल्लिखित करना आवश्यक व अपेक्षित है कि निर्देशित विवाद के अनुसार श्रमिक द्वारा सदाशिवम को प्रबन्धक पक्ष द्वारा की गई पदोन्नति को चुनौती दी गई है इसलिए उपलब्ध साक्ष्य व प्रलेख से यह विनिश्चय करना आवश्यक है कि क्या सदाशिवम की पदोन्नति प्रबन्धक द्वारा की गई थी व यदि ऐसी नहीं है तो संबंधित समिति की सिफारिश के अनुसार मात्र स्थरीकरण को देखते हुए क्या श्रमिक गंगाराम कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि यह साबित हो कि वह सदाशिवम से वरिष्ठ है व दोनों का कार्य एक समान था।

7. जहां तक श्रमिक गंगाराम व सदाशिवम की वरिष्ठता का प्रश्न है, यह तथ्य मान्य है कि गंगाराम की नियुक्ति सदाशिवम से पूर्व हुई थी इसलिए वह मैकेनिस्ट 'बी' के पद पर सदाशिवम से वरिष्ठ था।

8. कार्य की प्रकृति के संबंध में श्रमिक गंगाराम ने अपने शपथ पत्र के पद सं. 2 में यह बताया है कि सदाशिवम ने कभी भी मशीनिस्ट "ए" के अनुरूप मशीनों पर कार्य नहीं किया जबकि जिन अन्य श्रमिकों के साथ गंगाराम प्रारंभ से कार्यरत है वह कार्य मशीनिस्ट "ए" के पद का है। कुछ श्रमिकों के नाम भी इस संबंध में शपथ पत्र में उल्लिखित किये गये हैं। किसी भी श्रमिक का शपथ पत्र इस संबंध में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। जिरह में श्रमिक ने यह बताया है कि मशीनिस्ट "ए" के जितने भी कार्य हैं वे सब उसके द्वारा किये जाते हैं। इसके विपरीत प्रबन्धक की ओर से गवाह श्री बटेडिया का जो शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है उसमें इस बात का खण्डन किया गया है कि श्रमिक ने कभी भी मैकेनिस्ट "ए" के रूप में कार्य किया हो व यह भी बताया गया है कि पी. एन. सदाशिवम अत्याधिक आधुनिक ग्राईंडिंग मशीन पर कार्य करता था व उसके अलावा भी अन्य मशीनों पर जो कार्य उसके द्वारा किया जाता था व मैकेनिस्ट "ए" के अनुरूप थे किन्तु उसे मैकेनिस्ट "बी" के पद का

वेतन दिया जाता था। इस गवाह से दोनों श्रमिकों के कार्य की प्रकृति के संबंध में कोई भी प्रश्न जिरह में नहीं पूछे गये हैं। गवाह श्री बटेडिया से इस प्रकार की जिरह भी नहीं हुई है जिससे यह माना जाये कि उन्होंने किसी भी रूप से प्रभावित होकर कार्य की प्रकृति के संबंध में गलत साक्ष्य प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त नियोजक के जो गवाह प्रस्तुत हुए हैं वे निश्चित रूप से संबंधित तथ्यों के लिए सुसंगत व विशेषज्ञ साक्ष्य के रूप में हैं तथा श्रमिक की साक्ष्य की तुलना में इस साक्ष्य को स्वीकार नहीं करने का कोई भी कारण नहीं हो सकता। इस प्रकार जहां तक कार्य की प्रकृति का प्रश्न है, दोनों पक्षों की साक्ष्य को देखते हुए यह मानने का आधार है कि गंगाराम की तुलना में सदाशिवम द्वारा मैकेनिस्ट "ए" के पद का कार्य किया जाता था व इस प्रकार यदि किसी भी रूप में प्रबन्धक द्वारा सदाशिवम को पदोन्नति देने का मामला हो तो भी इस आधार पर श्रमिक को कोई अनुतोष स्वीकार नहीं किया जा सकता।

9. नियोजक की जो प्रतिरक्षा है उस संबंध में श्री एन. एल. बटेडिया ने प्रदर्श एम—1 से प्रदर्श एम—10 प्रलेख को प्रस्तुत करते हुए यह बताया है कि न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय व संबंधित यूनियन के साथ हुए समझौतों के आधार पर समिति का गठन किया गया था व समिति की सिफारिश के अनुसार ही सदाशिवम को मैकेनिस्ट "ए" के पद में पद का लाभ दिया गया था। श्रमिक से जो जिरह हुई है उसमें उसने किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होना बताया है व उसके संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। प्रदर्श एम—1 से एम—10 सभी प्रलेख न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय, यूनियन के साथ हुए समझौते व प्रबन्धक पक्ष के नियमों से संबंधित है। इनसे यह स्पष्ट साबित होता है कि समिति का जब पुर्नगठन हुआ था उस समय सदाशिवम के प्रतिवेदन पर उसके कार्य का पुनः मूल्यांकन किया गया था व उनको सिफारिश पर ही सदाशिवम को मैकेनिस्ट "ए" के पद का लाभ दिया गया था। जवाब में अधिनिर्णय व समझौते के संबंध में जो विभिन्न तथ्य बताये गये हैं व जिनका पूर्व में उल्लेख किया गया है उनके बाबत कोई भी विवाद श्रमिक ने जवाबुलज्वाब में या साक्ष्य में नही लिया है। प्रदर्श एम—3 अधिनिर्णय 11-8-70 का है जिसके पठन से यह स्पष्ट है कि संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को यह शिकायत थी कि उन्हें वेतनमान कार्य के अनुसार नहीं मिलता है व इसीलिए कार्य मूल्यांकन समिति के गठन का निर्देश दिया गया था। जब जब समझौते हुए हैं उनपर संबंधित रजिस्टर्ड यूनियन के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं तथा समिति में भी इन यूनियन के सदस्य शामिल थे। इस प्रकार नियोजक की मौखिक साक्ष्य व प्रदर्श एम—1 से एम—10 से यह निःसन्देह साबित है कि श्रमिक सदाशिवम का स्थरीकरण मैकेनिस्ट"ए" के पद पर विधिवत गठित समिति की सिफारिश पर किया गया था व इस कार्यवाही को प्रबन्धक द्वारा की गई पदोन्नति की परिभाषा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार यह विवाद जिस प्रकार/जिस रूप में न्यायाधिकरण में भेजा गया है उसके अनुसार श्रमिक कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

10. श्रमिक ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि जिस समिति द्वारा सदाशिवम को मैकेनिस्ट "ए" के पद का लाभ देने की सिफारिश की गई उसके समक्ष उसने अपना कोई भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। यह भी श्रमिक का कथन नहीं है कि उसने किसी भी समिति की सिफारिश से असन्तुष्ट होने के कारण प्रबन्धक को अथवा समिति को कोई अपील या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हो। इससे यह मानने का आधार भी बनता है कि श्रमिक समिति द्वारा की गई कार्यवाही से किसी भी रूप में असन्तुष्ट नहीं था।

11. श्रमिक ने अपने क्लेम व दावा जवाब में समिति के गठन का, उनकी सिफारिश का व समझौतों के संबंध में कोई भी अभिकथन नहीं किया हैं इस कारण नियोजक की ओर से जो प्रलेख प्रस्तुत किये गये है उनके अलावा अन्य कोई भी प्रलेख या साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं था। प्रस्तुत साक्ष्य व प्रलेख से भी यह पूर्ण रूप से साबित है कि वैध रूप से कथित समिति की सिफारिशों के अनुसार सदाशिवम का स्थरीकरण किया गया था व इस कारण इस आधार पर श्रमिक कोई भी पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता।

12. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत अभिकथन साक्ष्य व प्रलेख तथा पूर्व में किये गये विवेचन का निष्कर्ष यह है कि श्रमिक सदाशिवम की पदोन्नति प्रबन्धक पक्ष द्वारा मैकेनिस्ट "ए" के पद पर नहीं की गई थी, श्रमिक गंगाराम ने वैध रूप से पठित समिति की सिफारिश को किसी भी रूप में कहीं भी चुनौती नहीं दी है तथा निर्देशित विवाद भी इस संबंध में नहीं है। इसलिए समिति की सिफारिश के अनुसार सदाशिवम को दिये गये लाभ के अनुरूप गंगाराम कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता।

12. विवेचित तथ्यों व परिस्थितियों के विवेचन के परिणामस्वरूप निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय श्रमिक के खिलाफ किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि श्रमिक गंगाराम को प्रबन्धक पक्ष द्वारा मैकेनिस्ट"ए" के पद पर पदोन्नति नहीं करने की कार्यवाही वैध व न्यायोचित है व परिणामस्वरूप श्रमिक कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

13. अवार्ड आज दिनांक 16-9-94 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

के. एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1994

का. आ. 141—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर उद्योग लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण,

जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28 दिसम्बर, 1994 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-25011/1/72 एल आर -I]
बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th December, 1994

S.O. 141.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Udyog Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 28-12-94.

[No. L-25011/1/72-L.R.I.]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 9/1972

रैफरेंस : केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश क्रम एल. 2 5011/1/72 एल आर.आई दिनांक 30-9-72

सीमेन्ट माईन्स कर्मचारी संघ

--प्रार्थी

बनाम

जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर

--अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के. एल. व्यास, आर एच.जे.एस

प्रार्थी की ओर से : श्री. जे. एल. शाह एवं श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री मनोज शर्मा

दिनांक अवार्ड : 16-8-94

अवार्ड

सीमेन्ट वर्कर्स कर्मचारी संघ की ओर से श्री जे. एल. शाह सीमेन्ट माईन्स कर्मचारी यूनियन की ओर से श्री जे. के. अग्रवाल तथा प्रबन्धक की ओर से श्री मनोज शर्मा उपस्थित हैं। दोनों संबंधित यूनियन के प्रतिनिधिगण ने आज जाहिर किया कि संबंधित फैक्ट्री लंबे समय से बन्द है तथा उन्हें अपने पक्षकारों से आगे पैरवी करने के कोई भी निर्देश नहीं हैं इसलिए कार्यवाही समाप्त की जा सकती है। प्रबन्धक पक्ष के प्रतिनिधि को कोई आपत्ति नहीं है। अतः यूनियन के प्रतिनिधिगण द्वारा कोई भी निर्देश नहीं होना जाहिर करने के कारण मामले में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये।

के. एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1994

का. आ. 142.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैं. मेवाड़ मारबल्स लि. मैं. सीकंसारिया मारबल्स एंड मिनरल लि., मैं इन्टर नेशनल मिनरलस लि. के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-12-95 को प्राप्त हुआ था ?

[संख्या एल 29011/4/89 आई आर (विविध)]
बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th December, 1994

S.O. 142.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of 1. M/s. Mebare Marbles Ltd. 2. M/s. Singsaria Marbles and Mineral Ltd. 3. International Minerals Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 28-12-94.

[No. L-29011/4/89-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 9/92

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश क्रमांक संख्या एल 29011/4/89 आई आर दिनांक 7-4-92

अध्यक्ष/जनरल सचिव, भारतीय माईन्स मिनरल मजदूर संघ श्री कृष्णा निकुंज, गुलाबबाग के पास उदयपुर-313001

--प्रार्थी

बनाम

1. मैनेजिंग डायरेक्टर मैसर्स मेवाड़ा मारबलस लि. शास्त्री मार्केट भीलवाड
2. मैनेजिंग डायरेक्टर, मैसर्स सीकंसारिया मारबल्स एंड मिनरल लि., बोल्या सदन, कांकरोली।
3. जनरल मैनेजर/मैनेजिंग डायरेक्टर मै. दी. इन्टरनेशनल मिनरल्स लि. पो.आ. 27 कांकरोली।

--अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के. एल. व्यास आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. एल. शाह

अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं

दिनांक अवार्ड 8-9-94

अवार्ड

श्री जे. एल. शाह यूनियन की ओर से उपस्थित हैं। विपक्षी की ओर से कोई हाजिर नही है। श्री शाह इस प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करना चाहते है। अतः इस प्रकरण में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है। जो राज्य सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ भेजा जावें।

के. एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1994

का. आ. 143.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार जयपुर उद्योग लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 28-12-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल 29012 /36 /84 डी -III -बी]
बी० एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th December, 1994

S.O. 143.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Udyog Limited and their workmen, which was received by the Central Government on 28-12-94.

[No. L-29012/36/84-D.III.B.]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर

केस नं. सी आई टी. 85 /1984

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल 29012/36/84 डी-III (बी) दि 30-11-84

अध्यक्ष जयपुर उद्योग कर्मचारी यूनियन पोस्ट फलौदी क्वारी जिला सवाई माधोपुर।
—प्रार्थी

बनाम

व्यवस्थापक, फलौदी क्वारीज जयपुर उद्योग लि. पोस्ट फलौदी क्वारी, जिला सवाईमाधोपुर।
—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के. एल व्यास आर.एच.जे.एस
प्रार्थी की ओर से: श्री जे. के. अग्रवाल
अप्रार्थी की ओर से: श्री मनोज शर्मा
दिनांक अवार्ड: 16-8-1994

अवार्ड

संबंधित यूनियन की ओर से श्री जे. के. अग्रवाल व प्रबन्धक पक्ष की ओर से श्री मनोज शर्मा उपस्थित। श्री जे. के. अग्रवाल का कथन है कि उन्हें अपने पक्षकार से मामले में कोई भी निर्देश उपलब्ध नहीं है इसलिए नियमानुसार आगे कार्यवाही की जा सकती है। श्री मनोज शर्मा को इस तर्क पर कोई आपत्ति नहीं है। निर्देश के संबंध में कोई भी साक्ष्य किसी भी पक्ष की लेखबद्ध नहीं हुई है। मामला 1984 से विचाराधीन है। संबंधित यूनियन के प्रतिनिधि ने आज कोई भी निर्देश नहीं होना जाहिर किया है इसलिए मामले में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जाये।

के. एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1994

का. आ. 144.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर उद्योग लि. के प्रबन्धतंत्र के सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-12-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल 29011 /6 /73 — एल . आर —I]
बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th December, 1994

S.O. 144.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Udyog Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 28-12-94.

[No. L-29011/6/73-I.R.I.]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 12/73

रैफरेंस : राज्य सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-29011/6/73 एल.आर. I दिनांक 19-2-1973

सीमेन्ट माईन्स कर्मचारी संघ
—प्रार्थी

बनाम

जयपुर उद्योग लि., सवाई माधोपुर
—अप्रार्थी

उपस्थित

प्रार्थी की ओर से : श्री जे.एल. शाह
अप्रार्थी की ओर से : श्री मनोज शर्मा
दिनांक अवार्ड : 16-8-1994

अवार्ड

सीमेन्ट वर्कर्स कर्मचारी संघ की ओर से श्री जे.एल. शाह व सीमेन्ट माईन्स कर्मचारी संघ की ओर से श्री जे.के. अग्रवाल तथा प्रबन्धक पक्ष की ओर से श्री मनोज शर्मा उपस्थित। दोनों संबंधित यूनियन के प्रतिनिधिगण ने आज जाहिर किया कि संबंधित फैक्ट्री लम्बे समय से बन्द है तथा उन्हें अपने पक्षकारों से आगे पैरवी करने के कोई भी निर्देश नहीं हैं इसलिए कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

मामले में प्रबन्धक पक्ष की ओर से साक्ष्य हुई है लेकिन यूनियन के प्रतिनिधिगण द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन्स होने के कारण उस पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है । प्रबन्धक पक्ष के प्रतिनिधि श्री मनोज शर्मा को मामले में कार्यवाही समाप्त किय जाने पर कोई आपत्ति नहीं है । अतः यूनियन के प्रतिनिधिगण द्वारा कोई भी निर्देश नहीं होना जाहिर करने के कारण विवाद में नो डिस्प्युट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

के.एल. व्यास, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1994

का.आ. 145 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-12-94 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-11025/3/86-डी-I-बी]
बि. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th December, 1994

S.O. 145.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Lakheri Cement Works and their workmen, which was received by the Central Government on the 28-12-94.

[No. L-11025/3/86-D.I.B.]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 25/86

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-11025(3)86/डी-I (बी) दिनांक 10-3-86

दामोदर लाल शर्मा पुत्र श्री काला राम शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट बदवासी जिला नागौर, राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

जनरल मैनजर, लाखेरी सीमन्ट वर्क्स, ए.सी.सी. लाखेरी जिला बूंदी।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के.एल. व्यास, आर.एच.जे.एम.

प्रार्थी की ओर से श्री जे.के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से श्री एम.डी. अग्रवाल

दिनांक अवार्ड 2-9-1994

अवार्ड

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निर्देशित विवाद का क्लेम प्रस्तुत किया गया है तथा विपक्षी की ओर से क्लेम का जवाब भी प्रस्तुत हुआ है । विपक्षी को साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी यूनियन की साक्ष्य हेतु पत्रावली निश्चित की हुई थी । आज श्री जे.के. अग्रवाल प्रार्थी की ओर से एवं श्री एम.डी. अग्रवाल विपक्षी की ओर से उपस्थित हैं । पक्षकारों के प्रतिनिधिगण ने दिनांक 23-8-94 को एक बाहमी समझौता पैश किया था जिसे उसी रोज तस्दीक किया गया । पक्षकरान के प्रतिनिधिगण की प्रार्थना पर मामले में समझौते के आधार पर अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे । समझौता अवार्ड का एक अंग रहेगा ।

के.एल. व्यास, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1994

का.आ. 146—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स जयपुर उद्योग लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-12-94 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-29011/45/81-डी-III-बी]
बि.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th December, 1994

S.O. 146.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Jaipur Udyog Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 28-12-94.

[No. L-29011/45/81-D.III.B.]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 9/82

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-29011/45/81-डी-III(बी) दि. 23-2-82

जयपुर उद्योग कर्मचारी यूनियन, जिला सवाई माधोपुर

—प्रार्थी

बनाम

मैसर्स जयपुर उद्योग लि. पो.ओ. फतौदी कचैरी जिला सवाई माधोपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के.एल. व्यास, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से	श्री जे.के. अग्रवाल
अप्रार्थी की ओर से	श्री मनोज शर्मा
दिनांक	16-8-1994

अवार्ड

यूनियन की ओर से श्री जे.के. अग्रवाल व प्रबन्धक पक्ष की ओर से श्री मनोज शर्मा उपस्थित आये । श्री अग्रवाल का कथन है कि व अपने पक्षकारों की ओर से कोई भी निर्देश नहीं होना बताया है । पत्रावली पर उनका कोई भी अधिकार पत्र उपलब्ध नहीं है परन्तु आदेशिकाओं के अवलोकन से यह पता लगता है कि प्रारंभ यूनियन की ओर से श्री पी.सी. गांधी प्रतिनिधि उपस्थित होते थे व बाद में दिनांक 20-7-84 से लगातार श्री जे.के. अग्रवाल को उपस्थित यूनियन की ओर से दर्ज की जा रही है । श्री अग्रवाल के अलावा आज कोई प्रतिनिधि यूनियन की ओर से उपस्थित नहीं है । दिनांक 2-7-83 को न्यायाधिकरण द्वारा एक लिखित आदेश पारित किया गया था व उसके अनुसार रिलीफ अंडरटेकिंग के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही लंबित होने के कारण इस विवाद में अग्रिम कार्यवाही स्थगित की गई थी । श्री मनोज शर्मा प्रतिनिधि प्रबन्धक पक्ष का कथन है कि रिलीफ अंडरटेकिंग के तहत कार्यवाही समाप्त हो गई है व वर्तमान में बी.एफ.आई.आर. के तहत इस उद्योग से संबंधित कार्यवाही विचाराधीन है व इस कारण जो पूर्व में स्थगन आदेश जारी किया गया था उसका कोई भी प्रभाव नहीं रहता है । किसी भी पक्ष की साक्ष्य अब तक प्रकरण में नहीं हुई है । चूंकि यूनियन के प्रतिनिधि श्री अग्रवाल ने अपने पक्षकार की ओर से कोई निर्देश नहीं होना जाहिर किया है इसलिए मामले में नो डिस्प्यूट पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

के.एल. व्यास, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1994

का. आ. 147—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बाम्बे पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 1, बाम्बे के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-12-94 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-31011/10/94 आई आर/(विविध)]
बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th December, 1994

S.O. 147.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on the 29-12-94.

[No. L-31011/10/94-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, BOMBAY

Present :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.
REFERENCE NO. CGIT-1/41 OF 1992

Parties :

Employers in relation to the management of Bombay Port Trust.

AND

Their Workmen.

Appearances :

For the Management : Shri Anchan, Advocate.

For the Workmen : Shri Wagh, Advocate.

INDUSTRY : Ports & Docks STATE : Maharashtra

Bombay, dt. 16th day of December, 1994

AWARD

By letter dt. 28th May 1992 Government of India Ministry of Labour has referred dispute mentioned in the schedule below for adjudication under section 10(1)(d) read with 2A of the Industrial Disputes Act, 1947.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bombay Port Trust Bombay in withdrawal of the Telephone Clerk and ordering abolition of Third Shift in Railway Engineering Section without complying the provision of section 9A of the I. D. Act, 1947 w.e.f. 16/02/89 is just, proper and legal ? If not, to what relief are the workmen entitled to ?"

2. The grievance of the Union has to be found in the statement of claim filed by its Assistant Secretary.

3. The telephone board of the railway engineering section office at Mazgaon was manned round the clock in three shifts known as first, second and third shift. In each one of the shifts there was a clerk-cum-operator and a messenger. The clerk received messages from B.P.T. railway Manager's department about accident etc. and also for summoning emergency staff required for urgent work such as repairs of track, engines etc. On receipt of such message the clerk used to ask the messenger to deliver the same. Without issuing any prior notice or discussing issue with the Union as per the practice followed for a number of years. The Authorities by letter dt. 15-2-89 effected a change by withdrawing the telephone clerk-cum-operator posted in the third shift resulting in abolition of that shift in railway engineering section office at Mazgaon Bombay. This was effective from 16-2-89 and since that day messages are directly received by the CPWI (chief permanent way inspector) a BPT officer at his residence on his private phone and he processed them further. Union is not aware as to whether this officer is paid any allowance for this night duty work. There was no reason and/or urgency for this action and it resulted in withdrawal of one telephone clerk and also of third shift which ought to have been done in accordance with provisions of Sc. 9A of the Act by giving notice of change and therefore the action is illegal improper and unjustified.

4. Matter was taken to the Assistant Labour Commissioner but resulted in a failure report since the Management of the BPT contended that the change introduced was not a change in service condition. Written statement has been filed by secretary Bombay Port Trust Shri Apte who has admitted that the clerk working in the third shift was transferred but his contention is that he is transferred to the Chief engineer's

office at Ballord Pier to work in the normal office hours from 10.30 am to 5.30 pm. That was because there was reduction in the work done by the clerk in the third shift because of shrinkage of railway tracks from 240 kilometers to 130 kilometers, removal of number of slidings, reduction in shunting operations and improvement in general upkeep of the railway tracks. The chief permanent way inspector got a telephone connection at his residence and if any messages about major accident etc. requiring urgent attention during night were received by the Chief Permanent way inspector directly as his residence there was no need of a clerk in the night shift. It is contended it is for the Management to deploy staff as per the need. It did not amount to any change in the service conditions and therefore there was no merit in the contention that a notice under section 9A of the I.D. Act was necessary and in the absence of that the action is illegal and unjustified.

5. Issues have been framed and they are set out below together with my findings.

ISSUES	FINDINGS
1. Whether the workman establishes that the action of Management amounts to closing of shift.	Not established
2. Whether notice u/s. 9A of the act was required to be given.	No.
3. If so what effect.	As per order.

6. No oral or documentary evidence has been adduced on either side. The counsel have been heard.

7. The admitted position is that there were three shifts in each one of which there was a clerk-cum-operator and a messenger and by order dt. 15-2-1989 the clerk has been withdrawn from the third shift and transferred elsewhere in the same department. It is stated that third shift has been ordered to be abolished. However, that order dt. 15-2-89 sent produced to see if there has been an abolition of that shift as stated by the union. It is also not clear as to whether the messenger working in that shift has been withdrawn and transferred elsewhere Mr. Wagh appearing on behalf of the Union has not aware of this. Therefore there is difficulty in accepting the contention of the Union that there has been an abolition of the third shift or that withdrawal of one clerk resulted in abolition of the shift. Mr. Wagh's relied upon Sc. 9A and the items 6 of the 4th schedule of the I.D. Act. Item 6 reads as thus

"starting, alteration or discontinuance of shift working otherwise than in accordance with standing orders".

8. He submits that if this is done and it has been done in this case by discontinuing of shift working Sc. 9A would come in play and since no notice has been given the action would be illegal. As stated earlier discontinuance of the shift is not established and therefore item 6 is not attracted and therefore Sc. 9A does not operate.

9. Assuming for a moment that the action of the Management resulted in discontinuance of shift I find that the contention that Sc. 9A immediately comes in play is not correct. Sc. 9A says that no employer who proposes to effect any change in the conditions of or service applicable to any workman in respect of any matter specified in the 4th schedule shall effect such change. Therefore it is necessary to show that the employer has effected any change in the conditions of service applicable to any workmen and if that is not done than Section 9A will not operate even if any of the items of the 4th schedule is attracted.

10. Here in this case the Management has assigned reason for withdrawing that clerk-cum-telephone operator from that shift as there was no need for it and transferred that clerk-cum-telephone operator in the same department at Ballord Pier to work in normal office hours from 10.30 am to 5.30 pm that I do not think it could be objected. The work of receiving a message of an urgent nature was considerably reduced for the reasons stated in para 7 of the written statement and the Chief Permanent way inspector who was provided with a residential telephone could attend to dispensing with the intermidiary namely the clerk in the third shift. All that the clerk was doing was to receive and transmit such messages. In my view this could be done by the Management and it was not necessary to give any notice under section 9A because there was no change in the conditions of service applicable to that workman.

11. Mr. Wagh wanted the larger issue namely that it resulted in the reduction of one post to be considered in the light of this which I do not think I can do while adjudicating upon the dispute referred to me. In fact I may state that there is no material to show that there has been as a result a reduction in the posts of clerk. I, therefore, answer issues accordingly I pass award accordingly.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1994

का.आ. 148 —जब कि टेलिकॉम विभाग, गुंटूर के प्रबंधन और उनके कर्मकार, जिनका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय टेलिकॉम संघ, लाइन स्टाफ और वर्ग "घ" गुंटूर टेलिकॉम जिला गुंटूर द्वारा किया जा रहा है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और जब कि, उपरोक्त प्रबंधन और उनके कर्मकार जिनका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय टेलिकॉम कर्मकार संघ, लाइन स्टाफ और वर्ग "घ", द्वारा किया जा रहा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 15) की धारा 10क की उप धारा (i) के अंतर्गत, एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए भेजने पर सहमत है और उक्त विवाचन करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेज दी है,

अतः अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10–क की उप धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त करार को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10–क के अंतर्गत)

के बीच

पक्षकारों के नाम

नियोजक के प्रतिनिधि	कर्मकार के प्रतिनिधि
श्री जी. आई. दयाधन राव	श्री वी.बी.एस. राजू
एस डी ई (टी), महा प्रबंधक	क्षेत्रीय सचिव,
का कार्यालय, टेलिकॉम,	ए.आई.टी.ई.यू., लाइन स्टाफ,
गुंटूर	वर्ग "घ"
	गुंटूर क्षेत्र

पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित विवाद को विवाचन के लिए श्री ए. प्रभाकर, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) हैदराबाद के पास भेजने की सहमति हो गई है ।

(1) विवाद के विशिष्ट मामले	श्री ए. श्रीनिवास राव, भूतपूर्व नैमित्तिक मजदूर की सेवाओं की तथाकथित अवैध छटनी
(2) अंतर्ग्रस्त प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम के नाम व पता सहित	महाप्रबंधक टेलिकॉम, गुंटूर

पक्षकार का नाम

(3)	अंतर्ग्रस्त प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम के नाम व पतों सहित विवाद से संबंधित पक्षकारों के ब्यौरे	प्रबंधन के प्रतिनिधि श्री जी. आई. दयार्धन राव, एस डी ई (टी), महाप्रबंधक का कार्यालय, टेलिकॉम, गुंटूर
(4)	कर्मकार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में अंतर्ग्रस्त है या संघ का नाम, यदि कोई हो, जो संबंधित कमकारों या कर्मकार का प्रतिनिधित्व करता हो	कर्मकार के प्रतिनिधि श्री वी. वी. एस. राजू, पुत्र श्री बुची, क्षेत्रीय सचिव ए आई टी ई यू लाइन स्टॉफ, वर्ग "घ", गुंटूर क्षेत्र
(5)	प्रभावित उपक्रम में नियोजित कमकारों की कुल संख्या	शून्य
(6)	विवाद से प्रभावित अथवा प्रभावित होने वाले कर्मकारों की अनुमानित संख्या	शून्य

विवाचक अपना पंचाट तीन माह की अवधि के भीतर अथवा हमारे मध्य हुए परस्पर लिखित करार द्वारा आगे बढ़ाए गए समय में देगा । यदि उपरोक्त अवधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता है तो विवाचन के लिए भेजा गया विषय स्वतः निरस्त हो जाएगा और हम नए विवाचन के लिए वार्ता करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

प्रबंधन की ओर से	संघ की ओर से
ह./-	ह./-
(जी. आई. दयार्धन राव)	(वी. वी. एस. राजू)
एस डी ई (टी), महाप्रबंधक का कार्यालय, टेलिकॉम जिला गुंटूर	क्षेत्रीय सचिव, ए आई टी ई यू. लाइन स्टॉफ वर्ग "घ" गुंटूर क्षेत्र

विवाचक की सहमति

विषय — औद्योगिक विवाद अधिनियम—टेलिकॉम विभाग, गुंटूर के प्रबंधन और उनके कर्मकार श्री ए. श्रीनिवास राव, भूतपूर्व नैमित्तिक मजदूर के मध्य उक्त मजदूर की सेवाओं की तथाकथित अवैध छंटनी के संबंध में औद्योगिक विवाद—धारा 10-क के अंतर्गत विवाचक की सहमति के बारे में :

उपरोक्त विषय पर पत्र सं. 8/4/94-ए एल सी-बी डेड ए दिनांक 19-9-1994 के संदर्भ में। इस संबंध में, मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत उपरोक्त विवाद का विवाचन करने के लिए लिखित रूप से सहमति देता हूं ।

ह./-

(ए. प्रभाकर)

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

हैदराबाद

[सं. एल-40012/217/94-आई आर (डी यू)]

के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th December, 1994

S.O. 148.— Whereas an industrial dispute exists between the management of Telecom Department, Guntur and their workman represented by the All India Telecom Employees Union, Line Staff and Group 'D' Guntur Telecom District Guntur.

And whereas, the said management and their workman represented by all India Telecom Employees Union, Line Staff and Group 'D' have by written agreement under sub-section (i) of Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agree for refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement :

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (3) of Section 10-A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

Between

Name of the Parties

Representing Employer	Representing Workman
Sh. G.I. Dayardhana Rao, SDE(T), O/o General Manager, Telecom, Guntur	Sh. V.V.S. Raju Area Secetary AITEU Line Staff Grade 'D' Guntur Area.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri A. Prabhakar, RLC(C) Hyderabad.

(i) Specific matter in dispute:	Alleged illegal retrenchment of services of Shri A. Srinivasa Rao, Ex-Casual Mazdoor.
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking;	General Manager, Telecom District; Guntur.
(iii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.	Representing the management Sh. G.I. Dayardhana Roa, SDE(T), O/o General Manager Telecom, Guntur

(iv) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute and the name of the Union, if an y representing the workmen or workman in question.	Representing the workman Sh.V.V.S.Raju,S/o Sh. Buchi Area Secretary, AITEU Line-Staff Group 'D' Guntur Area.
(v) Total number of workmen employed in the undertaking affected.	Nil
(vi) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.	Nil

The arbitrator shall make his award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in sitting. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall free to negotiate for fresh arbitration.

On behalf of the management

Sd/-
(G.I. Dayardhana Rao)
SDE(T)
O/o General Manager
Telecom District..Guntur.

On behalf of the Union

Sd/-
(V.V.S. Raju)
Area Secretary
AITEU, Line Staff
Group (D),
Guntur Area.

CONSENT OF THE ARBITRATOR

Sub: I.D. Act—I.D. between the management of Telecom Deptt. Guntur and their workmen Sh. A. Srinivasa Rao, Ex. Casual Mazdoor over alleged illegal termination of his service—Consent for Arbitration under Section 10-A reg:

In reference to letter no. 8-4-94-ALC-BZA dated 19-9-1994 on the cited subject. In this regard I am hereby giving, my written consent for Abritration in the above mentioned dispute under Section 10-A I.D. Act.

Sd/-
(A. Prabhakar)
Regional Labour Commissioner (Central)
Hyderabad.

[No. L-40012/217/94—IR(DU)]
K.V.B. UNNY Desk Officer

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1994

का.आ. 149 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार म/स डाराबसाउ बि कारसेटीनस सन्स (बॉम्बे) प्राईवेट लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं.-1, बॉम्बे के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-12-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-31012/4/91-आई आर (विविध)]
बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th December, 1994

S.O. 149.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (11 of 1947), the Central Government herey publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Darabshaw B. Cursetjee's Sons (Bombay) Pvt. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 29-12-94.

[No. L-31012/4/91-IR(MISC)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, BOMBAY

PRESENT:

Shri Justice R. G. Singhakar, Presiding Officer.
Reference No. CGIT-54 of 1991

PARTIES:

Employers in relation to the management of M/s. Darabshaw B. Cursetjee's Sons (Bombay) Pvt. Ltd.

AND

Their Workmen

APPEARANCES:

For the Management—No appearance

For the Workman—Shri Anilkumar Advocate.

INDUSTRY : Port & Docks STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 16th day of December, 1994

AWARD

Government of India, Ministry of Labour has referred following dispute for adjudication under section 10(1)(d) read with sub-section 2A of the Industrial Disputes Act, 1947

"Whether the termination of service of Shri S. S. Surajbin Singh by the management of M/s. Darabshaw B. Cursetjee's Sons (Bombay) Pvt. Ltd. with effect from 5-11-90 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

2. Statement of claim has been filed by the workman. He has been in the employment of M/s. Darabshaw B. Cursetjee's Sons (Bombay) Pvt. Ltd. herein referred to as the workman and the employer respectively. The workman joined the employment of the Company on 1-4-1979. He states that on 30th April, 1990, put in an application for leave for 22 days. That was necessitated because of his wife's serious illness at his native place. He was permitted to go to his native place. It took sometime for his wife to recover any by the time she recovered workman himself fell sick. During this spell his leave expired. Since there was no one is the workman's house to send a telegram to inform employer it was intimated a little later and medical certificates also sent.

3. The employer, however, while he was at his native place sent chargesheet-cum-notice of enquiry dated July 16, 1990. It came out with a case that the workman was remaining unauthorisedly absent right from 3-5-1990. He was charged with 'misconduct' under Clauses 17(1), 28 of the Standing Orders applicable to the organisation. The charges were 'wilful insubordination of disobedience of lawful and reasonable orders of the employer'. And secondly 'absence without leave'. The main charge was absence with effect from 3-5-1990.

4. An enquiry it appears came to be conducted in his absence and on the adverse report he came to be dismissed by the management. It is this order of dismissal that he is challenging.

5. The employer has filed written statement. According to the employer the workman was never sanctioned leave. He

had no leave to his credit and the ground mentioned was not true. He was asked to come back but he did not do so. Misconduct therefore, committed by him was held proved in the departmental enquiry and on the basis of that his services came to be terminated because his past record was also not good. The employer filed written statement but thereafter, chose to remain away from this Tribunal. This matter was therefore, requied to be held ex-pate. Shri Suraj Bin Singh, the workman has filed an affidavit in support of his case and also produced xerox copies of the application he addressed the management and certificates he had sent to the management. Since there was no appearance on behalf of the employer there has been no cross-examination of Shri Suraj Bin Singh, the workman.

6. The admitted position is that the services of Shri Suraj Bin Singh came to be terminated and the alleged misconduct consisted of remaining absent unauthorisedly with effect from 3-5-1990. The said action was taken after giving him charagesheet and holding a Departmental enquiry and the management's case is that he was given adequate opportunity to defend himself at the enquiry. That enquiry admittedly was held ex-parte. Since the disciplinary action of dismissal has been preceded by Departmental Enquiry which was held in accordance with the Standing Ordres and in accordance with the principles of natural justice this Tribunal should held that it is legal and justified.

7. As against this the workman contends that he made an application on 30th April, 1990, and he was informed that it is granted and therefore, he proceeded to his native place where his wife was seriously ill. In support of this he has filed an affidavit and mentioned therein that his wife was seriously ill and therefore, he has proceeded to his native place after giving an application for leave and after being told that his leave was granted by the Company. He further states that his wife was under the treatment but in the meanwhile his daughter fell ill and expired. This came as a shock and he himself fell ill because of this strain, involved in looking after his wife and daughter. He further states that he sent letters to the company and medical certificates as soon as he could move out and send the same. Sent further letter dated 11-6-1990 by which he asks extension of leave on the ground of his wife's illness and also requested for his salary for the month of April 1990. He also wrote letters dated 20th April, 2nd August and 21st August 1990 in reply to the chargesheets and enquiry proceedings about his illness and requested for sending his salary so as to unable him to travel to Bombay. He has produced xerox copies of those letters and medical certificates.

8. First letter that he received from the Company was of 16th July 1990 which accused him of remaining absent unauthorisedly and committing misconduct of insubordination and absence without leave. It is for the first time that the Company informed that his leave was not sanctioned and he was remaining absent with effect from 3-5-1990. He received another letter dated 19-8-1990 about the enquiry to be held against him. He informed, according to him, as stated in the affidavit through his brother who was previously working with the Company and also by that letter requesting that the enquiry proceedings may not be conducted and also that the allegations against him in the earlier letter dated 16-7-90 were incorrect.

9. He thereafter receives the Company's final notice saying that the adverse findings are recorded in the enquiry proceedings by the Enquiry Officer and asked to show cause why order of dismissal should not be imposed upon him. Before he could reply to this letter which he received on 4-10-1990, the Company dismissed him from service by letter dated 5-11-1990.

10. He has stated that as per practice that he had applied for leave through his immediate superior and he did so and it was Mr. Survey, Booking Incharge, his superior who told him that his leave was sanctioned. That is why he proceeded to his native place. According to him that is no insubordination nor absence without leave. He also introduced the Company about the grounds for overstay and requested for extension of leave and therefore, his absence was necessitated by his wife's illness, his daughter's illness and his own illness. He has also mentioned that the punishment imposed upon him is as unduly harsh for the misconduct he was charged with. It is also according to him discriminatory. He complains of non-supply of copy of the Enquiry Officer's report which was given to him only at the time of conciliation proceedings. It has to be stated that all this evidence which he has given in the form of affidavit is not challenged in cross-examination nor there is any contra evidence on record. This evidence in the form of affidavit is supported by the medical certificates obtained by the workman and first one Annexure 'A' to the affidavit shows that his wife Smt. Geetabai was under the treatment of Dr. Gautam with effect from 10-6-90. The other certificates produced by him shows that he was under the treatment with effect from 25-5-90 to 12-6-1990 and was fit to resume duties on 13-6-1990. He has mentioned the reasons and also sent communication to the employer on 11-6-1990, 20-7-1990 and 2-8-1990. The last one is dated 21-8-1990. It appears therefore, that the absence was necessitated because of his wife's illness and before proceeding to his native place to look after his wife, he had applied for leave and was told that it was granted. He was, thereafter, required to get extension because of his daughter's illness and his own and he had sent communications as soon as it was possible for him to do to the employer. In my view this unchallenged evidence which is required to be considered because what is to be seen is whether the order of dismissal is not only legal but whether it is legal and justified. In my opinion it does not appear to be justified in the facts and circumstances of the case and the employer has apart from filing written statement has not taken any pains to assist this Tribunal in this proceedings and adduced any material in support of justification of such an order by adducing relevant material.

11. I will therefore, hold in favour of the wrokman on the first point about the justification of the order of dismissal.

12. The point that arises for consideration is with regard to the relief the workman is entitled to in the event the order is found to be not justified. The consequence is that he would be entitled to reinstatement and consequential benefits and back wages. I think the said relief will have to be granted to him which I grant.

Award accordingly.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1994

का.आ. 150.—जबकि दूर संचार विभाग, गुंटूर के प्रबंधन तथा उनके कर्मकार, जिसका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय दूर संचार कर्मकार संघ, लाइन स्टाफ और वर्ग "घ", गुंटूर दूर संचार, जिला—गुंटूर कर रहा है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और जबकि, उक्त प्रबंधन और उनके दूर संचार कर्मकार संघ जिसका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय दूर संचार कर्मकार संघ, लाइन स्टाफ और वर्ग "घ", द्वारा किया जा रहा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10—क की उपधारा (i) के अंतर्गत एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को न्याय-निर्णयन हेतु भेजने पर सहमत हैं और उक्त विवाचन करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेज दी है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त करार को प्रकाशित करती है :—

करार

(औद्योगक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10—क के अंतर्गत)

के बीच

पक्षकारों के नाम

नियोजक के प्रतिनिधि	कर्मकारों के प्रतिनिधि
श्री जी. आई. दयार्धन एस डी ओ (टी), महाप्रबंधक का कार्यालय, दूरसंचार, गुंटूर	श्री बी. वी. एस. राजू पुत्र श्री बुची, एरिया सेक्रेट्री, ए. आई. टी. ई. यू., लाइन स्टाफ एण्ड ग्रुप "डी" गुंटूर क्षेत्र

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को विवाचन के लिए श्री ए. प्रभाकर राव, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.) हैदराबाद के पास भेजने की सहमति हो गयी है :—

(1)	विवाद के विशिष्ट मामले	श्री पी. कोटेश्वर राव, पूर्व-नैमित्तिक मजदूर की सेवाओं की अभिकथित अवैध छंटनी
(2)	प्रबंधन का नाम	एस. डी. ओ. (टी.), महाप्रबंधक दूर संचार, गुंटूर
(3)	कर्मकार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में ग्रस्त है अथवा संघ का नाम, यदि कोई हो, जो संबंधित कमकारों का प्रतिनिधित्व करता हो।	श्री वी. वी. एस. राजू, सेक्रेट्री, ए. आई. टी. ई. यूनियन लाइन स्टाफ एण्ड ग्रेड "डी"
(2)	प्रबंधन का नाम	एस. डी. ओ. (टी), महाप्रबंधक का कार्यालय, गुंटूर
4)	उपक्रम में नियोजित प्रभावित कर्मकारों की कुल संख्या	शून्य
(5)	विवाद से प्रभावित अथवा प्रभावित होने वाले कर्मकारों की अनुमानित संख्या	शून्य

विवाचक अपना पंचाट तीन माह के भीतर अथवा हमारे बीच हुए परस्पर लिखित करार द्वारा आगे बढ़ायी गयी अवधि के भीतर देंगा। यदि उपरोक्त अवधि के अन्दर पंचाट नहीं दिया जाता है तो विवाचन के लिए भेजा गया विषय स्वतः निरस्त हो जाएगा और हम नए सिरे से विवाचन के लिए वार्ता करने को स्वतंत्र होंगे।

प्रबंधन की ओर से	संघ की ओर से
ह./- (जी. आई. दयार्धन राव) एस. डी. ई. (टी.). महाप्रबंधक का कार्यालय, दूर संचार, गुंटूर	ह./- (वी. वी. एस. राजू) एरिया सेक्रेट्री, लाइन स्टाफ एण्ड ग्रुप "डी", गुंटूर क्षेत्र

(विवाचक की सहमति)

विषय : औद्योगिक विवाद अधिनियम—दूर संचार विभाग, गुंटूर के प्रबंधन और उनके कामगार श्री पी. कोटेश्वर राव, पूर्व नैमित्तिक मजदूर के बीच अभिकथित गैर-कानूनी तरीके से उनकी सेवा समाप्त करने पर औद्योगिक विवाद—धारा 10—क के अंतर्गत विवाचन हेतु सहमति—के बारे में

आज प्रातः सहायक श्रमायुक्त (के.), हैदराबाद के साथ टेलीफोन पर हुई वार्ता के संबंध में, मैं अधिनियम की धारा 10—क के अंतर्गत उपर्युक्त विवाद में विवाचन के लिए अपनी लिखित सहमति देता हूं।

ह./-
(ए. प्रभाकर)
क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.)
हैदराबाद

[सं. एल-10012/215/94-आई आर(डी यू)]
के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th December, 1994

S.O. 150.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Telecom Deptt. Guntur and their workman represented by the All India Telecom Employees Union, Line Staff and Group 'D', Guntur Telecom District, Guntur.

And whereas, the said management and their workman represented by All India Telecom Employees Union, Line Staff and Group 'D' have by written agreement under sub-section (i) of Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947, agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now-therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 10-A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)
Between

Name of the Parties

Representing Employer	Representing workman
Shri G.I. Dayardhana SDO(T), O/o Gen. Manager Guntur	Shri. V.V.S. Raju, S/o Shri Buchi Area Secretary AITEU, Line Staff & Group 'D' Guntur Area.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri A. Prabhakar, RLC(C) Hyderabad.

(i) Specific matters in dispute	Alleged illegal retrenchment of service of Shri P. Koteswara Rao Ex-Casual Mazdoor.
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking ;	General Manager, Telecom Department, Guntur.

(iii)	Name of the workman in case he himself is involved in the dispute of the name of the Union, if any, representing in question	Representing the workman. Sh. V.V.S. Raju Secretary, AITE Union Line Staff & Grade 'D'
(iv)	Total number of workman employed in the undertaking affected.	NIL
(v)	Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.	NIL

The arbitrator shall make his award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in sitting. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

On behalf of the management — On behalf of the union

Sd/- (G.I. Dayardhana Rao) SDE(T) O/o Gen. Manager Guntur

Sd/- (V.V.S. Raju) Area Secretary, Line Staff & Group 'D' Guntur Area.

CONSENT OF THE ARBITRATOR

Sub: I.D. Act I.D. between the management of Telecom Department Guntur and their workman Shri P. Koteswara Rao, Ex-Casual Mazdoor over alleged illegal termination of his service—Consent for Arbitration under Section 10-A—Reg.

In response to the telephonic call had with ALC(C) Hyderabad today morning, I am hereby giving my written consent for the Arbitration in the above mentioned dispute under Section 10-A of the Act.

Sd/-
(A. Prabhakar)
Regional Labour Commissioner (Central)
Hyderabad

[No. L-40012/215/94-IR (DU)]
K.V.B. UNNY, Desk Officer

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1994

का.आ. 151—जबकि दूरसंचार विभाग, गुडीवाड़ा के प्रबन्धन तथा उनके कर्मकार जिसका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय टेलिकॉम कर्मकार संघ, लाइन स्टॉफ और वर्ग "घ", विजयवाड़ा टेलिकॉम, विजयवाड़ा जिला द्वारा किया जा रहा है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और जबकि, उपरोक्त प्रबन्धन तथा उनके कर्मकार जिनका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय टेलिकॉम कर्मकार संघ, लाइन स्टॉफ और वर्ग "घ", द्वारा किया जा रहा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10—क की उप धारा (i) के अन्तर्गत एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए भेजने पर सहमत हैं और उक्त विवाचन करार की एक प्रति केन्द्र सरकार को भेजी है;

अतः अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10—क की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्र सरकार उक्त करार का एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अन्तर्गत)

इन पक्षकारों के मध्य पक्षकारों के नाम

नियोजक के प्रतिनिधि	कर्मकारों के प्रतिनिधि
श्री बी जगदीश बाबू, एस.डी.ओ. टेलिकॉम, गुडीवाड़ा	श्री बी. कोंड्डय्या, जिला सचिव, अखिल भारतीय टेलिकॉम कर्मकार संघ, लाइन स्टॉफ और वर्ग "घ" विजयवाड़ा टेलिकॉम, जिला विजयवाड़ा

पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित विवाद को विवाचन के लिए श्री ए. प्रभाकर, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.) हैदराबाद के पास भेजने की सहमति हुयी है ।

(1)	विवाद के विशिष्ट मामले	श्री जी. सिम्हादरी, भूतपूर्व नैमित्तिक मजदूर की सेवाओं की तथाकथित अवैध छंटनी
(2)	प्रबंधन का नाम	महाप्रबंधक, दूरसंचार (टेलीकॉम), गुडीवाड़ा
(3)	कमकार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में अन्तर्ग्रस्त है या संघ का नाम, यदि कोई हो, जो संबंधित कर्मकारों या कर्मकार का प्रतिनिधित्व करता हो ।	कर्मकार के प्रतिनिधि श्री बी. कोंड्डय्या, सचिव, अखिल भारतीय टेलिकॉम कर्मकार संघ, लाइन स्टॉफ और वर्ग "घ" विजयवाड़ा टेलिकॉम जिला-विजयवाड़ा
(4)	प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या	शून्य
(5)	विवाद से प्रभावित अथवा प्रभावित होने वाले कर्मकारों की अनुमानित संख्या	शून्य

विवाचक अपना पंचाट तीन माह के भीतर अथवा हमारे मध्य हुए परस्पर लिखित करार द्वारा आगे बढ़ाए गए समय

में देगा। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता है तो विवाचन के लिए भेजा गया विषय स्वतः निरस्त हो जायेगा और हम नए विवाचन के लिये वार्ता करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

प्रबंधन की ओर से	संघ की ओर से
ह./-	ह./-
(बी. जगदीश बाबू)	(बी. कांडय्या)
एस.डी.ओ. टेलिकॉम, गुडीवाड़ा	जिला सचिव, अखिल भारतीय टेलिकॉम कर्मकार संघ, लाइन स्टॉफ और वर्ग "घ" विजयवाड़ा टेलिकॉम, जिला–विजयवाड़ा

विवाचक की सहमति

विषय :—औद्योगिक विवाद अधिनियम—टेलिकॉम विभाग, गुडीवाड़ा के प्रबंधन और उनके कर्मकार श्री जी. सिम्हादरी, भूतपूर्व—नैमित्तिक मजदूर के मध्य तथाकथित गैर-कानूनी तरीके से उनकी सेवा समाप्त करने पर औद्योगिक विवाद–धारा 10–क के अंतर्गत विवाचन हेतु सहमति ।

आज प्रातः, सहायक श्रमायुक्त (के.), हैदराबाद के साथ टेलिफोन पर हुई वार्ता के संबंध में, मैं अधिनियम की धारा 10–क के अंतर्गत उपर्युक्त विवाद में विवाचन के लिए अपनी लिखित सहमति देता हूं।

(ह./-)
(ए. प्रभाकर)
क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.)
हैदराबाद

[सं. एल–40012/216/94–आई आर (डी.यू.)]
के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 29 December, 9194

S. O. 151:—Whereas an industrial dispute exists between the management of Telecom Deptt. Gudivada and their workman represented by the All India Telecom Employees Union, Line Staff and Group 'D' Vijayawada Telecom District Vijayawada.

And whereas, the said management and their workman represented by All India Telecom Employees Union, Line Staff and Group 'D' have by written agreement under sub-section (i) of Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947, agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 10-A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

AGREEMENT

(Uhder Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

Between

Name of the Parties

Representing Employer	Representing workman
Shri B. Jagadish Babu SDO Telecom, Gudivada	Shri B. Kondaiah, District Secretary AITE Union Line Staff & Group 'D' Vijayawada Telecom District Vijayawada

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri A. Prabhakar, LRC(C) Hyderabad.

(i) Specific matters in dispute :	Alleged illegal retrenchment of service of Shri G. Simhadri Ex:Casual Mazadoor
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking;	Sub-Divisional Officer Telecom, Rajendranagar 2nd Line, Gudivada 521 301.
(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute of the name of the Union, if any representing in question	Representing the workman Sh. B. Kondaiah Secretary, AITE Union Line Staff & Grade 'D' Vijayawada, Telecom District Vijayawada
(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected	NIL
(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute	NIL

The arbitrator shall make his award within a period three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in sitting. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

On behalf of the management	On behalf of the Union
Sd/-	Sd/-
(B. Jagadish Babu) SDO Telecom, Gudivada	(B. Kondaiah) District Secretary AITE Union Line Staff & Group 'D', Vijayanada Telecom District Vijayawada

(CONSENT OF THE ARBITRATOR)

Sub : I.D. Act—I.D. between the management of Telecom Department Gudiwada and their workman Sh. G. Simahadri, Ex-Casual Mazdoor over alleged illegal termination of his service—Consent for Arbitration under Section 10-A—Reg.

In response to the telephonic call had with AI.C(C) Hyderabad today morning, I am hereby giving my written consent for the Arbitration in the above mentioned dispute under Section 10-A of the Act.

Sd/-
(A. Prabhakar)
Regional Labour Commissioner (Central)
Hyderabad)

[No. L-40012/216/94-IR(DU)]
K.V.B. UNNY, Desk Officer.

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1994

का.आ. 152.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-12-1994 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/35/91-आई.आर.बी-2]
वी.के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th December, 1994

S.O. 152.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bhubaneshwar as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of UCO Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 28-12-1994.

[No. L-12011/35/91 IR(B-II)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR

PRESENT :

Shri P. K. Tripathy, M.A.LL.B., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar.

Industrial Dispute case No. 40 of 1991 (Central)
Bhubaneswar, the 15th December, 1994.

BETWEEN

The management of UCO Bank,
UCO Bank Head Office,
12, Old Court House Street,
Calcutta-1. —First Party management.

AND

Their workmen represented through
UCO Bank Employees' Association,
C/o. UCO Bank Zonal Office,
25-A, Janpath (Ist Floor), Unit-III,
Bhubaneswar. —Second party-workmen.

APPEARANCES :

Sri D. Mukundan, Dy. Chief Officer—For the first PAD ..... party-management.
Sri P. Pappa Rao, Organising Secretary of the Association. —For the second party-workmen.

AWARD

..This case arises out of reference made by the Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred upon them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (for short 'Act') vide their Order No. L-12011/35/91-IRBI dated 10th December, 1991. The schedule of reference reads as hereunder and the following 25 persons have been described as the concerned workmen.

"Whether the action of the management of UCO Bank in not regularising the services of 25 workmen mentioned below is justified ? If not, to what relief are the workmen entitled to ?"

Sl. No.	Name
1.	K. C. Das
2.	Sankar Behera
3.	S. P. Nayak
4.	Ashok Kumar Singh
5.	Dasarathi Bagarti
6.	M. K. Mohanty
7.	Laxmidhar Parida
8.	G. P. Das
9.	Sukanta Jena
10.	Chandramani Prustry
11.	Subash Chandra Behera
12.	Sanatan Sahoo
13.	U. C. Pattnaik
14.	B. K. Sahoo
15.	Ramachandra Bagarti
16.	Nityananda Mohant
17.	P. K. Behera
18.	C. C. Das
19.	K. K. Gochhayat
20.	K. Sankar Rao
21.	Madan Mohan Acharya
22.	Ramakanta Mohanty
23.	Nimai Charan Rath
24.	Beguni Kerai &
25.	Gagan Nayak

2. At the out-set it may be mentioned that the UCO Bank Employees' Association (for short 'Association') at Bhubaneswar is representing the workmen and that Association and the management have consistently submitted that so far as it relates to Sri K. C. Das and B. B. K. Sahoo (vide the above serial Nos. 1 and 14 of the workmen), they have been regularised in service and therefore, they are no more the concerned workmen in the present dispute. Thus, for all practical purposes and while con-

sidering the issues, the case of those two workmen are not taken-up for consideration whereas the case of the remaining 23 workmen will be adjudicated.

3. It is also the undisputed fact that the workmen vide Serial Nos. 8 G. P. Das, 10-Chandramani Prusty and 18-C. C. Das have been refused employment from 29-8-91, 24-8-91 and 29-1-91 respectively. On the other hand, the remaining 20 workmen as per the aforesaid serial numbers are still continuing to work as casual workers in different branches of the management.

4. In their claim statement the workmen have inter-alia contended that in different branches of the bank in Orissa they were engaged as casual workers as against permanent vacancies but on casual basis on a paltry daily wage of Rs. 8 or Rs. 10 and inspite of the fact that each of them worked for much more than 240 days in several calendar years, yet they were not regularised in service nor they were paid better wage. Besides these workmen there were many more such casual workers engaged in different branches of the management functioning at different places in the State of Orissa and the Association took-up their cause and requested the management for regularising them in service and to pay wage rate of 1|30th of the basic scale of the Class-IV category on the principle of 'equal pay for equal job' as because, according to the Association, these casual workers were performing similar type of job like the Class-IV employees i.e., the sub-staff. When the management turned a deaf ear, the Association took-up the matter with the labour agency and raised a dispute before the Asst. Labour Commissioner (Central), Bhubaneswar. The conciliation proceeding taken-up by the A.L.C.(C) did not succeed and therefore, he reported the matter to the Central Government for making a reference. At that time there was a further bi-partite discussion between the management and the Association (who had espoused the cause of the casual workers) and it ended in a settlement dated 12-10-89 in which it was agreed upon by the parties to the settlement that those casual workers who satisfy the requirements and criterias detailly mentioned in the terms of settlement, would be regularised and for others a further discussion shall be made between the management and the Association. It is the further case of the workmen that in accordance with that settlement all the relevant casual workers applied for regularisation of their services in the prescribed proforma but the management while regularising the services of 134 casual workers did not favourably consider the case of the above-named 25 workmen (out of whom two have again been considered, in the manner stated above). The workmen contend that the management unreasonably refused to regularise their services on flimsy ground. They further contend that even if it is held that they do not fulfil the criterias in the settlement dated 12-10-89, yet because of their long service as casual workers spreading to several years, the management should have taken-up for consideration their demand for regularisation in in service and should not have made an attempt to remove them from service. In that connection, the workmen further contend that the above-named serial Nos. 8, 10 and 18 of the workmen were disengaged from the respective dates (as mentioned above) without following the procedure in Section 25-F of the Act. The workmen, thus pray to pass an Award in their favour for regularisation in service by empanelling them and until then to pay them wage as per the circular dated 31-3-90 by following the principle of 'equal pay for equal job'.

5. The sum and substance of the plea taken by the management in its written statement is that the present workmen are bound by the terms of the settlement dated 12-10-89 and they can not raise the present dispute. On that score the management challenged the maintainability of the present reference. The further contention of the management is that since the workmen do not come within the purview of the agreed criterias mentioned in the settlement dated 12-10-89, therefore, they can not be regularised in service nor they are entitled for such regularisation. It further states that the workmen were paid wages as per the provisions in the Minimum Wages Act and therefore, they should not have any grievance in that respect and so far as it relates to removal of the aforesaid three workmen and continuance of the remaining 20 as casual workers, the management contents that in terms of the settlement all these workmen should have been disengaged but because the workmen went to the High Court and obtained a stay order against the proposed action of disengagement, therefore, the 20 casual workers were allowed to continue by honouring the stay order of the Hon'ble Court and thereafter because of pendency of the present dispute. But so far as the above-named three workmen are concerned (Sl. Nos. 8, 10 and 18), they had already been lawfully disengaged by the date the stay order was communicated to the management. It further contends that the workmen are not entitled to the reliefs claimed.

6. On the basis of the aforesaid legal and factual backdrop, the following issues have been framed :—

ISSUES

(1) Is the reference maintainable ,

(2) Whether the alleged bi-partite settlement dated 12-10-89 is binding on the parties to the dispute ?

(3) Whether the action of the management of UCO Bank in not regularising the services of 25 workmen is justified ?

(4) To what relief, if any, the workmen are entitled to ?

7. The workmen have examined three witnesses and have tendered in evidence Exts. 1 to 9 whereas the management has examined one witness and has tendered in evidence Ext. A series to Ext. M in support of their respective contentions. The details of the evidence shall be discussed at the relevant places while adjudicating the issues.

8. The issues are inter-linked with the another, hence they are taken-up together for consideration.

So far as the question of maintainability is concerned, it depends upon whether the settlement dated 12-10-89 i.e., Ext. L is binding on the workmen

and if that is so then what is the implication of paragraph-7 of the said settlement and whether the workmen are estopped from raising the present dispute. Similarly, it is to be considered whether refusal of employment to the workmen vide Sl. Nos. 8, 10 and 18 amounts to retrenchment and what is the effect of it and what remedies, if any, the concerned workmen are entitled to and simultaneously to what relief the other workmen are entitled to regarding regularisation in service and/or for payment of back wages and the rate of the wage. Thus, it is apparent from all the aforesaid facts and circumstances that much is dependant the manner in which Ext. L is to be read. Of course, if the language in Ext. L is plain and simple then the interpretation which is available from such plain reading is to be given.

9. On a joint reading of the evidence of W.W. Nos. 1 to 3, M.W. 1, Ext. B the list of casual workers empanelled as per the settlement (Ext. L), Ext. C alongwith the annexure-I i.e., the letter addressed to the A.L.C. with the list of casual workers in different branches and Ext. 9, the list of the present workmen showing their qualification, date of engagement and age on the date of their first engagement, it is found that by the date when the dispute was raised vide Ext. C, besides the 134 empanelled workers as per Ext. B, the present concerned workmen were also working as casual workers. The terms of the settlement, Ext. L in paragraph-2 has mentioned the eligibility criterias, viz :—

(1) A casual worker engaged for a period of 240 days or more with or without interruption during the period of three years immediately preceding the settlement are the casual workers who would be considered for absorption and while computing the days, the holidays and Sundays falling in the week in which such casual workers had been engaged would be counted in favour of the worker.

(2) Such casual worker should have the minimum and maximum age of 18 and 26 years respectively on the date of his first engagement as casual worker (underlining is to give emphasis).

(3) Educational qualification should not be below VIIIth standard but the worker should not have passed S.SL.C. or equivalent examination on the date of his first engagement as casual worker. However, relaxation in that matter was granted by blocking promotional prospect.

Paragraphs 4 and 5 of that settlement mention regarding the empanelment and thereafter paragraphs 6 & 7 mention about the pending disputes and the same is quoted as hereunder :—

"6. Pending Disputes.—Any person eligible for absorption under this settlement shall withdraw any case pending before any Conciliation Officer Labour Court Tribunal or any other Court of law and his claim, if any, shall be deemed to have been settled in terms of this settlement. Upon any person applying for absorption in terms of this settlement shall be deemed to have accepted the benefits under this settlement in full satisfaction in respect of any pending dispute or claim. He shall not be eligible for any benefits beyond what is stipulated in this settlement.

7. Parties agree to discuss and resolve disputes pending as on date before any Conciliation Officer, Labour Court, Tribunal or any other Court of Law in respect of claims for appointment or wages by person or by union representing such persons based on their working in the Bank on casual basis if such persons are not covered under this settlement".

10. Interpreting the aforesaid paragraphs 6 & 7, the workmen contend that since they were not absorbed in terms of the settlement, therefore, their case is still wide open for consideration by the management and the settlement does not estop them from raising this dispute. On the other hand, the management contends that in view of the settlement in paragraph-6 to the effect that "Upon any person applying for absorption in terms of the settlement shall be deemed to have accepted the benefit under this settlement in full satisfaction in respect of any pending dispute or claim and he shall not be eligible for any benefit beyond what is stipulated in this settlement" and in view of the fact that the present workmen had made applications for empanelment vide Exts. A to A/23, they are estopped from raising any dispute after rejection of their applications being not falling within the eligibility criterias as mentioned in pragraph-2 of the settlement). The management further contends that Ext. 9 clearly says that the workmen vide Sl. Nos. 21 and 23 of the reference were over-aged by the date of their first engagement in the year 1988 and 1987 respectively whereas the remaining 21 workmen were all under-aged ranging from 14 to 17 years by the date of their initial engagement and as such, their case did not merit consideration in terms of paragraph-2 of the settlement. When they have availed that opportunity of applying and failed there, now they can not claim for regularisation in view of the binding force of the settlement. In that connection, the management has relied upon a decision reported in 1963 (II) LLJ page-647 (Sirsilk Ltd. Vrs. Govt. of Andhra Pradesh).

In the above-cited case the point for consideration before the Hon'ble Supreme Court was as to whether a settlement arrived after passing of an Award is operative in preference to the Award and whether in such a case the Award can be withheld from publication. While discussing that aspect of the law, Hon'ble Court have been pleased to consider the legal implications of a bi-partite settlement and have been pleased to propound that in view of the provisions of Section 18(1) & (3) and Section 19(1) of the Act, a settlement arrived at by agreement between the employer and the workmen otherwise than in the course of a conciliation proceeding is binding on them from the date of such settlement unless a date

of its enforceability is mentioned and that such settlement is binding on the parties to the settlement. The law being very clear on that point, the workmen have not disputed this legal position.

11. It is the admitted position from Ext. A series besides the evidence of the witnesses from both the sides that the presntly involved 23 workmen applied for regularisation of their services and for their empanelment on the basis of the settlement, Ext. L. Thus, in view of paragraph-6 of the settlement (Ext.L) the workmen are bound by the terms of the settlement. After coming to such a finding, it is to be seen whether in view of the provision in paragraph-7 of the settlement, the workmen are debarred or estopped in advancing a claim for regularisation in services.

As it appears, clause-7 of the settlement (Ext. L) is not ambiguous and on a plain reading of the same it appears that such casual workers who are not covered by the settlement can negotiate with the Bank for regularisation of services or settlement of their disputes. In other words, a person who is not covered by the settlement can not take advantage of clause-7 in Ext. L. That however, does not end the matter, in as much as, while recording such a finding the Tribunal should see if the terms of the agreement were properly implemented while considering the applications of the workmen. If such applications have not been properly considered, then certainly the workmen have a forum to agitate the same and being in seisin of that matter, the Tribunal has the jurisdiction to decide that issue.

12. According to the eligibility criterias in paragraph-2 of Ext. L, only of the criterias is that the concerned casual worker should have worked for 240 days with or without interruption within a period of three years preceding the date of settlement i.e. 12-10-89. Thus, a casual worker who was given casual employment for temporary period with extention from time to time with effect from 12-10-86, such a candidate can be considered for regularisation. It is the undisputed evidence available in record that each of the workmen have worked for more than 240 days between 12-10-86 to 12-10-89. At the risk of repetition it may further be noted that the public holidays falling within the weeks of engagement go to the credit of the casual worker. The further eligibility criteria which is relevant for the purpose of this case is that the casual worker should be above 18 years and below 26 years of age on the date of his first appointment. So far the term 'first engagement' is concerned i.e., to be given a beneficial interpretation without prejudice to the interest of the Bank and avoiding the narrow interpretation which was incorrectly made by the management It appears from Ext. 9 that ranging from 1982 till 1988, the 23 workmen were engaged and save and except Sl Nos. 21 and 23, the other concerned workmen were below 18 years of age by the date of their initial casual employment. The Bank has advanced the plea that the aforesaid workmen were engaged from time to time as and when there was requirement Therefore, the spell of engagement given on or after 12-10-86 should be computed as the commencement of the first appointment in view of the terms of the settlement. If that is so, then some of the workmen had completed the age of 18 years by 12-10-86 i.e., three years prior to the date of the settlement. Under such circumstance, their applications for regularisation though required to be considered, the same were wrongly rejected. Under such circumstance, the management must make a fresh assessment of the eligibility criteria in accordance with this guideline which is on the bais of a correct interpretation of the terms of settlement.

13. As it appears a few more workmen are still left over being not falling within the eligibility criteria so far the age is concerned. In view of the terms of the settlement a condition can not be imposed on the management so far as such workmen are concerned but it may be noted here that the management is a Nationalised Bank and is a Public Undertaking. The Government owes a responsibility as far as practicable to eradicate unemployment problem besides saving the man force i.e., casual labour from the system of exploitation. The management wants persons to be employed if they have the requisite qualification. The aforesaid ineligible workmen having past experience in service as casual workers and satisfying the minimum age requirement on the date of settlement should be favourably considered for regularisation in service, in as much as, after serving the management as casual workers for so many years they have lost the prospect of employment anywhere else. However, this is a matter left to the conscience of the management for equitable consideration.

From the dates available in Ext. 9 , a bare calculation of the age of 18 on 12-10-86 being made it appears to this Tribunal that so far as the workmen vide Sl. Nos. 2 to 8, 10, 11 and 13 are concerned by 12-10-86 they had the requisite minimum age as per clause 7 of Ext. L. Sl Nos. 21 and 23 were already over-aged whereas the remaining workmen attended the age of 18 after 12-10-86 but before 12-10-89.

14. As per the aforesaid discussion, it is held that though the workmen are bound by the terms of settlement, Ext. L, yet some of them being eligible to be regularised in service or for empanelment were not duly and properly considered and therefore, the reference is maintainable and the workmen are not estopped from challenging the dispute under reference.

15. The workmen Nos. 8, 10 and 18 as mentioned above have been retrenched by the management. This fact is an admitted position though on the basis of conflicting pleadings by both the parties, (which has already been noted in a preceding paragraph.) It appears from Ext. 7 that the Asst. General Manager directed the Branch Managers to disengage the ineligible casual workers and Ext. 7 relates to a similar direction for disengaging workman No. 10 According the workmen, the provisions in Section 25-F was not followed while making retrenchment of workmen Nos. 8, 10 and 18. On the other hand, the management contends that since their disengagement was in terms of the settlement (Ext. L) and Ext. 7 is a consequential correspondence, therefore, the management was not required to follow the provisions in Section 25-F of the Act. The workmen

have filed the decisions reported in A.I.R. 1976 S.C. Page-1111 (State Bank of India Vrs. N. S. Money), 1982 S.C.C. 649=1982 (I) LLJ page-330 (L. Robert D'Souza Vrs. Executive Engineer, Southern Railway), A. I. R. 1978 SC Page-8 (Delhi Cloth & General Mills Vrs. Sambhu Nath) and 1981 (3) S. C. C. Page 225=1981 (II) LLJ Page-70 (Mohan Lal Vrs. Bharat Electronics Ltd) regarding the interpretation and the principle to be followed in a case of retrenchment. It may be noted here that in the aforecited decisions though the facts and circumstances are distinguishable from the facts and circumstances of the present case, yet the principles propounded therein are applicable, in as much as, while interpreting the term 'retrenchment', the Hon'ble Court have been pleased to propound that even if a casual worker is abruptly disengaged after serving the Institution or organisation for a considerable period, then that is retrenchment and in such a case retrenchment without following the provisions in Section 25-F is illegal and in such cases the retrenched worker is entitled for reinstatement with back wages. So far this principle is concerned of course the management has not advanced any contrary contention. As has been noted above, the contention of the management on the other hand, is that the disengagement of workmen Nos. 8, 10 & 18 and for that matter such attempt made for the other workmen was in accordance with the terms of the settlement. It may be noted here that this plea of the management is not sustainable both legally and factually. So far as the factual aspect is concerned the management has not produced any record or document (appointment letters is orders) to show that employment was given to the workmen for any particular period by mentioning the last date of engagement. Hence, in absence of any such evidence, the provisions in Section 2(oo) sub-clause (bb) of the Act does not come to the aid of the management. Apart from that, the settlement Ext. L does not mention that the ineligible workers would be refused employment without following the procedure in Section 25-F of the Act. Even if such an expressive term would have been there in the settlement, then also enforceable, in as much as, the settlement is a contract between the employer and the employee and according to the provisions in Section 23 of the Indian Contract Act, 1872 the consideration or object of an agreement if forbidden by law or opposed to public policy, then such consideration are regarded as unlawful and unenforceable. Hence as has been mentioned above, if such a term would have been there, then also it being opposed to the provisions in Section 25-F and the public policy of the Government regarding satisfied mode for terminating time casual workers, such a clause would not have been enforceable. Be that as it may as has been noted above, in the terms of settlement (Ext. L) there is no specific agreement between the parties that those ineligible workmen would be retrenched without following the provisions in Section 25-F of the Act. Under such circumstance, when admittedly the management has not followed the provisions of retrenchment in Section 25-F, therefore, the retrenchment of workmen Nos. 8, 10 and 18 is found illegal and non-sustainable. Thus, they are liable to be reinstated, with back wages. It may be noted here that before retrenchment of any of the workmen the management is bound to follow the provisions in Section 25-F and 25-G of the Act.

16. The other point which falls for consideration is as to whether the workmen are entitled to equal wage for equal job done by them while being on casual employment under the management. In that connection, the contention of the management is that the workmen were engaged and paid daily wages as per the provisions, in the Minimum Wages Act and the minimum wages fixed by the State Government from time to time. In other words, the management has admitted that it has not paid wage equivalent to 1|30th of the minimum basis scale of a worker in Class-IV category. It is in the evidence of W.W. Nos. 1, 2 and 3 that all the workmen were performing the same and similar job like the other regular employees in the Class-IV category (sub-staff). On this score, the management has not challenged the evidence of the workmen. In this connection, the workmen have relied upon the decisions reported in 1986 LLJ page 134 = Vol. 52 (186) F. L. R. page-147 (Dhirendra Chamoli Vrs. State of U. P.), 1986 Lab. I. C. Page-551=Col. 52 (1986) Page-216 (S. Singh Vrs. Engineer-in-chief) and 1988 (1) LLJ Page-370 (Daily Rated Casual Labour Employed under P&T Dept. through Bharatiya Dak Tar Mazdoor Manch Vrs. Union of India and others). In each of the aforesaid three cited cases, the Hon'ble Supreme Court while considering the case of casual workers engaged by the Public Sector Undertakings have been pleased to propound that the fundamental principle of 'equal pay for equal job' should be followed and more so by the Public Sector Undertakings and Government Departments because they are the model employer. Thus, a contravention of that principle of natural justice and equity is reprehensible. Thus, on principle the claim of the workmen is accepted.

In this connection, the workmen have also relied upon the circular dated 31-3-90 which has been marked as Ext. 1 from the side of the workmen and |Ext. M from the side of the management. In paragraph-3 of that circular the management provided for a higher daily wage. Thus, when the management has accepted to pay a higher wage, the controversy does not remain as controversy any more. However, keeping in view my finding regarding regularisation of some more workmen, if not all it may further be mentioned that in paragraph-5 (a) of the settlement, Ext. L, it has been agreed upon by the parties that a person who is empanneled for absorption shall not be entitled to claim any benefits for higher wage or service or any other perquisites for the period he was engaged on casual basis prior to this absorption. Thus, the management may not grant the back wages by following the principle of 'equal pay for equal job' to such of the workmen who shall be empanneled in terms of this Award. This also governs the workmen Nos. 8, 10 and 18, if they are empanneled. In other words if these three workmen are reinstated in service and regularised or empanneled, then they may be paid back wages at the rate it was paid to the similar category of workers who were/are regularised. If not, these three workmen besides the other ineligible workmen (who would not be regularised being

ineligible) should be paid the wage at the rate of 1|30th of the minimum entitlement of a Class-IV employee (sub-staff) from the date of their initial engagement till the date of retrenchment, if any.

17. To sum-up the findings, it is held that the reference is maintainable and the workmen are entitled to maintain the same even on the face of the settlement, Ext. I, in view of the fact that the manament did not properly interpret the terms of the settlement. Thus, the casual workers who had attended the age of 18 years by 12-10-86 are required to be regularised in service if they fulfil the other conditions and those who do not fulfil that age requirement, the management should consider their case for regularisation in an equitable and sympathetic manner. So far as it relates to the retrenched workmen vide Sl. Nos. 8, 10 and 18 the order of retrenchment being illegal is declared so with a direction to the management to reinstate them in service with back wages. So far as the matter relating to equal pay for equal job, the management being a Public Sector Undertaking is bound to honour the principle of law of equity and Constitutional liability and must make payment of equal pay for equal job in the manner indicated in a preceding paragraph. However, when the matter relates to regularisation of service, keeping in view the condition in paragraph-5 of the settlement, the matter should be appropriately adjusted in the manner indicated in a preceding paragraph. Similarly, so far as the left out workmen are concerned, they should be paid equal pay in the aforesaid manner from the date of their initial engagement till they continue in service.

The issues are decided and the Award is passed accordingly.

Dictated & corrected by me.

P. K. TRIPATHY, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1994

का. आ. 153—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-12-94 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12012/94/86—डी II (ए) आई आर (बी-2)]

वी. के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 30th December, 1994

S.O. 153.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India and their workmen, which was received by Central Government on 29-12-94.

[No. L-12012|94|86-D.IIA|IR(B-II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (MP).

Case Ref. No. CGIT|LC(R)(2)|1987

BETWEEN :

Smt. Alka Richariya (Pandey) C|o Shri S. N. Pandey, 45, Chandra Shekar Azad Marg, Jhansi (MP).

AND

The Branch Manager, Union Bank of India, Satna Branch, Satna (MP).

PRESIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

APPEARANCES :

For Workman :—Shri J. P. Richariya.

For Management:—Shri S. K. Rao, Advocate.

INDUSTRY : Banking DISTRICT : Satna (M.P.)

AWARD

Dated : December, 9, 1994

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-12012|94|86-D.II(A) Dated 30th December, 1986 for adjudication of the following dispute :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Union Bank of India, in terminating the service of Smt. Alka Richariya (Pandey) w.e.f. 13-11-79 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. The case of the workman is that she was appointed as a Clerk in the Union Bank of India, Regional Office, Jabalpur against the regular and permanent vacancy; that the workman was allowed to work for a period of 180 days that the management has deliberately created temporary breaks in her service and the workman was terminated from service against the provisions of Sec. 25G and H of the I. D. Act. The workman prays that her termination being illegal and against the principle of natural justice she should be reinstated with retrospective effect & with all benefits thereof.

3. Management has specifically denied that Smt. Alka Pendey was appointed against the regular permanent post. Management has alleged that Smt. Alka Pandey has been employed as temporary clerk for temporary period for doing the work of temporary nature on daily wage basis. Management has specifically denied that the workman has worked for 180

days or that the break in her service was artificial. It is alleged by the management that the workmen has worked at Satna Branch from 4-10-78 to 31-10-78 for 28 days, from 1-11-78 to 29-11-78 for 29 days and from 1-12-78 to 30-12-78 for 30 days, total 87 days and she has worked in the year 1979 for 93 days. It is contended that the workman is not entitled for the benefit of Sec. 25F of the I. D. Act as she has not worked for 240 days in a calendar year and further because she was appointed on daily wages for temporary periods. It is also alleged by the management that the workman has raised the dispute after inordinate delay and as such she is not entitled to get any relief.

4. Workman and the management have also filed written arguments.

5. Smt. Alka Pandey has stated that she has worked for 182 days in the Union Bank, Satna Branch and the Bank deliberately made the breaks in her service so that she may not continue in service. The workman has not produced any document in support of her pleading in the statement of claim that she was appointed against the regular permanent vacancy. Even in her statement before the Tribunal she has not stated that she has worked on regular permanent post. As against this from the cross-examination of workman, Smt. Alka Pandey, it is clear that she was appointed for a limited period. Smt. Alka Pandey has further admitted that she applied in Banking Recruitment Board and could not succeed in that examination. Consequently, it is clear that Smt. Alka Pandey, was appointed for temporary work for temporary periods. Thus the nature of her service being contractual she was rightly terminated due to afflux of time. In this connection, it is pertinent to note that Smt. Alka Pandey has raised an industrial dispute after the period of eight years of termination of her service and no explanation such as inordinate delay in raising the dispute is given by the workman either in her statement of claim or by leading oral and documentary evidence.

6. It is observed in case of Guest Keen, William (P) Ltd. Vs. P. J. Sterling (AIR 1959 SC p. 1279 that the delay in raising the dispute is not barred but the delay will be definitely taken into account against the workman. The workman was on temporary post. She has not worked for 240 days in a calendar year. She has not filed or proved any document to show that her appointment was against the permanent vacancy. In respect of the delay of 8 years of raising an industrial dispute is material which indicates the falsity of her claim. The management has filed documents to show that the workman was appointed for temporary post. Consequently, the termination was just and proper.

7. Consequently, the reference is answered in favour of the management and as her termination was justified she is not entitled for any relief. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1995

का.आ. 154.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16-1-1995 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है (और अध्याय-5 और 6) धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है, के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला कानूर के तालुक तालीपरम्बा में राजस्व ग्राम कुरुमाटूर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

[संख्या : एस-38013/18/94-एसएस-1]

जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd January, 1995

S.O. 154.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 16th January, 1995 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala, namely :—

"The area within the revenue village of Kurumattur in Taliparamba taluk of Kannur District."

[No. S-38013/18/9-4-SS.I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1995

का. आ. 155.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार असिस्टैंट इंजीनियर पोस्टल सब डिवीजन, जलगांव के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नागपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/29/91-आईआर(डीयू)]

के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 1995

S.O. 155.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Nagpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Assistant Engineer P&T (Civil) postal Sub-Division, Jalgaon and their workmen, which was received by the Central Government on 30-12-1994.

[No. L-40012/29/91-IR (DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, NAGPUR

Presided by Shri S. J. Deshmukh, B.A.,LL.B.

Reference (CGT) No. 1 of 1991

Adjudication :

BETWEEN

The Assistant Engineer, P&T (Civil), Postal Sub-Division, Jalgaon .. Party No. 1

AND

Their workman Party No. 2

In the matter of reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

APPEARANCES :

Assistant Engineer—for Party No. 1.

Shri M. S. Choudhary, Representative—for Party No. 2.

AWARD

(Passed on 29th September, 1992)

This is a Reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act. 1947 made by Central Government for adjudication in respect of dispute between the employer in relation to the management of Postal Civil Sub-Division, Jalgaon and their workman. The dispute referred to for adjudication as per schedule is as under:

"Whether the action of the Asstt. Engineer, Postal Sub-Division, Jalgaon on behalf of the management in retrenching the services of Shri Vishwanath Daulat Suptd. only-wages/casual worker w.e.f 1-2-88 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. The statement of claim filed by the Party No. 2/workman i.e. Vishwanath Daulat Sapkal is at Exh. The applicant has submitted that he was selected as a Mazdoor on daily-wages on N.M.R. @ Rs. 13 per day vide letter dated 30-10-1986 by the Assistant Engineer, Postal Civil Sub-Division, Jalgaon. The applicant was in service continuously for more than a year during the period from 5-11-1986 to 31-1-1988. That the services of the applicant are terminated by the Assistant Engineer with effect from 1-2-1988 vide his letter dated 1-2-1988 without assigning any reason, notice or notice pay in lieu thereof and retrenchment compensation. That the Assistant Engineer did not follow the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 at the time of retrenchment of the applicant/Party No. 2.

3. That the industrial dispute was raised over the issue of illegal retrenchment of the applicant/workman and the same was represented before the Assistant Labour Commissioner (Central), Nagpur and Labour Enforcement Officer (Central), Bhusawal by Shri M. S. Chaudhari, Divisional Secretary, A.I.T.E.E. Union. Class-III, Jalgaon vide his demand notice dated 23-1-1989. During the period from 23-1-1989 to 9-7-1990 the said dispute was pending in the office of Assistant Labour Commissioner (Central), Nagpur. That the conciliation proceedings in the said dispute ended in failure. Failure report was submitted to the Secretary, Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by the Labour Inforcement Officer (Central), Bhusawal vide letter dated 13-2-1991. The Central Government considered that the said dispute is desirable to refer it for adjudication and, therefore the dispute has been referred to this Tribunal for adjudication.

4. The applicant submits that he was again appointed as a Mazdoor on daily-wages w.e.f. 3-6-1989 vide letter dated 3-6-89 by the Assistant Engineer, Postal Civil Sub-Division, Jalgaon. In this respect it is submitted that the appointment of the applicant as Mazdoor with effect from 3-6-89 is not reinstatement but re-engagement. The management at present is paying less wages to the applicant than that of the wages paid to him during 5-11-1986 to 2-6-1989. The applicant submits hat his termination with effect from 1-2-1988 is illegal and unjustified. Therefore, it is prayed that the applicant be reinstated with effect from 1-2-1988 with continuity of service and back-wages for the period from 1-2-88 to 2-6-89.

5. The Assistant Engineer, Postal Civil Sub-Division, Jalgaon vide Exh. 14 filed his reply to the statement of claim of the Party No. 2. Admittedly the applicant i.e. Vishwanath Daulat Sapkale was appointed as Mazdoor on daily-wages at Rs. 13 per day with effect from 30-10-1986. According to the Party No. 1 management the appointment was purely temporary and was liable to be terminated at any time without any notice. There is no dispute that the services of the applicant have been terminated with effect from 1-2-1988. It is denied that the applicant was continuously in service with effect from 30-10-1986. In this respect it is submitted that he was in service for 57 days in 1986, 322 days in 1987 and 53 days in 1988. The applicant has not done his duty continuously within the meaning of Sub-Section 2(a) (ii) of Section 25-B of the I. D. Act, 1947. It is submitted that termination order was issued as per special condition given in appointment order and as per the policy of Government not to employ and labour on daily-wages, as such there was no necessity to comply with the provisions of Section 25-F of the I. D. Act, 1947. Admittedly, the applicant has been re-appointed from 3-6-1989. According to the management the fact of re-appointment shows that the department has no grudge against the applicant. It is submitted that less wages are not paid to the workman. In short, it is submitted that there was no question of reinstatement of the applicant. His termination is legal and proper. There is no merit in the Reference.

6. As stated earlier the dispute referred to this Tribunal as per Schedule is as under :—

(1) Whether the action of the Asstt. Engineer, Postal Sub-Division, Jalgaon on behalf of the management in retrenching the service of Shri Vishwanath Daulat Sapkale, daily-wages/casual work w.e.f. 1-2-88 is legal and justified ?

(2) If not, to what relief the workman is entitled to?

My findings are as follows :

(1)) No.

(2) The applicant Shri Vishwanath Daulat Sapkal is entitled to reinstatement with continuity of service and back-wages.

REASONS

7. In this reference no oral evidence has been adduced by the parties. The party No. 2 has placed on record in all 12 documents as per list of documents Ex. 5. All these documents Exh. 21 to 32 have been admitted by the Party No. 1. The Party No. 1 has filed documents as per list Exh. 20 and all these documents Exh. 33 to 38 have been admitted by the party No. 2. I have heard oral submissions of Shri M. S Chaudhary, Divisional Secretary, A.I.T.E.E. Union, Class-III. Jalgaon for the applicant and the Assistant Engineer, Postal Sub-Division, Jalgaon, in person. On going through the record and the documents I find much force and substance in the submissions made on behalf of the applicant, party No. 2.

8. Following are the admitted facts on record. The applicant was appointed as a Mazdoor on daily-wages on N.M.R. @ Rs. 13 per day vide order dated 30-10-1986 (Exh. 22) by the Assistant Engineer, Postal Civil Sub-Division, Jalgaon. The services of the applicant came to be terminated by the Assistant Engineer vide his letter dated 1-2-1988 (Exh. 24). The applicant was again appointed as a Mazdoor on daily-wages with effect from 3-6-1989 vide letter dated 3-6-89 (Exh. 28).

9. It is not disputed that before terminating the services of the applicant compliance of provisions of Section 25-F of the I. D. Act was not done. Admittedly before terminating the services of the applicant no notice was served on him nor he was paid one month's pay in lieu of notice and retrenchment compensation. There is no dispute that prior to his retrenchment, the applicant was continuously in service of the management with effect from 30-10-1986 to 31-1-1988. The applicant alongwith Exh. 23 has filed statement showing the actual days on which he had performed duties. The statement shows that during the period from 5-11-1986 to 31-8-1988 the applicant has put in 405 days of continuous service. The applicant has completed continuous service of 317 days during the period from 1-2-1987 to 31-1-1988. It is thus clear from the said statement that the applicant has completed more than 240 days during 12 months preceding his date of termination. The case of the applicant is fully covered by the provisions of Sub-section 2(a)(ii) of Section 25-B of the I. D. Act, 1947. As the applicant was continuously in service with effect from 30-10-1986 for more than 240 days during the period of 12 calendar months preceding his termination, the party No. 1 ought to have complied with the provisions of Section 25-F of the I. D. Act, 1947 before terminating his service. The party No. 1 having failed to comply with the provisions of Section 25-F of the I. D. Act, the termination of the applicant with effect from 1-2-1988 is illegal and unjustified. It therefore, follows that the applicant is entitled to reinstatement with continuiy of service and back-wages. For the reasons stated above the Reference is answered accordingly.

10. In the result, the following Award is passed.

AWARD

The action of the Assistant Engineer, Postal Civil Sub-Division, Jalgaon on behalf of the management in retrenching the services of Vishwanath Daulat Sapkale, casual worker, with effect from 1-2-1988 is not legal and justified. The applicant/casual worker Shri Vishwanath Daulat Sapkale is entitled to reinstatement with continuity of service and full back-wages. The Party No. 1 is directed to pay Rs. 200 as cost to the applicant.

Nagpur :
Dated : 29th September, 1992
(B. R. Walekar)
For Secretary.

S. J. DESHMUKH, Presiding Officer

नई दिल्ली 3 जनवरी 1995

का. आ. 156.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण केन्द्रीय सरकार बम्बई मर्केनटाईल कोआपरेटिव बैंक लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण न. 1 बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-12-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल 12012/174/93/आई आर (बी-1)]
राजा लाल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 1995

S.O. 156.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1 Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Mercantile Co-op. Bank Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 26-12-1994.

[No. L-12012/174/93-IR (B-I)]
RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, BOMBAY

PRESENT :

Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-57 of 1993

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Bombay Mercantile Co-op. Bank Ltd.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Management—Shri Patel, Advocate.

For the Workman—Shri Inamdar, General Secretary of the Union.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra

Bombay, the 22nd day of November, 1994

AWARD

Government of India Ministry of Labour has by letter dated 27th August, 1993 referred dispute in the schedule, for adjudication under Section 10(1)(d) read with section 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bombay Mercantile Co-operative Bank Ltd., Bombay in terminating the service of Shri Khushnood Ahmed Naqvi, Asstt. Accountant w.e.f. 25-7-92 without issuing any charge sheet and without instituting and conducting any departmental inquiry is lawful and justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. Statement of claim has been filed under the signature of Ali Zafar Zia, General Secretary of the Bombay Mercantile Co-op. Bank workmen's Union and written statement thereto has been filed on behalf of the Bank by Shri Pathan Assistant General Manager Personnel. Matter has been now adjourned sine die.

3. However today on behalf of the parties an application has been made for taking the matter on board and it accompanied by a settlement reached between the Parties to the dispute. By way of final settlement payment has been already made and that fact is admitted before me by the General Secretary of the Union Shri Zakir Inamdar. The settlement is also signed by the workmen Khushnood Ahmed Naqvi and on behalf of the Management by Shri Pathan. Both of them admit their signatures. The Learned Counsel appearing on behalf of the Bank is also present today before me. In view of the settlement reached in accordance with the settlement Award.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, BOMBAY

Reference No. CGIT-1/57 of 1993

Bombay Mercantile Co-op. Bank Ltd.,

AND

Their Workmen.

May it Please this Hon'ble Court

The above matter appeared on the Board of this Hon'ble Court on 16-9-1994. On the said date, neither the Workman nor his Advocate were present.

In view of the above position, this Hon'ble Court informed the Advocate appearing for the Employer Bank that since neither the Workman nor his Advocate is present, the Court is not in a position to fix the next date in the above matter and that the Notices will be issued to both the parties fixing the next date.

In the meantime, the parties to the above reference have arrived at a settlement and pray that the above reference be taken on Board today and be disposed off in terms of the settlement.

BOMBAY,

Dated, this 22nd day of November, 1994.

Sd/-

For the Workman

Sd/-

For the Employer Bank

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 BOMBAY

Reference No. CGIT-1/57 of 1993

Bombay Mercantile Co-op. Bank Ltd.,

AND

Their Workmen

May it please this Hon'ble Tribunal.

It is respectfully submitted that Bombay Mercantile Co-op. Bank Workmen's Union and Shri Khushnood Ahmed B. Naqvi, do not desire to proceed further with the above reference in view of the amicable settlement arrived at between B.M.C. Bank Ltd. and Shri Khushnood Ahmed B. Naqvi. Shri Naqvi has agreed and accepted the payment offered to him in the letter No. 55/STF/5546 dated 25th July, 1992 in full and final settlement of all his dues. Accordingly, the Bank Management has on this day issued 4 fresh Pay Orders bearing Nos. 57/STF/HO/092225 for Rs. 6,519. 57/STF/HO/092226 for Rs. 65,190, 57/STF/HO/092227 for Rs. 15,559 and 57/STF/092228 for Rs. 5,257/25 respectively in full and final settlement of all the payments due and payable to Shri Naqvi which he has agreed and accepted in full and final settlement and has no claim of any nature including reinstatement in the Bank.

The parties to the above reference prays that in consideration of this Settlement arrived at the Hon'ble Tribunal be pleased to make an Award disposing off the above reference as not pressed.

Dated : 19th November, 1994.

For Management :

Sd/-
Illegible.

Sd/-
Shri Khushnood Ahmed B. Naqvi.

Sd/-
Shri Zakir Inamdar,
General Secretary.

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1995

का. आ. 157.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार असिस्टेंट साल्ट कमिश्नर तूतीकोरिन के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में लेबर कोर्ट तीरूनलवेली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-94 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल 42011/1/88 डी II(बी)/आई आर (डी यू)]

के. वी. वी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 1995

S.O 157.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Labour Court, Tirunelveli as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Assistant Salt Commissioner, Tuticorin and their workmen, which was received by the Central Government on 30-12-1994.

[No. L-42011/1/88-D.II(B)/IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE LABOUR COURT, TIRUNELVELI

PRESENT :

Thiru S. Ramalingam, B.A., M.S.W., B.L., Presiding Officer.

Wednesday, the 6th day of October, 1994

Industrial Dispute No. 27/92 (Madurai) 539/92 (Tirunelveli)

BETWEEN

The Secretary,
Central Salt Mazdoor Union,
36/12, Kamarajar Salai,
(Prakash Colony),
Sivanthakulam,
Tuticorin-628003. ...Petitioner.

AND

The Management,
The Assistant Salt Commissioner,
Office of the Asstt. Salt Commissioner,
Post Box No. 46, Tuticorin-628001. ...Respondent.

This Industrial Dispute coming on this day for final disposal before me in the presence of Thiru G. Maniachari, Authorised Representative for the petitioner, and Thiru T. Gabrial Raj, Government Pleader, Advocate for the Respondent having stood over this day and this court made the following :—

AWARD

The dispute between the employers in relation to the management of Assistant Salt Commissioner, Tuticorin and the workmen was referred for adjudication under Clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947) as per order of the Government of India, Ministry of Labour in No. L-42011/1/88-D. II(B)/IR(DU), dated 9-1-1992 to decide the point,

"Is the Assistant Salt Commissioner, Tuticorin justified in refusing regular employment to the 12 workmen (list enclosed) on the ground that they are employed to maintain salt platform mazdoor on behalf of the licensees and their appointment is made by the department only for the purpose of annual estimates? If not, to what relief the concerned workmen are entitled to?"

1. The petitioner's case in his claim statement is as follows : Thiru A. Arulanandam and 11 others have been employed permanently as Platform Mazdoors in the Assistant Salt Commissioner for the last 10 to 30 years and their work is of permanent nature, and they have been working under the direct control and supervision of the respondent and other officers of the management concern, on a very low meagre wages. So the petitioner union has been continuously submitting demands before the respondent on behalf of the above said 12 employees for the enhancement of wages, bonus and for better emoluments and service conditions. The respondent was not considering the reasonable demands of the employees and the petitioner union raised the issues as Industrial Dispute before the Regional Labour Commissioner, Madras and the Assistant Labour Commissioner, Trivandrum. Meanwhile as per the direction of the Ministry of Law, the above said dispute was again taken by the Labour Department under the I.D. Act, 1947. No settlement was arrived

at before the Assistant Labour Commissioner, Trivandram the dispute was referred for adjudication to this Court. The said employees have been working continuously and without any interruption for a pretty long period directly by the respondent only for maintaining the salt storage platform even though the wages are being paid in the name of the licencees. The nature of work of these employees is of a permanent one and not casual or temporary as falsely alleged. Hence they ought to have been made permanent after the completion of 240 days work in a year and should be regularised as Group 'D' employees as per 1973 bulletin. But it is regretted to note that the concerned employees have been wrongly listed as employees of licensees and hence it is only a misnomer and they are entitled to be regularised and paid as such with all benefits with retrospective effect from the date of the completion of 240 days from their date of appointment as per the rulings laid down by the Supreme Court, High Court and Industrial Courts of the country. Hence the petition.

2. In the counter filed by the respondent, it is contended as follows : The petition is not maintainable either in law or on facts. The 12 Platform Mazdoors are working for the past several years under the supervision of Salt Department Officials at various places. The wages are fixed as per the rates of wages prescribed by the State Public Works Department from time to time. Salt Department under the Ministry of Industry, Government of India is responsible for monitoring the production and supply of salt in the country. The Platform Mazdoors are engaged for maintaining the Salt Storage Platform on daily wages basis on behalf of the Salt Licencees as per Rule 121, 129 and 130 of Central Excise and Salt Act, 1994 and the amount of wages paid are being recovered from the licences by way of a special cess. This method is adopted when the platform and Drying Grounds are used jointly by number of licensees. In case of single licensee of large scale salt works, it is left to the licensees themselves to maintain them. The expenditure is first met by the department by sanctioning annual maintenance estimate and the rate of wages paid in as per the public works department schedule of rates for the District on which the factory is located. Thus the platform mazdoors are neither regular employees of the establishment nor casual labours. The Platform Mazdoor are engaged are not covered by factories Act. Employees Provident Fund Benefits have been extended to them on voluntary basis Employees Contribution is also met the licensees by providing for their item in the Annual Maintenance Estimate. As the licensees with smaller holdings could not combine and maintain the platform, the Department has all along been executing their work on behalf of the beneficiary licensees and recovering the proportionate cost from them. The Platform Mazdoor are engaged on daily wages basis as per sanction under and estimate framed for the purpose. So the role of department is only as an employing agency on behalf of the minor licensees who are not in a position to execute works of common interest viz., maintenance of platforms and drying grounds as per Rules 121 and 130 of Central Excise Rules, 1944. The Mazdoor are not governed by any Acts or Rules framed for the regular Government servants and they also do not hold any regular post as such with a fixed scale of pay under Government. The Mazdoors are not covered by the General terms and conditions for employment of casual labour in the Government organisations like post & Telegraph, Railways etc. Therefore the petitioner (12 workmen) is not entitled to get any relief.

3. The points that arise for consideration in this petition are :

1. Whether the refusal of regular employment to the 12 workers by the Assistant Salt Commissioner is justified ?

2. Whether the petitioners/workers are entitled to regularisation and arrears of wages with attendant benefits ?

3. To what relief, the petitioners are entitled ?

POINTS 1 to 3—On behalf of the 12 workers whose names are given in the annexure attached to the claim petition of the Secretary, Central Salt Mazdoor Union, Tuticorin represented by its Secretary has filed this claim petition claiming benefits of regularisation from the date of appointment of the workers and other accruing benefits. The consistant stand taken up by the petitioner Union is that these 12 workers have been working under the Assistant Salt Commissioner, Tuticorin for more than several years as mazdoors. The dates of appointment of these 12 workers also have been stated in the said annexure. As per this annexure, the worker Jeyaraman had been appointed on 1-7-1933 and Kandasami has also entered into service on the very same day. Anthonimuthu appears to have entered into service on 1-7-1923 as per this list. Thus they claim that they had put in more than four decades of service and that in spite of their long service, they have not been regularised. This is their grouse and crumbling of the workers. The Services claimed by these petitioners/workers as per the annexure have not been challenged or controverted to by the respondent. In para 2 of the counter filed on 4-11-1992 it had been categorically admitted that these 12 platform workers are working for the past several years under the supervision of Salt Department Officials at various places. Therefore their working under the Salt Department is admitted in the counter. We find further admission in the counter to the effect that they are working under the Salt Department. One of the workers by name Arulanandam has also afforded evidence as W.W.1 to the effect that the workers have been appointed several decades ago and they are working directly under the Salt Department. His evidence is that in the event of any disciplinary proceedings etc., they used to be served on them by the Salt Department Officials. He claims in his evidence that they have been given housing facilities and earned leave benefits. His evidence though cross-examined has not been shown as false. To rebut the evidence afforded by this workers, no rebuttal evidence has also been let in by the respondent/Salt Department. So, the cumulative effect that will emerge from the unrebuttal evidence of the worker Arulanandam as P.W. 1 coupled with the admission made in the counter itself is that these persons have been or are working under the supervision of the Salt Department officials for several decades and they have been working as daily rated employees or mazdoors.

While the respondent Department had not let in oral or documentary evidence, the workers were able to produce documents from which there can be no other conclusion except feeling that due representation made by the workers have been recognised by the Government itself regarding the regularisation of these workers. The office of the Deputy Salt Commissioner, Madras as per its proceedings dated 28-12-1981 under Exhibit W.3 addressed to the Secretary Central Salt Mazdoor Union says that they are eligible to leave benefits. The Central Board of Excise and Customs as per its Official Memorandum dated 10-9-1993 under Exhibit W. 16 has stated that the workers who have put in one year of continuous service in Central Government other than the Government of Telecommunication on and Postal and Rail way may be regulated by one scheme as appended. Even as per this circular the petitioners/workers are entitled to be regularised as they are doing the very same work like other permanent employees. That apart on the workers side, a catena of rulings rendered by our Apex court had been pressed into service to bring home the point beyond the shadow of doubt. In the Supreme Court ruling reported in (1988) 72 F.J.R (S.C.) Page 124 National Federation of P & T Employees and another v. Union of India and another, it has been held as following State shall in particular strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only among individuals but also amongs groups of people residng in different areas or engaged in different vocations. The classification of employees into regularly recruited employees and casual employees for the purpose of paying, less than the minimum pay payable to employees in the corresponding regular address particularly on the lowest rungs of the department where the pay scales were the lowest was not tenable. The further classification of casual labourers into three categories, viz., (i) Those who had not completed 720 days of service (ii) those who had completed 720 days of service and not completed 1200 days of service; and (iii) those who had completed more than 1200 days of service for the purpose of payment of different rates of wages, was equally not tenable. Such a classification was violative of articles 14 and 16 of the constitution. It was also opposed to the spirit of article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, which exhorted all States to ensure fair wages and equal wages for equal work. Therefore the workmen employed as casual

labourers should be paid at the rates equivalent to the minimum pay in the pay scales of the regularly employed workmen in the corresponding cadres with the dearness allowances and additional dearness allowance if any payable thereon." After delivering the judgement on October 27 1987, the Apex Court had reiterated the same principle in yet another ruling reported in (1988) 72 FJR (S.C.) Page 175 U.P. Income Tax Department Contingent and Staff Welfare Association v. Union of India and others. Again the Apex Court had held in the ruling reported in 1990 I LJ Page 320 Bhagwati Prasad and Delhi State Mineral Development Corporation that these type of persons or workers are entitled to be regularised. Having regard to these principles enunciated by the Apex Court and taking into consideration the admissions made by the respondent that these persons/workers have been working directly under the Salt Department there could be no doubt that these workers are entitled to be regularised from the date of their appointment as stated in the annexure itself. Therefore the following workers viz., S. Cheeliah, M. Javaraman. P. Ramalakshmanan M. Kandasamy, C. Anthonymuthu and A. Savarimuthu had already been retired after their age of 60 years. So far as these persons are concerned they are entitled to regularisation benefits with arrears of pay and other attendant benefits. As regards the rest of the persons, they are entitled to be made permanent and to be paid the arrears of salary and other attendant benefits from the date of their appointment Hence, I answer point No. 1 in the negative and I hold that the refusal of regular employment to the 12 workers by the Assistant Salt Commissioner is not justified. I answer point No. 2 and 3 in the affirmative in favour of the petitioners.

In the result the petition is allowed. The petitioners/workers S. Chelliah M. Javaraman, P. Ramalashmanan, M. Kandasamy, C. Anthonymuthu and A. Savarimuthu are entitled to regularisation benefits from the date of their appointment with arrears of wages and other attendant benefits. The rest of the workers/petitioners are entitled to be made permanent from the date of their appointment by the respondent and they are entitled to arrears of salary and other attendant benefits. No costs.

Dictated to the steno-typist transcribed by him, corrected and pronounced by me in open court this the 6th day of October, 1994.

THIRU S. RAMALINGAM, Presiding Officer

LIST OF WITNESSES EXAMINED:

For Petitioner side : WW1 Thiru A. Arulanantham.

For Respondent Side : Nil.

Exhibits marked by the Petitioner side:

Ex. W.1—Failure of conciliation report Dt. 31-12-1987

Ex. W2—5-3-1983 Respondent Notice

Ex W.3—28-12-81 Respondent Letter.

Ex. W.4—7|10-11-86 Govt. of India, Ministry of Industry Letter.

Ex. W.5—7-11-88 Respondent Letter

Ex. W.6—22-10-74 Respondent letter.

Ex. W.7/2-8-74 Tamil Nadu Government National Employment Organisation Letter.

Ex. W.8—14-8-75 Respondent Order.

Ex. W.9—30-1-78 Petition.

Ex. W.9A—Acknowledgement card

Ex. W. 10—9-3-87 Petition.

Ex. W. 11—25-5-87 Management Letter.

Ex. W.12—3-8-87 Management Letter.

Ex. W. 13—18-8-87 Petition.

Ex. W. 14—14-12-87 Assistant Labour Commissioner, Trivandrum Letter.

Ex. W. 15—31-12-93 Failure of conciliation Report.

Ex W.16—10-09-93 Issued by the Under Secretary and Director, Central Board of Central Exist.

Ex.W.17 2 Xerox copy mof the OM dated 11-7-74 issued by Department of Personnel & Administrative.

Ex.W.18 Extract of the letter dated 6-6-1974 issued by Ministry of Labour Directorate of Employment and Training.

Ex.W.19 Transfer order issued to the petitioner Sri. Kandasamy for the Superintendent of Salts Tuticorin Dated 3-4-92.

Ex.W.20 Relief report dated 4-4-92 issued by Salt factory Officer, Arasarady.

Ex.W.21. Copy of the letter dated 1-1-92 of the Deputy Salt Commissioner.

Ex.W.22 The order of the appellate authority of the payment of gratutity Act, 1972.

Ex.W.23 Transfer order issued to WW1 Sri Arulanandam dated 3-8-75 by the authority of the Karapad dsalt factory.

Ex.W.24 Notice dated 3-7-91 issued by Deputy Superintendent of Salt to W.W.1 the petitioner Sri Arulanadam

Ex.W.25 Letter date 9-1-84 issued by the Superintending of Salts Cuddalore Circle to the Secretary of the petitioner.

Ex.W.26 Circular dated 28-2-89 of the Assistant Salt Commissioner, Tuticorin.

Ex.W. 27 Application letter of the Assistant Salt Commissioner Tuticorin to WW1 petitioner Arulanandam dated 8-12-89.

Exhibits marked by
Respondent side : NIL

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1995

का. आ. 158.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार टैलीकॉम फैक्ट्री, बम्बई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, न. 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/96/89-आई आर (डी यू)]

के. वी. वी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 1995

S.O. 158.—In pursuance of Sectoin 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom Factory, Bombay and their workmen which was received by the Central Government on 30th December, 1994.

[No. L-40012/96/89-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, BOMBAY

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-36 of 1989

PARTIES :

Employers in relaion to the management of Telecom Factory, Bombay

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Management—Shri Masurkar, Advocate.

For the Workman—Shri Jain, Union representative.

INDUSTRY : Post & Telegraph. STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 16th day of December, 1994

AWARD

Government of India, Ministry of Labour has made following reference under section 10(1)(d) read with subsection 2A of tht Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Telecom Factory, Bombay in not promoting Mr. A. S. Joglekar and Mr. M. R. Malkar as Inspector in the inspection department on regular basis as per the result declared on 30th January, 1986 is justified ? If not, what relief both these workmen are entitled to ?"

2. All India P&T Industrial Workers' Union, Telecom Factory Branch, Bombay has filed statement of claim under the signature of its Asstt. Secretary, Shri Jain. It is stated therein that S/Shri M. R. Malkar and A. S. Joglekar were serving in the Inspection Department of the Telecom Factory as Inspectors. They have a grievance because they were not promoted to the regular post of Inspector with effect from 1st January, 1987 and the management promoted another workman, Shri C. S. Chogale as Inspector though he was junior to the two workmen S/Shri Malkar and Joglekar. Shri Malkar's No. 8861/13 while Joglekar 8803/13 and that of Shri Chogale is 8809/13.

3. To prepare a panel in Insnection Department Shop No. 13 of the factory, a notice dated 29th October, 1985 was issued by the management for three posts of Insnector. Out of three one was for Scheduled Caste and two for unreserved category candidates. There was no reservation for Scheduled Tribes candidate in this notification. It also mentioned clearly that the candidates applied for reserved posts have to submit proof that they are belonging to the reserved category. Trade test was held on 20th January, 1986. Shri Chogale had also appeared for the trade test which was held on that day. He further appeared under unreserved category.

4. Result was declared on 30th January, 1986 mentioning the names of candidates who have qualified in the trade test are kept on the panel of approved candidates in the order of seniority. In that list of candidates appearing as against Shri Chogale it is mentioned that he belonged to Scheduled Tribe category. Inspite of the fact that he was junior to Shri Malkar and Shri Joglekar as shown in that list and inspite of the fact that he did not belong to the Scheduled Caste for which tthe post was reserved he came to be appointed to officiate as Inspector with effect from 1st January, 1987 in the vacancy caused by the death of Shri Kakde. The grievance of these two workmen S/Shri Malkar and Joglekar is that the record also did not show that Shri Chogale belonged to Scheduled Tribe.

5. The justification that is given by the management by written statement is that Shri Chogale belonged to Scheduled Tribe, that there was a vacancy for Scheduled Tribe candidate and it was carried forward since 1977 for non-availability of Scheuled Tribe candidate and therefore, filled in by Shri Chogale who belonged to Scheduled Tribes and when no Scheduled Caste candidate was available for filling that vacancy. It is admitted that in the notification issued it was not mentioned that one post was reserved for Scheduled Tribe. But the management states that it is a minor lapse and does not vitiate the action in filling of the vacancy by a Scheduled Tribe candidate. It is permissible to interchange because of the notification by M.H.A. Office M. No. 27/25/68-Estt. (SCT), dated 25th March, 1970. It is denied that the office record did not show that Shri Chogale belonged to Scheduled Tribe. He appeared and passed and filled in the vacancy which was reserved for Scheduled Caste but was interchangeable with Scheduled Tribe which was lying vacant since 1977 for non-availability of Scheduled Tribe candidate. The roaster, according to the management will show that the vacancy could not be filled up from 1977 to 1987 and out of the 22 points 20 points have been occupied by the unreserved category candidates and one point each by Scheduled Caste and Scheduled Tribe remained unfilled. There is still deficiency in reserve category of Scheduled Caste.

6. Further written statement has been filed on behalf of the workmen reiterating the earlier contention and refuting allegations made in the written statement. It is contended that the roaster prepared is not authentic and cannot be relied upon.

7. There is no dispute on the point that S/Shri Malkar and Joglekar were senior to Shri Chogale. There is further no dispute on the point that in the trade test held they qualified themselves and therefore, their names were kept on the panel of the approved candidates. Shri Chogale was also qualified and placed on that panel of approved candidates. Since he was junior to S/Shri Malkar and Joglekar and also junior in the seniority list it is contended on behalf of the workmen that he should not have been promoted in preference to Malkar and Joglekar. The order promoting S/Shri Chogale, Malkar and Joglekar has been produced at Exh. 'A' and that document is dated 18th October, 1994. That clearly shows that Shri Chogale was promoted with effect from 1st January, 1987 and Shri Malkar promoted with effect from 22nd August, 1988 and Shri Joglekar promoted with effect from 28th November, 1989. Therefore, obviously the management has to justify this action and it is there that the workmen have been contending the management has not succeeded in doing so.

8. The management tries to justify this action on the ground that Shri Chogale belonged to the Scheduled Tribe category, that vacancy therefore, was filled in by a Scheduled Tribe candidate Shri Chogale. On the other side it has been contended that in the notification issued on 29th October, 1985 inviting applications for selection of candidates for three posts it was not mentioned that there is a reserved post for Scheduled Tribes candidate. On the contrary, what is mentioned is that out of three posts one is for Scheduled Caste and two for unreserved. Therefore the management could not have taken up a Scheduled Tribe candidate in that vacancy meant for Scheduled Caste candidate. To this the reply is the roaster shows that Scheduled Tribe candidate was not available since 1977 for filling up the vacancy and that was carried forward since then till Shri Chogale came to be appointed in 1987. Therefore though the vacancy was reserved for Scheduled Caste candidate and since Scheduled Caste candidate was not available the same should be filled by Scheduled Tribe candidate.

9. In support of this contention an extract Exh. 'D', Ministry of Home Affairs O.M. No. 27/25/68-Estt. (SCT) is produced. It deals with the case of the period for carrying forward of reservations and exchange of vacancies between Scheduled Caste and Scheduled Tribe in the year to which the served vacancies are carried forward. However, it is subsequently mentioned that while advertising or notifying a vacancy which has been carried forward to the third year, it should be made clear in the advertisement/requisition that while the vacancy is reserved for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates would also be eligible for consideration

in the event of non-availability of suitable Scheduled Caste candidates. Obviously this had not been done in the requisition issued by the management on 29th October, 1985. It clearly shows that out of the three posts one is for Scheduled Caste. It does not mention that this vacancy is carried forward since 1977 or from any year and that if it could not be filled in by Scheduled Caste candidate it would be filled in by Scheduled Tribe candidate. Therefore, reliance upon this memorandum will not be good. Proposal was given by the Asstt. Labour Commissioner to conduct another test indicating the clear vacancies reserved for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidate but the same was not acceptable to the management. The union was agreeable for arbitration also but the same was not acceptable to the management. The management is not in my opinion justified in contending that the vacancy could be filled in by a Scheduled Tribe candidate in the circumstances and has been rightly filled in.

10. It is also to be noted that the vacancy occurred because of the death of Shri Kakde. That is clear from the order dated 9th February, 1987. Shri Kakde died on 31st December, 1986. Results were declared on 30th January, 1986. Therefore, to fill up this vacancy of Kakde, Shri Malkar who was seniormost was available. Shri Kakde was not belonging to the Ssheduled Caste or Scheduled Tribe and that position is not disputed. The roaster is not admitted by the union and there is no authetic material except true copy under the signature of the Personnel Officer, Telecom Factory. Union has also produced gradation list of Industrial Workers for Shop No. 13 as forwarded by Head Asstt. Establishment Section to the Secretary of the Union and Shri Chogale's name is to be found at Serial No. 7 in the column "state if Scheduled Caste or Scheduled Tribe". There is no mention that he belonged to Scheduled Tribe. The union therefore, is contending that in this list he has not be shown to be Scheduled Tribe candidate. However, in the panel prepared as against his name it is mentioned that he belonged to Scheduled Tribe. It may not be necessary for me to resolve this dispute because I am of the view that in the absence of mention in the notification that one of the posts was reserved for Scheduled Tribe it was not permissible for the management to fill up that post by a candidate for the Scheduled Tribe lynoring the fact that the vacancy arose because of the death of Shri Kakde who did not belong to the reserved category either Scheduled Caste of Scheduled Tribe. The justification given by the management, therefore, is not acceptable to me and in my opinion the two workmen will have to be given the relief namely that the senior Shri Malkar should have been promoted to the post filled in by Shri Chogale with effect from 1st January, 1987. The subsequent vacancy would go to Shri Joglekar. They are entitled to the wages on the basis that they were so promoted with effect from those dates and also would be entitled to be placed in the seniority with effect from those dates.

Award accordingly.

Sd/-

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1995

का. आ. 159.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सुपिरन्टैन्डन्ट आफ पोस्ट आफिस पुने, एम एफ एल डिविजन के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1 बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30 दिसम्बर 1994 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/96/89-आई आर (डी यू)]

के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 1995

S.O. 159.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Supdt. of Post Office, Pune, MFL Divn. and their workmen, which was received by the Central Government on 30-12-94.

[No. L-40012/96/89-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, BOMBAY

Present :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.

REFFRENCE NO. CGIT-58 OF 1990

Parties :

Employers in relation to the Management of Supdt. of Post Office, Pune, MFL Division.

AND

Their workmen

Appearances :

For the Management : Shri B. M. Masurkar, Advocate.

For the workmen : Shri Jagarwal.

INDUSTRY : Post & Telegraph STATE : Maharashtra

Bombay dt. 14th day of December, 1994

AWARD

Government of India Ministry of Labour has referred following dispute mentioned in schedule for adjudication under section 10(1)(d) read with 2A of the Industrial Disputes Act, 1947.

SCHEDULE

"Whether the action of the superintendent of Post Office, Pune, MFL Division, Pune in relation to its branch of village Kendur Distt. Pune in terminating the services of Shri Suryakant K. Shinde and E.D.A. Postmaster at Village Kendur w.e.f. 12-10-87 is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled to ?"

2. Admitted facts are that Shri Shinde was working as extra departmental delivery agent since 28th January 1983 to March 1985. He came to be selected as extra departmental Post Master and appointed with effect from 27-3-85 and the order is dated 9th of May 1985. It so happened that the Management during the course of checking found that he had not deposited the amount collected and therefore he came to be suspended for this alleged misconduct. Later by order dt. 21-9-87 his services came to be terminated. The delinquent workman, therefore, made a grievance about this and ultimately this dispute has come to be referred to this Tribunal. The grievance has been made by him in the statement of claim that there has been no inquiry into the alleged misconduct, that he has not been given an opportunity to defend himself and penalised without following the principles of natural justice.

3. He further contended that his services could not be terminated by resorting to rule 6 read with rule 2(d) of EDA conduct and service rules 1964 because he was working as extra departmental delivery agent prior to his appointment as extra department Branch Post Master from 28-3-85 to 21-9-87 without a break at Kepdur EDBO Branch thus having 4 years and 8 months continuous service to his credit. Provisions of rule 9 of EDA were not followed as he was never given any chargesheet and no inquiry was ever held. He denies the allegations about late credit of amounts collected on account of PCO (telephone) collections. He, therefore, prayed for setting aside that order and back wages.

4. Written statement has been filed on behalf of the Management and therein the justification is given for the action. Admitting that he was in service and contending that because of his misconduct by late crediting of the amounts he has been dealt with under the relevant rule 6 it is further contended that a preliminary inquiry was held and it was not necessary to hold regular departmental inquiry and it could be finalised under rule 6 of the E. D. agent conduct and service rules.

5. I have heard Shri Masurkar on behalf of the Management and representative of Shri Shinde the delinquent employee. Admitted position has been set out above and it is seen that the justification for the action taken by the management is that the delinquent employee committed misconduct by not crediting amount collected by him in treasury. It is stated in the written statement that he was expected to credit the amounts "promptly everyday". That he did not do and the same is sought to be shown by statement Ex. 'C' annexed to the written statement. It does show that the amount has not been deposited on same day it is collected or on the following day of collection. However, it does appear that it has been credited soon after it is collected. The relevant instructions are to be found at Ex. 'F' (M-6). They are with regard to receipt of money and 4(1) which is referred to in the written statement show that the amount should be paid in "full without undue delay" into treasury or into Bank to be credited to the appropriate account and made part of the general treasury balance. Instruction, therefore, do not support the contention of the Management that it should be credited daily. What it states is that it should be paid without undue delay. From the statement Ex. 'C' (M-3) it is clear that they have been paid soon after and there is in my view no undue delay much less unexplained delay. It appears his predecessor Kum. Shah also did the same thing between 17-11-85 and 27-1-86. The delinquent workman Shri Shinde states that he was not explained by anyone that he has to deposit the amount on the same day and that he did not know about it. He stated that within 2/3 days amount was being deposited before he took over and he also did likewise. When he was explained this he has been depositing the amount as per the instructions of mail overseer. He also sought to be excused for that for the reason that he was not aware about it and was not explained. He has also stated intermediate holidays were sometimes responsible for delayed payment.

6. It is thus seen that there was charge of misappropriation of funds or it was a case of temporary misappropriation of funds by delaying credit of the amount collected and yet there was no inquiry held before extreme penalty of dismissal was imposed.

7. Management seeks to justify this action under rule 6 of EDA conduct and service rules 1965. That rule speaks of termination of service and also states that the service of an employee who has not already rendered more than 3 years continuous service from the date of his appointment shall be liable to termination by the appointing authority at any time without notice. The Management therefore contends that his was a case covered by rule 6 because he had not put in more than 3 years service. That does not appear to be correct in the sense that he was in continuous service from 1983 first as a delivery agent and thereafter as FD Post Master. The period is of more than 3 years. Apart from that the point is whether recourse could be had to rule 6. The general instructions below rule 6 show that in case of misconduct recourse could not be had to rule 6. A regular inquiry could not be dispensed with in such cases of misconduct. Those DG's instructions are produced at Annexure 'C' to the statement of claim. It directs that the short circulating is not permissible and disciplinary proceedings are necessary if specific irregularly comes to surface in view of the safeguard afforded to EG agents under article 311 of the Constitution. Principles of natural justice also require that one cannot be condemned without a hearing and that has not been done. The management's reliance on his statement in preliminary inquiry (statement dt. 14-4-87 in the preliminary inquiry) as his confession justifying dispensing of the inquiry is not correct because statement dt. 14-4-1987 is not a confession of guilt. It is in effect an explanation. There is nothing to contradict the explanation and the Management therefore in my view was not at all justified in imposing penalty of dismissal from service.

8. Apart from the fact that he will be entitled to reinstatement the point is whether Mr. Masurkar's submission that he should not be given benefit of back wages deserves to be accepted. Normally rule is that when an order of dismissal is set aside the delinquent employee is entitled to back wages. He submits that this rule can be altered when he is gainfully employed in the intervening period. He submits that the employee was running a saloon and earning. The delinquent Shri Shinde who is before me does admit that he was working in his brother's Hair curring saloon and earning Rs. 20 to 25 per day. In view of the fact that he was getting money I direct that he be paid half back wages. Dismissal is set aside. Reinstatement with half back wages.

Award accordingly.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1995

का. आ. 160.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टैलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जलगांव के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30 दिसम्बर 1994 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/227/91-आई.आर. (डी.यू.)]

के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd January, 1995

S.O. 160.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government herey publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom District Manager, Jalgaon and their workmen, which was received by the Central Government on 30-12-1994

[No. L-40012/227/91-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, BOMBAY

PRESENT :

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-1/73 of 1992

PARTIES :

Employers in relation to the management of Telecom District Manager, Jalgaon.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Management : Shri Patil, Advocate.

For the Workmen : Shri Chaudhary.

INDUSTRY : Telecommunication. STATE : Maharashtra.

Bombay, dated 16th day of December, 1994

AWARD

Government of India Ministry of Labour has made reference for adjudication of a dispute mentioned in the schedule below 10(1)(d) read with 2A of the Industrial Disputes Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the Telecom District Manager, Jalgaon in terminating the service of Shri Dattaram Hari Baykar is justified? If not, what relief the workman concerned is entitled to?"

2. Statement of claim has been field by the workman Shri Baykar. He states that he was a casual labour under respondents 2 and 3 from May 1982, referring 683 days of service. Continuously worked for more than 240 days during the period from December 1979 and May 1980 and for 110 days between August 1980. While working his services were utilised by respondent 2 and sometime by respondent 3. His services were however terminated with effect from June 1982. In spite of the fact that he had put in more than 240 days as on May 1982 and that too without any notice or wages in lieu of notice and retrenchment compensation.

3. According to him respondent one to three were displeased with the applicant because while working at Savada-Khirod he sustained severe shock on 20-4-1976 and was hospitalised till 31-10-89 at Amalner. He was not given proper attention nor proper medical treatment nor financial aid and his letters evoked no response. It is his case that though the respondent had worked at Jalgaon in January 1991 he was not reengaged but the work was entrusted to a private contractor. Guidelines have been issued by the Chief General Manager stating that all the casual labourers who have been recorded prior to 30-3-1985 and who have completed 240 days of continuous service in any twelve claendar months were eligible for grant of temporary status. It was also stated that period of absence for the purpose of granting temporary status to the casual labourers could be condoned by the concerned TDE without limit provided he had worked for 240 days continuously during any twelve calendar months and with a rider that this would be a one time concession. Taking shelter under that letter the Telecom District Manager Jalgaon granted temporary status to some casual labourers. The applicant did not receive any order of temporary status and those who were given temporary status have been taken back on duty from the month of August 1990. The introduction of skill for grant of temporary status was not extended to the applicant while it was given to the other casual labourers and their names were included in the waiting list of casual labourers circulated by letter dated 21-11-89. He has been deprived of his legitimate claim and has been discriminated and therefore not reengaged.

4. He has been in continuous service for more than a year within the meaning of section 25B of the I.D. Act, and his services have been terminated without following provisions of section 25F of the Act and therefore his prayer is he be granted temporary status by applying the test laid down in letter dated 7-6-1990 of the General Manager, given back wages with interest with effect from 1-10-89 the date from which the claim of temporary status was enforced and costs.

5. The Management has filed written statement. It is admitted that Baykar worked and the number of days he worked have been given. According to the Management after 1976 April he did not turn up till November 1979. He was employed, waiving his absence but given fresh employment. He met with a minor accident on 20-4-76 and was admitted to the Municipal Hospital Savda by labour party incharge and there was hospitalisation only for 2 to 3 days and thereafter he went to his permanent residence without intimation to the party incharge. The Labour party incharge bore expenses of hospitalisation. When he came back he was provided a job with effect from December 1979 which was continued till May 1982 with minor break but he did complete 240 days in between days, further admitted that he was continuously on duty upto May 1982 but left work without intimation and absented himself from June 1982. In the month of October 1988 he was diverted TDE Dhule where he worked on 154 days in March 1989. On 21-9-89 he was diverted to DET (X bar) instalation Jalna but he did not report at Jalna. He was not on duty as on 31-3-85 as well as on 1-10-89. His breaks of service have been given in para 9. He could not be awarded temporary status as break in service was of more than 6 years. His total working days and absence are shown in appendix A to the reply which shows that he was present for 881 days and absent for 3968 days. It is denied that his services were terminated and the contention is that he voluntarily left work without any intimation and whenever he reported back and work was available he was given work. It is denied that there was any contravention of the provisions of the I.D. Act. So far as the treatment is concerned it is stated that he was given the treatment and he left on his own and did not claim compensation or produce adequate material in support. So far as entrustment of work to a contractor it is contended that it was of an urgent nature and therfeore given as it could not have been done by the casual labour available to the department. The letter received from the concerned heads did not permit condoning of the break in the case of Shri Baykar.

6. It is then contended that an application has been made by Shri Chaudhary, circle secretary ATEEU line staff group duly before the CAT bench, Bombay and therefore this proceeding is not maintainable and liable to be dismissed.

7. It is the case of the workman that he had worked right from May 1975 to May 1982 under respondent Nos. 2 and 3 and that appears to be not disputed by the respondents because statement annexed to the written statement shows that in May 1975 he worked for 23 days and in June for 25 days, July for 10 days March 1976 for 19 days and April 1976 for 13 days. Thereafter he worked between November 1979 and May 1980 for 178 days and August 1980 to May 1981, 249 days. In August 1981 he worked for 21 days and between October 1981 and January 1982 for 106 days and thereafter between March 1982 and May 1982 for 83 days. The workman's further case is that between December 1979 to November 1980 he worked for more than 240 days and this part of the case is admitted in para 3 of the written statement. An attempt was made to dispute this in reply to affidavit filed on behalf of the Management by stating in para 1 that his assertion that he has completed 240 days continuously with effect from December 1979 to November 1980 was totally incorrect and that cannot succeed in view of the admission in the written statement. Therefore it is clear that he had worked for more than 240 days during that spell as stated by him in his appliction and admitted in the written statement. Thereafter he worked as stated in the statement annexed to the written statement from October 1988 to March 1989 for total number of 154 days.

8. The workman claims on the basis of this benefit of circular issued dated 7-6-1990 by the Management under the signature of Assistant General Manager Shri Hashmi. It says that persuant to order dated 7-12-1990 comprehensive statement in respect of casual mazdoor has been received from various field units it was understood that all eligible casual mazdoors have since been granted temporary status as per DOT order on the subject endorsed by this office. It is further stated if some case are still pending they may be settled expeditiously. As a result of the guidelines furnished therein it is seen that eligibility for confirment of temporary status to the casual mazdoors is given in para one and it is stated that all those casual mazdoors who are employed before 30-3-1985 and who have completed continuous service of 240 days during calendar months before 30-3-1985 without any consideration of break of service either due to departmental or own reasons are eligible. It is thereafter mentioned thus "eligibility conditions are only two. (1) the casual mazdoor should have been employed before 30-3-85, and (2) he should have worked continuously by 240 days during tny calendar months".

9. The workman's case is that he fits in this category and therefore was eligible for confirmation of temporary status. He made a request to that effect and after conciliation failed reference has been made. Letter dated 24-10-1991 of the Labour enforcement (officer) Bhusaval mentions the subject and it is stated therein that the Industrial Dispute between the Management of the Telecom, District-Jalgaon and their workman represented by Assistant Circle Secretary, AITE Union class III, Jalgaon over the issue of retrenchment and non grant of temporary status to Shri Dattaram Hari Baykar, casual Labour.

10. The order dated 7-6-1990 is further considered on 14-3-1991 Appendix A to the written statement and it is stated therein that the matter regarding condonation of the period has been reconsidered in the light of difficulties which are being faced by the units and it is now decided CTD/TDM may condone absence upto a period of five years for the purpose of granting temporary status and no further relaxation be given in any case beyond this limit. While doing so reference has been made to the granting of temporary status to the casual mazdoors and condonation of absence for the purpose. If that be so it is difficult to see how in the case of the present workman Shri Baykar the management can deprive him of the temporary status for which he is eligible.

11. It appears from the written statement para 9 that the management considers the break between May 1976 and October 1982 and October 1988 as coming in the way of giving effect to guidelines circulated by order dated 7-6-1990 and later order dated 14-3-1991 because of circular dated 21-10-1992 appendix 6 with the written statement. That circular makes a reference to letter dated 30-8-90 which unfortunately does not appear to be on record. However that circular of 21-10-1992 defines the powers of Divisional Engineer and powers of Chief General Manager, Telecom with regard to period for which break in service could be condoned. I do not see how this will override the earlier circular dated 14-3-1991 and guideline dated 7-6-1990. No mention has been made in this circular of 1990 to either of them. The last paragraph mentioning that this order supersedes all orders issued till date on the subject will have to be read in the context. The management's inability to treat the case of present workman under guidelines circular dated 7-6-1990 and 14-3-1991 cannot be justified. I, therefore, find that the present workman who had put in more than 240 days in a year prior to 1985 was entitled to the confirment of temporary status and for having worked between October 1988 to March 1989 which accounted for absence for less than 5 years.

12. I am sorry to state that the reference has not been happily worded. The grievance of the Union was non-grant of temporary status also as can be seen from Annexure A Labour Enforcement Officer's letter and yet that has not found its way in the drafting of the dispute for reference. Further that was a part of the grievance if not the whole of it and that has led to a dispute and the statement of claim and the written statement as well as material produced clearly shows that the dispute was with regard to non-grant of temporary status. I think in view of this he is entitled to the grant of temporary status.

13. He made some grievance about not receiving treatment and medical expenses for the injury sustained while on duty. I do not think I can deal with that aspect of his grievance in the present reference I do not find that the same was made an issue before the conciliation officer and because of that has not found its way in the reference of the dispute for adjudication. As a result of temporary status whatever benefit he is entitled to under the circular dated 7-6-1990 the management will give and I ordered the same.

Award accordingly.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1995

का.आ. 161—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16-1-1995 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला कोलम के तालुक कन्नाथूर में राजस्व ग्राम पश्चिम कल्लाड़ा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

[संख्या एस-38013/1/95-एसएस-1]

जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 5th January, 1995

S.O. 161.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 16th January, 1995 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala, namely :—

"Area within the revenue village of West Kallada in Kunnathur taluk of Kollam District."

[No. S-38013/1/95-SS.I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1995

का.आ. 162.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16-1-1995 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला अलापुजहा के तालुक चेरथला में राजस्व ग्राम कोडमथूरुथू, कुथीयाथोड और थूरावुर दक्षिण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

[संख्या : एस-38013/2/95-एसएस-1]

जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 5th January, 1995

S.O. 162.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 16th January, 1995 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala, namely :—

"The areas within the Revenue Villages of Kodumthuruthu, Kuthiyathode and Thuravoor South in Cherthala Taluk of Alappuzha District."

[No. S-38013/2/95-SS.I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1995

का.आ. 163.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, विविध हाइड्रोजन तेल और उनके मिश्रण जिनमें सिन्थेटिक ईंधन स्नेहक तेल और इसी प्रकार के तेल शामिल हैं, के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 26 में शामिल हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छह मास की कालावधि के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या : एस-11017/2/84-डी-1ए]
एस.एस.पराशर, अवर सचिव

New Delhi, the 5th January, 1995

S.O. 163.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the industry engaged in the manufacture or production of mineral oil (crude oil), motor and aviation sprit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, lubricating oils and the like, which are covered by entry 26 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/2/84-DI (A)]
S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1995

का.आ. 164.—यतः मैसर्स आर.के. स्वामी, बी.बी.डी.ओ., एडवरटाइजिंग (प्रा.) लिमिटेड टीएन-10021 और शाखाएं (इसके आगे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो, इससे अभिप्रायः उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

यह केन्द्र सरकार की राय में उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमों में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं हैं तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 इसके आगे जहां कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त स्कीम से है) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है।

अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा एक के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना से संबंधित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेश के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा।

2. न छूट प्राप्त स्थापनाओं के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन सृजित स्कीम के अन्तर्गत देय अंशदान के देर से स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंशदान का दर किसी समय भी कम न होगा।

3. पेशगियों के मामले में छूट प्राप्त स्थापना को स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 से कम हितकर नहीं होगा।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जाएगा। उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के प्रतिकूल प्रभावी होने की सम्भावना है वहां अपनी अनुमति से पूर्व, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2(च) में निश्चित किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होते, सदस्य बनाए जाएंगे।

6. जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) या किसी अन्य छूट-प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में काम पर लगाया जाता है तो नियोक्ता उसे निधि का तुरन्त सदस्य बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि लेखे में संचयों को अंतरित कराने और उसके लेखे में जमा कराने की व्यवस्था करेगा।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा जैसे भी मामला हो, समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

8. भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बातों के होते हुए भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में शेषों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उत्तरदायी होगा।

9. तथा 10. न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेंगे और केन्द्र सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किये गए मार्ग निदेशों के अनुसार कार्य करेंगे/ न्यासी बोर्डों द्वारा रखे गये भविष्य निधि लेखों की लेखा परीक्षा वार्षिक रूप से योग्य सनदी लेखापाल द्वारा स्वतन्त्र रूप से की जायेगी/जहां भी आवश्यक होगा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों को दुबारा लेखा-परीक्षा कराए और ऐसे पुनः लेखा-परीक्षा के खर्च नियोक्ता वहन करेगा।

11. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

12. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने कर्मचारियों के अंशदानों को आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा। अंशदानों की विलम्ब में अदायगी करने के लिए समान परिस्थितियों में नियोक्ता नुकसानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक न-छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती हैं।

13. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा। प्रतिभूतियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियंत्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

14. सरकार के निदेशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा।

15. न्यासी बोर्ड एक वस्तु-ब्यौरा रजिस्टर तैयार करेगा और ब्याज और विमोचन आय को समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा।

16. जमा किए गए अंशदानों, निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित ब्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखे तैयार करेगा।

17. वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा।

18. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पासबुक जारी कर सकता है। ये पास-बुकें कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतिकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हें अद्यतन किया जाएगा।

19. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में ब्याज उस दर में जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय करें परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।

20. यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ब्याज की दर इस कारण से कि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से अदा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा।

21. नियोक्ता भविष्य निधि की चोरी के कारण लूट-खसूट, ख्यानत, गबन अथवा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पूरा करेगा।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करें।

23. उक्त स्कीम के पैरा 69 की शैली पर किसी कर्मचारी को निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में नियोक्ताओं के अंशदानों को जब्त करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार जब्त की गई राशियों का अलग से लेखा तैयार करेगा और उसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो।

24. स्थापना के.भ.नि. नियमों में किसी बात के होते हुए भी सेवानिवृत होने अथवा किसी अन्य स्थापना में रोजगार लगने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के निधि की सदस्यता न रहने पर यदि यह देखने में आता है कि स्थापना के.भ.नि. नियमों के अन्तर्गत अंशदान की दर, जब्ती आदि की दर, सांविधिक स्कीम की दरों की तलना में कम अनुकूल है तो उस का अन्तर नियोक्ता द्वारा दिया जाएगा।

25. नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन से सम्बन्धित सभी खर्चे जिसमें लेखों के रखरखाव रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण शामिल है, वहन करेगा।

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है, उसकी मुख्य बातों को कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगाएगा।

27. "समुचित सरकार" स्थापना की चालू छूट पर और शर्तें लगा सकती हैं।

28. यदि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी स्थापना आती है, पर अंशदान की दर बढ़ायी जाती है, नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान की दर उचित रूप में बढ़ाएगा, ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभों से स्थापना की स्कीम के अन्तर्गत दिए जाने वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों।

29. उक्त शर्तों में से किसी एक से उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है।

[सं. एस-35015/13/93-एस.एस.-II]
जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 6th January, 1995

S.O. 164.—Whereas M/s. R. K. Swamy, BBDO Advertising (P) Ltd. TN/10021 and its branches (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of similar character ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed here to the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said Scheme which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to the automatically. The employer shall not however make any other amendment in its P.F. rules without the approval of Regional Provident Fund Commissioner. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their points of view.

5. All employees (as defined in section 2(f) of the said Act) who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a provident fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government, as the case may be, from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees Provident Fund Organisation inter-alia for proper accounts of the receipts into and payments from the provident fund and the balances in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner or and officer authorised by him.

10. The accounts of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent Chartered Accountant annually. Where considered necessary, the Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

11. A copy to the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year. For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st of April to the 31st of March.

12. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest for any delay in payment of the establishment is liable in similar circumstances.

13. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a scheduled Bank under the Credit Control of the Reserve Bank of India.

14. Failure to make investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees sevrally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

15. The Board of Trustees shall maintain a scriptwise register and ensure timely realisation of interest.

16. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

17. The Board shall issue an annual statement of accounts to every employee within six months of the close of financial/accounting year.

18. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue pass books to every employees. Those pass book shall remain in the custody of the employees and will be brought uptodate by the Board on presentation by the employees.

19. The accounts of each employee shall be credited with interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such rate as may be decided

by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

20. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason than the deficiency shall be made good by the employer.

21. The employer shall also make good any other loss that may be caused to the Provident Fund due to theft burglary, defalcation mis-appropriation or any other reason.

22. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government/Central Provident Fund Commissioner may prescribe from time to time.

23. If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employees' contribution in cases where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amount so forfeited prior to 1-1-90 utilise by the B-O-T for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

24 Notwithstanding anything contained in the Provident Fund Rules of the establishment, if on the cessation of any individual from the membership of the fund consequent on retiring from service or on taking up the employment in some other establishment, it is found that the rate or contribution rate of forfeiture etc., under the P.F. Rules of the establishment are less favourable as compared to these under the statutory Scheme, the difference shall be borne by the employer.

25. The employer shall bear all the expenses of the administration of the provident fund including the maintenance of accounts, submission of returns, transfer of accumulations.

26. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended there to alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

27. The appropriate Government may lay down any further conditions for continued exemption of the establishment.

28. The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of provident fund contribution is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions.

[No. S-35015/13/93-SS.II]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली 11 जनवरी, 1995

का.आ. 165—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पश्चिम रेलवे रतलाम (म.प्र.) के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012 (59)/83 डी 2(बी) बी-I)]

पी. जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th January, 1995

S.O. 165.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Railway, Ratlam (M.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on 27-12-94.

[No. L-41012/(59)/83-D-II(B)/B. I.]

P.J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT

JABALPUR (M.P.)

CASE NO. CGIT/LC (R)23/1986

BETWEEN

Shri Nirbhay Singh and 30 others represented by Shri Devi Lal S/o Shri Gandalal and 30 others, Soloman Ki Chal, Laxmanpura, Ratlam (MP)

AND

The Divisional Railway Manager, Western Railway, Ratlam (MP)

PRESIDED IN : By Shri Arvind Kumar Awasthy.

APPEARANCES:

For Workman : Shri R.C. Srivastava, Advocate.

For Management : Shri G.L. Gupta, Advocate.

INDUSTRY : Railways DISTRICT : Ratlam (MP).

AWARD

Dated the November 22, 1994

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide its Notification No. L-41012(59)/83 D. II(B) dated 29 January, 1986 for adjudication of the following dispute:—

"Whether the action of the Divisional Railway Manager, Western Railway, Ratlam in terminating the services of the 31 workers as shown in the Annexure with effect from 21-5-83, although as claimed by the union they were senior to many other casual workers is justified ? If not, to what relief the workmen are entitled ?"

ANNEXURE

Name	Father's Name	Date of Apptt.
1. Nirbhay	Ghise	10-11-78
2. Khatu	Galiya	10-11-78
3. Ambaram	Dhuraji	10-11-78
4. Raghunath	Tulsiram	10-11-78
5. Ishwarlal	Ramchandra	10-11-78
6. Harday Prasad	Ram Lakhan	10-11-78
7. Dilip	Pannalal	10-11-78
8. Miyani Bai	(Husband) Sitaram	10-11-78
9. Daya Ram	Pannalal	10-11-78
10. Paras	Nathu	11-11-78

1	2	3	4
11.	Ram Prasad	Shri Dulare	11-11-78
12.	Amar Singh	Kishan Singh	13-11-78
13.	Mohan	Bhima	12-1-79
14.	Vardi Bai	(Husband Amba Ram)	12-1-79
15.	Kali Shankar	Kallu	12-1-79
16.	Kanahyalal	Laxmi Narayan	12-1-79
17.	Devilal	Gandhalal	10-4-79
18.	Azij	Sarvan	10-4-79
19.	Jagdish	Asriya	10-4-79
20.	Shri Kishan	Mankya Ram	21-4-79
21.	Munnalal	Gayadin	4-5-79
22.	Govind	Ram Swaroop	4-5-79
23.	Rattan Lal	Tulsiram	4-5-79
24.	Shankar Lal	Dhuraji	4-5-79
25.	Shyamlal	Pannalal	4-5-79
26.	Mohan	Babru	4-5-79
27.	Raju	Rawji	5-5-79
28.	Punam Singh	Mitthu Singh	10-5-79
29.	Govardhan	Laxmi Narayan	10-5-79
30.	Azij	Imtiyas	10-5-79
31.	Dinesh	Ratanlal	28-10-79

2. The case of the workmen is that the workmen were working in the various department under the control of the Management and the applicants have completed more than 240 days of their services; that under Sec. 25B of the I.D. Act the workmen having completed 240 days of services shall be deemed to be in continuous service; that the services of the applicants were terminated with effect from 30-5-83 without following the procedure or without paying them retrenchment compensation and as such their termination is bad in law. The workmen have prayed that the action of the management in terminating the services of the applicants be held illegal and the workmen be directed to be reinstated with full back wages.

3. The management in its short reply denied all the allegations of the workmen and it was alleged that in the statement of claim the service particulars of the workmen are not mentioned and as such the petition is liable to be dismissed.

4. Inspite of the initial objection of the management for the supply of the particulars of the workmen and despite of the order dated 5-8-91 of my learned predecessor the particulars of the workmen were not supplied by the workmen. In the statement of claim the dates from which the workmen worked at the period of 240 days are not disclosed and no relevant record filed by the workmen. From the pursual of the order sheets it is clear that the learned Counsel for the workmen made the statement before my learened predecessor that the workmen have got employment and they are absorbed by the management. The workmen and the management were absent even after the service of the notice on the date of hearing i.e. 17-10-94.

5. In the aforesaid circumstances, it is clear that the workmen have no grievance against the termination of their service w.e.f. 21-5-83. Consequently, no dispute award is passed. Parties to bear their own costs.

ARVIND KUMAR AWASTHY, Presiding Officer

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995